जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

हिण्डौन सिटी

Rashtradoot

फोनः- 230200, 230400 फैक्सः- 07469-230600 वर्षः 17 संख्याः 258 प्रभात हिण्डौन सिटी, मंगलवार 22 जुलाई, 2025 पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

अपनी अवहेलना से दु:खी धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया

अवहेलना का कारण, शायद मोदी सरकार व उनके बीच बढ़ते गम्भीर मतभेद थे

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 जुलाई। यह पहला अवसर है, जब भारत के किसी पदासीन उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दिया है।

भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड ने इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे के साथ ही, वे राज्यसभा के सभापति पद से भी स्वत: ही हट गए हैं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे अपने इस्तीफे में उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है।

लेकिन सूत्रों का कहना है कि असली वजह कुछ और है। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन यह बड़ा और चौंकाने वाला घटनाक्रम हुआ है, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही पर असर पड़ सकता है।

- धनखड़ महसूस कर रहे थे, कि उन्हें वह ओहदा नहीं मिल रहा था, जो उन्हें उपराष्ट्रपति होने के कारण स्वाभाविक तौर पर वैसे ही मिलना चाहिए था। उदाहरण के लिए, जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति वैन्स भारत यात्रा पर आए थे तो धनखड़ के साथ उनकी मुलाकात आयोजित नहीं की गई थी, और इससे धनखड़ काफी क्षुब्ध थे, काफी आहत महसूस कर रहे थे।
- न्यायाधीश वर्मा के इम्पीचमैंट को लेकर भी समस्या थी। कछ पार्टियों, जिनमें प्रमुख पार्टी मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी है, ने इन्कार कर दिया था, महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से, न्यायाधीश वर्मा काफी नज़दीक माने जाते थे, मुलायम सिंह यादव के। कई वरिष्ठ वकील भी न्यायाधीश वर्मा के ''इम्पीचमैंट'' के खिलाफ थे।
- सरकार चाहती थी, महाभियोग के मसले पर, विपक्ष (मुख्य रूप से कांग्रेस) के लोकसभा सदस्य भी हस्ताक्षर करते, पर, कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस का तर्क था, उनके सांसद , राज्यसभा में हस्ताक्षर कर चुके हैं।
- धनखड़ के खिलाफ शिकायत यह भी थी, कि, वे योगी आदित्यनाथ की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे थे, तथा यू.पी. की भी कुछ ज्यादा ही यात्रा कर रहे थे।

धनखड़ 2022 में उपराष्ट्रपति बने थे और उनका कार्यकाल 2027 तक था।

ऐसी अपुष्ट खबरें हैं कि मोदी सरकार के साथ गंभीर मतभेदों के चलते उनसे इस्तीफा देने को कहा गया।

हाल के दिनों में, वे सरकार से खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे थे और उन्हें उचित सम्मान और प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा था। बताया जाता है कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति वेंस से उनकी मुलाकात नहीं हुई, जिससे उन्हें काफी ठेस पहुंची।

सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच मतभेद के साथ-साथ,उनका स्वास्थ्य भी एक मुद्दा था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ समय पहले उनसे मिलने गए थे।

जस्टिस वर्मा के महाभियोग को लेकर भी विवाद था।

कुछ विपक्षी दलों, जैसे समाजवादी पार्टी, ने इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था क्योंकि जस्टिस वर्मा मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाते थे।

कई वरिष्ठ वकील भी जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग का विरोध कर रहे थे।

सरकार केवल लोकसभा में महाभियोग लाना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं थी। कांग्रेस ने कहा कि आपके पास 100 से ज्यादा सांसद हैं, आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एयर इंडिया के तीनों टायर फटे, हादसा टला

नई दिल्ली, 21 जुलाई। मुंबई एयरपोर्ट पर सोमवार सुबह एअर इंडिया का एआई 2744 प्लेन लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गया। ये विमान कोच्चि से मुंबई आया था। मुंबई में भारी बारिश के कारण रनवे पर फिसलन थी, जिससे विमान रनवे से 16 से 17 मीटर दूर घास पर चला गया।

ये हादसा सुबह 9:27 बजे हुआ। तस्वीरों में दिखा कि विमान के दाहिने इंजन के नैसेल (ढक्कन) को नुकसान पहुंचा है। इस घटना के बाद विमान को पार्किंग तक लाया गया, जहां सभी यात्री और क्रू मैम्बर्स को उतारा गया। इस दौरान विमान के तीन टायर फट गए।

- एआई 2744 विमान मुम्बई में लैंडिंग के दौरान फिसल कर 16-17 मीटर घास पर चला गया।

एअर इंडिया ने बताया कि हादसे में किसी पैसेंजर या क्रू मेंबर को नुकसान नहीं पहुंचा है, हालांकि मुंबई एयरपोर्ट का मेन रनवे, 09/27 क्षतिग्रस्त हुआ है। रनवे पर फ्लाइट्स की आवाजाही बंद कर दी गई है। रनवे के किनारे तीन साइनेज बोर्ड और चार लाइटें भी टूट गईं।

न्यायाधीश वर्मा के ''इम्पीचमैंट'' नोटिस पर सौ लोकसभा सदस्यों ने हस्ताक्षर किए

संसद में ''इम्पीचमैंट'' (महाअभियोग) के प्रस्ताव पर कम से कम सौ लोकसभा सदस्यों व 50 राज्यसभा सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, सदन में प्रस्ताव बहस के लिए पेश होने के लिए

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 21 जुलाई। दिल्ली में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर भारी मात्रा में नकदी मिलने के मामले में, संसद में उन्हें हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। लोकसभा के 100 से अधिक सांसदों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ज्ञातव्य है कि जब नकदी मिलने की घटना हुई थी, तब वे दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे।

महाभियोग प्रस्ताव संविधान के तहत किसी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, जिसके लिए प्रस्ताव पर लोकसभा के कम से कम 100 और राज्यसभा के कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं।

- राज्यसभा के मार्क्सवादी सदस्य जॉन ब्रिटास व साम्यवादी पार्टी के संदोष कुमार ने मुद्दा उठाया, कि, न्यायाधीश शेखर यादव के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव अभी तक लिस्ट नहीं हुआ है, जबकि संसद न्यायाधीश वर्मा के खिलाफ महाअभियोग के मामले पर विचार कर रही है।
- मुख्य न्यायाधीश गवई ने, महाधिवक्ता नेदुमपरा के व्यवहार पर नाराज़गी व्यक्त की, जब उन्होंने न्यायाधीश वर्मा को वर्मा कहकर सम्बोधित किया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ''न्यायाधीश वर्मा हाईकोर्ट के सम्मानित जज हैं, उन्हें ''वर्मा'' कह कर सम्बोधित करना, उनका अपमान है।
- अधिवक्ता, नेदुमपरा का तर्क था, कि न्यायालय को इस मामले में दिल्ली पुलिस को एफ.आई.आर. दर्ज करके, जांच करनी चाहिए।

केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार को सर्वदलीय बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि इस प्रस्ताव को सदन में कब पेश किया जाएगा, यह संसद की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी।

शनिवार को राज्यसभा सदस्य जॉन ब्रिटास (माकपा) और पी. संतोष कुमार (भाकपा) ने न्यायमूर्ति शेखर यादव के खिलाफ, उनकी कथित साम्प्रदायिक टिप्पणियों के कारण लाए

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की तारीफ की

प्र.मंत्री ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों ने विदेशों में भारत के लिए सकारात्मक माहौल बनाया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 जुलाई। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए गए वैश्विक संपर्क कार्यक्रम (ग्लोबल आउटरीच) में सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह भारत की साझा शक्ति और विश्व मंच पर बढ़ते सम्मान का प्रतीक है।

प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल की सराहना की जिन्होंने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के वैश्विक संपर्क अभियान के तहत विभिन्न देशों की यात्रा की। उन्होंने कहा, सांसदों और उनकी पार्टियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक सकारात्मक माहौल बनाया है। इस प्रयास में उनका योगदान प्रशंसनीय है।

- प्र.मंत्री ने संसद सत्र से पूर्व पत्रकारों से औपचारिक सम्बोधन में कहा कि विपक्षी दलों व सांसदों ने देश के लिए एकता का प्रदर्शन किया।

प्रधानमंत्री ने कहा, ''ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेना ने जो पराक्रम दिखाया उसे हमे आगे बढ़ाना चाहिए, और जिस तरह देश ने संसद में एकजुटता दिखाई, वह अनुकरणीय है।

मोदी ने यह भी कहा कि वर्तमान मानसून सत्र देश के लिए ''गौरवपूर्ण मानसून सत्र'' है, खासकर इसलिए कि भारत ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को भेजा है और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में भी अहम सफलताएं हासिल की हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के तहत, आतंकियों के आकाओं के घर 22 मिनट में जमींदोज़ कर दिए गए। दुनिया इस नई भारतीय सैन्य ताकत से बहुत प्रभावित है।

उन्होंने आगे कहा, आजकल जब भी मैं विदेशी नेताओं से मिलता हूं, तो मुझे ''मेड इन इंडिया'' हथियारों में गहरी रुचि दिखाई देती है। भारत की रक्षा निर्माण शक्ति को वैश्विक पहचान मिल रही है।

रेल्वे पेपरलीक में 8 आरोपियों को सजा

नयी दिल्ली, 21 जुलाई। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अहमदाबाद स्थित अदालत के विशेष न्यायाधीश ने रेलवे पेपर लीक मामले में सोमवार को आठ आरोपियों को पाँच-पाँच वर्ष के साधारण कारावास और पांच-पांच लाख रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई।

ये सभी रेलवे के पूर्व कर्मचारी हैं और इन्हें यह सजा आपराधिक षडयंत्र, चोरी, चोरी की संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करने या रखने, अपराध के साक्ष्य को गायब करने और आपराधिक कदाचार के मामले में सुनाई गई है।

- सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी आठ को 5 साल की कैद व 5-5 लाख रु. के जुर्माने की सजा सुनाई। सभी आरोपी रेल्वे के पूर्व कर्मचारी हैं।

सीबीआई ने तत्कालीन मुख्य सतर्कता निरीक्षक, पश्चिम रेलवे, अहमदाबाद की शिकायत के आधार पर, अगस्त 2002में राजेश गोस्वामी,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमेरिकन अदालतों ने 75 प्रतिशत फैसले ट्रम्प के खिलाफ सुनाये

वाशिंगटन, 21 जुलाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के नए कार्यकाल की शुरुआत से अमेरिकी अदालतों ने 75 प्रतिशत मामलों में उनके खिलाफ फैसला सुनाया है और वर्तमान कार्यकारी शाखा के फैसलों को चुनौती दी है या स्थगित किया है। समाचार पत्र वाशिंगटन टाइम्स की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गयी।

- ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल के पहले 6 माह में उनके कार्यकारी निर्णयों के खिलाफ 500 मुकदमे हुए अर्थात प्रति कार्य दिवस चार मुकदमे।

रिपोर्ट के अनुसार अपने छह महीने के कार्यकाल के दौरान ट्रंप को अपनी कार्यकारी शाखा के कार्यों को चुनौती देने वाले कम से कम 500 मुकदमों का सामना करना पड़ा है, जो प्रति कार्यदिवस चार मुकदमों के बराबर है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मानसून सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने लोकसभा नहीं चलने दी

हंगामे के कारण बार-बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी, फिर चार बजे पूरे दिन के लिए लोकसभा स्थगित कर दी गई

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 जुलाई। संसद के महीने भर चलने वाले मानसून सत्र के पहले ही दिन लोकसभा में भारी हंगामा देखने को मिला। विपक्षी दलों ने सदन नहीं चलने दिया, क्योंकि नाराज विपक्षी सांसद पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर तुरंत बहस की मांग को लेकर नारेबाजी करते रहे और उन्होंने सदन की कार्यवाही बार-बार बाधित की। इसके चलते, सदन चार बार स्थगन करना पड़ा और अंतत: सदन को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया।

सरकार ने दोनों सदनों में इन मुद्दों पर पूरी बहस कराने की पेशकश कर दी थी, उसके बाद भी भारी हंगामा हुआ। यहां तक कि रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने हस्तक्षेप करते हुये कहा कि सरकार किसी बहस से भाग नहीं रही है, लेकिन फिर भी विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए वैल में खड़े रहे और तुरंत बहस की मांग पर अड़े रहे। विपक्ष ने दावा किया कि उन्होंने कम से कम 20 मुद्दों पर बहस के लिए नोटिस दिए हैं।

- विपक्ष, ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर चर्चा की मांग कर रहा था, सरकार की ओर से चर्चा के आश्वासन के बाद भी विपक्षी नेता नारेबाजी करते रहे।
- दोनों सदनों में कांग्रेस के सांसद काला स्कार्फ बांध कर आए थे।
- दूसरे दिन भी संसद में भारी हंगामा होने की संभावना है क्योंकि विपक्ष प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विदेशी दौरे पर नाराजगी जता रहा है, विपक्ष का कहना है प्र.मंत्री को सदन में होना चाहिए।

हंगामे की शुरुआत प्रश्नकाल के दौरान ही हो गई, जिससे स्पीकर ओम बिड़ला ने मजबूरन सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिये स्थगित कर दिया। इसके बाद कार्यवाही बार-बार स्थगित होती रही और अंत में भाजपा के दिलीप सैकिया द्वारा दोपहर 4 बजे के आसपास पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई।

राज्यसभा में अध्यक्ष जगदीप धनखड़ के कुशल संचालन के कारण वहां ऐसा कोई हंगामा नहीं हुआ। उन्होंने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को पहलगाम मुद्दा उठाने का अवसर दिया और फिर सदन के नेता व स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को यह आश्वासन देने दिया कि इस पर पूरी बहस कराई जाएगी। इससे पहले कि विपक्ष अन्य मुद्दे उठाता, धनखड़ ने राज्यसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया और कहा कि पहलगाम बहस के लिए समय सदन की कार्य संचालन समिति तय करेगी।

कांग्रेस के सांसद, जिनमें सोनिया गांधी भी शामिल थीं, दोनों सदनों में काले स्कार्फ पहनकर पहुंचे थे, जो उनके विरोध का प्रतीक था। वहीं, राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष पर, विपक्ष

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एक बार फिर मोदी विदेश यात्रा पर निकले, जब संसद का सत्र चल रहा है

राहुल गांधी ने इस पर टिप्पणी की, ''मोदी अपनी जवाबदेही से भाग रहे हैं''

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 21 जुलाई। संसद का मानसून सत्र सोमवार को शुरू हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस दौरान विदेश यात्रा पर जाने को लेकर विपक्षी दलों ने तीखा विरोध जताया। संसद में जहां चुनावी सूची में संशोधन, बढ़ती बेरोजगारी, ऑपरेशन सिंदूर के प्रभाव और मणिपुर में तनाव जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है, वहीं प्रधानमंत्री बुधवार को मालदीव और ब्रिटेन की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। विपक्ष ने इसे गैर-जिम्मेदाराना और गैर-लोकतांत्रिक फैसला बताया है।

प्रधानमंत्री संसद भवन तो आए, लेकिन सिर्फ मीडिया को औपचारिक संबोधन देने के लिए, जो सत्र शुरू होने से पहले की परम्परा है। इसके बाद वे दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल हुए बिना निकल गए। माना जा रहा है कि उन्होंने अपने संसद कार्यालय से लोकसभा में विपक्ष के हंगामे को देखा।

- सरकारी सूत्रों ने विदेश यात्रा को सही ठहराते हुए कहा, ''यात्रा का कार्यक्रम पूर्व निश्चित था, तथा यह यात्रा राजनीतिक रणनीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।''
- सरकार के आलोचकों ने प्रत्युत्तर में कहा है, सरकार की प्राथमिकता क्या है, देश में प्रजातंत्र को पोषित करना, क्योंकि, संसद निर्णायक भूमिका रखती है, प्रजातंत्रीय व्यवस्था में, क्योंकि किसी भी बहस के लिए यह देश का सबसे बड़ा मंच है।
- साथ ही मालदीव की चीन के नज़दीक जाने की इच्छा के कारण भारत-मालदीव रिश्ते इतने कमज़ोर कभी नहीं रहे।
- साथ ही, ब्रिटेन की इकॉनमी की स्थिति भी इस वक्त ज्यादा मजबूत नहीं है, महंगाई, राजनीतिक स्थिरता, तथा घटते राजनीतिक प्रभाव के कारण। अतः ब्रिटेन भारत के लिए खास उपयोगी साबित नहीं हो सकता।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर ''जवाबदेही से भागने का आरोप लगाया और कहा कि राष्ट्रीय संकट के समय संसद से दूरी बनाना लोकतांत्रिक कर्तव्य की अवमानना है।'' टीएमसी, सीपीआई (एम) और डीएमके के नेताओं ने भी यही बात दोहराई और कहा कि प्रधानमंत्री घरेलू ज़िम्मेदारियों से ज़्यादा विदेशी दिखावे को प्राथमिकता दे रहे हैं।

सरकारी सूत्रों ने इस दौरे का बचाव करते हुए इसे पहले से तय और रणनीतिक रूप से अहम बताया। लेकिन जानकारों का कहना है कि मोदी के इस दौरे, जिसमें वे मालदीव जा रहे हैं, की टाइमिंग कई सवाल खड़े करती है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

हमारी आनंदपूर्ण बदकारियाँ ही हमारी उत्पीड़क चाबुक बन जाती हैं। –शेक्सपियर

क्या इस संसद सत्र में प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे?

संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई 2025 से प्रारंभ हो चुका है। इस सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है। इतने महत्वपूर्ण संसद सत्र के प्रारंभ होते ही प्रधानमंत्री इंग्लैंड और मालदीव्स की विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। इससे यह संकेत तो मिलता ही है कि प्रधानमंत्री संसद में रहने को अधिक महत्त्व नहीं देते हैं।

इस सत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और आर्थिक स्थिति से संबंधित कई ऐसे गंभीर प्रश्न उठने की संभावना है जिस पर सरकार, विशेषकर प्रधानमंत्री को संसद के माध्यम से देश के समक्ष स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सामान्यतया, जब सरकार महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर सार्वजनिक रूप से न दे और प्रधानमंत्री केवल अपनी ही बात करें और जनता एवं राजनीतिक दलों द्वारा उठाए जा रहे प्रश्नों के संबंध में मौन साध लें, तो फिर उनके पास उत्तर प्राप्त करने का केवल एक ही विकल्प बचता है, कि वे संसद के अंदर, संसदीय प्रक्रियाओं के अनुसार सरकार से उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करें। हम इस आलेख में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण अनुत्तिरत प्रश्नों का उल्लेख करेंगे।

पहला प्रश्न पहलगाम की आतंकवादी घटना के संबंध में है। यह घटना 22 अप्रैल को घटी किंतु अभी तक इससे संबंधित अनेक पहलुओं का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। जब पहलगाम की बाई –शरण घाटी में सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी तो वहां पर क्यों पर्यटकों को इतनी बड़ी संख्या में जाने दिया गया? इसके कारण 26 निर्दोष पर्यटक, आतंकवादियों की गोलियों के शिकार हो गए। प्रश्न यह भी है कि अभी तक चार आतंकवादियों में से एक को भी पकड़ा क्यों नहीं गया? देश यह जानना चाहता है कि क्या ये देश में ही कहीं छुपे हैं, पाकिस्तान चले गए हैं या फिर किसी मुठभेड़ में मारे गए हैं? जो भी स्थिति हो, सरकार को संसद के माध्यम से देश को बताना चाहिए।

दूसरा प्रश्न ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देश को मिली सफलता एवं उसके परिणाम से संबंधित है। भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि भारत का कोई नुकसान इस संघर्ष में नहीं हुआ, जब कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाल ही में एक बयान दिया है कि इस संघर्ष में पांच जेट विमान गिराए गए। सरकार को यह साफ बताना चाहिए कि ये किसके थे? अब तक इस बारे में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। भारतीय सेना के प्रमुख अनिल चौहान और इंडोनेशिया में भारत के दूतावास में पदस्थापित रक्षा अटैची कैप्टन शिव कुमार ने यह माना कि भारत ने अपने जेट खोए हैं। यह सच बताने में सरकार को क्या परेशानी है कि भारत ने कोई जेट विमान खोए या नहीं और खोए तो कितने? जब संघर्ष होता है, तो दोनों पक्षों को जन धन की क्षति होना स्वाभाविक है। देश को यह जानने का हक तो है ही कि हमारे देश का कितना नुकसान हुआ है? अंततः, सारा पैसा तो देश की जनता से ही वसूल किया जाता है? इस बारे में इतनी अपारदर्शिता क्यों? संसद में सरकार या तो डोनॉल्ड ट्रंप के बयान का खंडन करे या पुष्टि करे।

तीसरा प्रश्न, ऑपरेशन सिंदूर के चलते,अचानक हुए युद्ध विराम के संबंध में है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बार-बार युद्ध विराम का श्रेय स्वयं ले रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को युद्ध विराम करने हेतु तैयार किया। इसके लिए उन्होंने आर्थिक प्रतिबंधों की धमकी का भी जिक्र किया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयानों में भारत और पाकिस्तान को तराजू के पलड़ों में एक समान रखा। यह भारत के लिए अटपटी सी स्थिति थी क्योंकि भारत ने अब तक कभी भी किसी तीसरे देश की भूमिका, भारत-पाक संबंधों में स्वीकार नहीं की थी।

क्या संसद में प्रधानमंत्री इस बात को जोर देकर कहेंगे कि राष्ट्रपति ट्रंप का कथन गलत है और उनकी कोई भूमिका इस युद्ध विराम में नहीं थी? इससे देश आश्वस्त होगा कि भारत ने पाकिस्तान से संबंधित अपनी इस नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया है कि वह किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा।

चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न, बिहार में चल रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में है। चुनाव आयोग द्वारा इस कार्रवाई के अंतर्गत बिहार के सभी आठ करोड़ मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरवाया जा रहा है। इनमें से दो तीन करोड़ मतदाताओं को अपना स्वयं का और माता / पिता का जन्म प्रमाण पत्र भी गणना प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। यह एक तथ्य है कि बिहार के लाखों लोग राज्य के बाहर अन्य राज्यों में कार्य हेतु जाते हैं। गहन पुनरीक्षण का निर्णय लेते समय चुनाव आयोग ने यह बिल्कुल नहीं सोचा कि कैसे भारी बरसात के बीच ये लोग अपना काम छोड़कर यह प्रपत्र भरने के लिए बिहार जाएंगे और कैसे ये लोग अपने माता या पिता का जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त कर पाएंगे? ऐसा लगता है कि इस पुनरीक्षण की प्रक्रिया के बाद लगभग डेढ़-दो करोड लोग ऐसे होंगे जिनके प्रपत्र दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत नहीं हो पाएंगे और इस कारण उनके नाम मतदाता सूचियों से काट दिए जाएंगे। तदनुसार ये लोग नवंबर में होने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में मत नहीं दे पाएंगे। सोशल मीडिया के कुछ लोगों जैसे अजीत अंजुम द्वारा बिहार में फील्ड पर किए जा रहे सर्वे के आधार पर यह रिपोर्ट सामने आई है कि बी एल ओ, अपने ही स्तर पर मतदाताओं की ओर से फॉर्म भरकर और हस्ताक्षर करके जमा कर रहे हैं और मतदाताओं को इसकी कोई जानकारी नहीं है। यह बात भी सामने आई है कि मतदाताओं को गणना प्रपत्र की एक प्रति नहीं दी जा रही है जैसे कि चुनाव आयोग के निर्देश हैं। इस प्रकार की दोषपूर्ण प्रक्रिया से मतदाताओं को अपने अधिकार से वंचित करने की कार्यवाही के संबंध में सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। यह सब क्यों किया जा रहा है जबकि बिहार में चुनाव नवंबर में हैं ? चुनाव आयोग यह सब मतदाताओं की नागरिकता जांचने के नाम पर कर रहा है जबकि कि भारत का कोई भी नागरिक अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर सकता। सरकार द्वारा नागरिकता का प्रमाण देने की कोई व्यवस्था ही नहीं की गई है। चुनाव आयोग द्वारा ऐसा इस समय यह सब क्यों किया जा रहा है, इस बारे में स्थिति, सरकार को स्पष्ट करनी होगी। यदि ऐसा नहीं किया गया तो सरकार एवं चुनाव आयोग के उद्देश्य पर संदेह के बादल हमेशा मंडराते रहेंगे। लोगों में भी यह आशंका बनी रहेगी कि इस पूरी कार्यवाही का उद्देश्य सत्ताधारी दल के विपक्षियों के नाम मतदाता सूची से बाहर करना ही तो नहीं है? इस पर विस्तृत चर्चा अत्यंत आवश्यक है, जिसे केवल यह कहकर यह नहीं टाला जा सकता कि यह प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।

विपक्षी दलों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी कारण से संसद स्थगित न हो और जिन भी नियमों में संभव हो, उनके अंतर्गत वे चर्चा करें, ताकि सरकार और प्रधानमंत्री को विभिन्न विषयों पर उठाए गए विषयों पर उत्तर देने के लिए बाध्य होना पड़े। सकारात्मक विपक्ष का काम केवल यह नहीं है कि हंगामा करके सत्र को बंद करवा दें। ऐसा करके वे सरकार की ही सहायता करेंगे।

पांचवा महत्वपूर्ण विषय लोकसभा एवं विधानसभा क्षेत्र के पुनर्सीमांकन का है। यदि जनसंख्या के आधार पर ही सीटों का सीमांकन किया जाता है तो यह संभावना है कि उत्तरी भारत की तुलना में दक्षिण भारत के राज्यों की लोकसभा सीटों की संख्या में बहुत कमी आ सकती है। इस कारण दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व संसद में बहुत हो जाएगा। इसी कारण दक्षिणी राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। इस संबंध में सरकार को अपनी सोच स्पष्ट करनी चाहिए। छठवां विषय जिस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, वह अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट ए आई 171 के उड़ान भरते ही क्रैश होने के संबंध में है।

इस दुर्घटना में 260 व्यक्तियों की जान चली गई।अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दुर्घटना का कारण क्या रहा? कहीं यह कारण तो नहीं था कि सरकार की विभिन्न सुरक्षा नियामक एजेंसियों में कर्मचारियों /अधिकारियों की अत्यंत कमी है और जिसके कारण पर्याप्त सुरक्षा जांच, उड़ान से पूर्व संभवतया नहीं हो पाई ? अब तक प्राप्त अंतरिम रिपोर्ट से ज्ञात हुआ है कि ईंधन के स्विच 'कट ऑफ' हो जाने के कारण इंजन बंद हो गए और यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस बारे में स्पष्ट और विस्तृत जानकारी संसद सदस्यों को सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए।

सातवां महत्वपूर्ण बिंदु जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करने से संबंधित है। इसका आश्वासन तो सरकार 2019 से ही दे रही है। हाल ही में श्रीनगर में शहीद दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को अपने घर से बाहर निकलने के लिए दीवार फांदकर जाना पड़ा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस और स्थानीय पुलिस द्वारा उन्हें रोका जा रहा था। किसी भी राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री को अपने ही देश में ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े और पुलिस बलपूर्वक रोकने का प्रयास करे तो यह संसद में चर्चा का विषय तो बनेगा ही। सरकार को यह बताना होगा कि क्यों जम्मू कश्मीर को अब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा है?

प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न घोषणाओं की वास्तविकता के बारे में भी संसद में प्रश्न उठेंगे जिसका उत्तर प्रधानमंत्री को देना चाहिए। उदाहरण के लिए बिहार के मोतिहारी में चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उस जिले में 3 लाख लोगों को पक्के आवास बनाकर दे दिए गए, जबकि सरकार की वेबसाइट के अनुसार ही अब तक कुल 14000 व्यक्तियों को ही मोतिहारी जिले में आवास मिले। गलत बयान देने के बारे में संसद सदस्य प्रधानमंत्री से जवाब मांग सकते हैं और प्रधानमंत्री से अपेक्षा रहेगी कि वे स्थिति स्पष्ट करें।

कावड़ यात्रा में के दौरान कांवड़ियों द्वारा सीआरपीएफ के जवान को पीटने की घटना भी चर्चा का विषय बन सकती है। इस बारे में विभिन्न प्रकार की घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा स्थिति स्पष्ट किए जाने की अपेक्षा सांसदों और देश को रहेगी।

इस वक्त हाल ही में बरसात के कारण देश के कई उच्च राज मार्ग, राष्ट्रीय उच्च मार्ग एवं कई पुल दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर गए जिसके कारण कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। जिस गति से बिहार और गुजरात में पुल टूटे हैं वह न केवल जनता के धन की बर्बादी को दर्शाता है अपितु भ्रष्टाचार की ओर इशारा भी करता है। बिहार के सांसद इस बारे में चर्चा की आशा रखेंगे।

गत कुछ सत्रों का अनुभव यह रहा है कि सरकार किसी भी विवादास्पद विषय पर चर्चा करने से बचती रही है और प्रधानमंत्री स्वयं भी ऐसे समय सदन में उपस्थित नहीं रहते हैं। कई बार तो सत्ताधारी दल के सांसद ही हंगामा करने लग जाते हैं जिसके कारण सरकार अपने जवाब देने के उत्तरदायित्व से बच निकलती है। विपक्षी दलों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी कारण से संसद स्थगित न हो और जिन भी नियमों में संभव हो, उनके अंतर्गत वे चर्चा करें, ताकि सरकार और प्रधानमंत्री को विभिन्न विषयों पर उठाए गए विषयों पर उत्तर देने के लिए बाध्य होना पड़े। सकारात्मक विपक्ष का काम केवल यह नहीं है कि हंगामा करके सत्र को बंद करवा दें। ऐसा करके वे सरकार की ही सहायता करेंगे। आशा की जानी चाहिए कि इस सत्र में विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर गंभीर बहस होगी और विपक्ष सरकार को मजबूर करेगा कि वह एवं उसके मुखिया, प्रधानमंत्री विभिन्न प्रमुख मुद्दों पर सरकार का रुख स्पष्ट करेंगे। अच्छा होगा यदि प्रधानमंत्री स्वयं संसद के सत्र के समय महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के दौरान सदन में उपस्थित रहें।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

नई राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी से सुनियोजित शहरी विकास को गति मिलेगी

■ **रहवासियों को सुनिश्चित होंगी बुनियादी सुविधाएं, निवेश के द्वार खुलेंगे, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी**

युवराज

विकसित राजस्थान-2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में सुनियोजित नगरीय विकास की अहम भूमिका है। इससे आर्थिक गतिविधियों को तेजी से बढ़ावा मिलता है जिससे बुनियादी ढांचे में निरंतर सुधार आने के साथ-साथ निवेश और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है।

इसी लक्ष्यों की प्राप्ति के क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक ने नई राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी का अनुमोदन किया है, जिससे राजस्थान सुनियोजित नगरीय विकास के क्षेत्र में अठाणी राज्य बन सकेगा। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2024 के प्रावधान ऐसी योजनाओं के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हैं जिनमें रहवासियों को बेहतर जीवन स्तर मिल सके। जिसमें सुबह की सैर के लिए पार्क भी हो और वर्षा तथा अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण की व्यवस्था भी हो। नीति के अंतर्गत सभी योजनाओं में हरित क्षेत्र की अनिवार्यता की गई है। सभी क्षेत्रफल की आवासीय योजनाओं में एकरूपता के दृष्टिगत 7 प्रतिशत पार्क-खेल मैदान एवं 8 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया गया है।

अंत्योदय की परिकल्पना होगी साकार, जरूरतमंद को मिलेगा आवास :-जरूरतमंद को आवास जैसी बुनियादी सुविधा का लाभ सुनिश्चित हो, इस ध्येय को भी नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। नीति के अंतर्गत सभी योजनाओं में ईडब्ल्यूएस-एलआईजी हेतु आरक्षित भूखण्डों का आवंटन स्थानीय निकाय के माध्यम से किये जाने का प्रावधान रखा गया है। इस प्रावधान से पात्र ईडब्ल्यूएस-एलआईजी व्यक्तियों को आवास की उपलब्धता पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही, औद्योगिक योजनाओं में श्रमिकों के निवास के लिए न्यूनतम 5 प्रतिशत क्षेत्रफल के भूखण्ड का प्रावधान किया गया है। इससे श्रमिकों को औद्योगिक इकाइयों के समीप ही आवास उपलब्ध हो सकेंगे जिससे उनको आवागमन के समय में बचत होगी और उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि भी होगी।

नीति में विकासकर्ता पर जवाबदेहिता और रहवासियों के लिए सुविधायुक्त आवासों का प्रावधान शामिल किया गया है। इसके लिए योजना के पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी होने के पश्चात विकास कार्यों का रख रखाव 5 वर्ष की अवधि अथवा रेजीडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) को हस्तान्तरण किया जाने तक योजना के 2.5 प्रतिशत भूखण्ड रहन रखे जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, आंतरिक विकास कार्यों के रख-रखाव हेतु रखरखाव शुल्क का प्रावधान भी किया गया है। नीति के क्रियान्वयन, निगरानी एवं समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय समिति के गठन का प्रावधान किया गया है, जिससे शहरी योजनाओं के विकास में आने वाली समस्याओं का त्वरित निदान हो सकेगा।

लम्बवत विकास को मिलेगा प्रोत्साहन :-शहरी क्षेत्रों का निरंतर विकास भूमि की उपलब्धता को सीमित करता है। ऐसे में आवश्यक है कि बहुमंजिला योजनाओं पर विशेष जोर दिया जाए। नई टाउनशिप पॉलिसी लम्बवत विकास को बढ़ावा देती है। इससे कम क्षेत्र में भी अधिक आवासों का निर्माण हो सकेगा और अधिक से अधिक लोग निवास कर सकेंगे। इसके साथ ही नीति के अंतर्गत मिश्रित भू-उपयोग योजना, समूह आवास योजना, फ्लैट आवास योजना, एकीकृत योजना (समूह आवासीय, फ्लैट आवासीय, प्लोटेड), वाणिज्यिक भू-उपयोग में आमजन की सुविधा के लिए सब सिटी सेन्टर, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, कम्युनिटी सेन्टर का प्रावधान भी किया गया है।

आवागमन में होगी सुविधा, बन सकेंगे सेक्टर रोड्स :-नीति में बड़े सेक्टर रोड के निर्माण के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके अंतर्गत राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों में सेक्टर सडकों के निर्माण एवं उनके सहारे व्यावसायिक पट्टी के विकास के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण की सेक्टर कॉमर्शियल पॉलिसी की तर्ज पर आपसी सहमति से भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जा सकेगी।

साथ ही, यह नीति सौर और पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को भी प्रोत्साहित करती है। नीति अनुसार, इन संयंत्रों की स्थापना के लिए राजस्व रिकॉर्ड में पहुंचमार्ग दर्ज होने व पहुंचमार्ग की न्यूनतम चौड़ाई की बाध्यता नहीं रखी गयी है। इसके अतिरिक्त नीति में जलस्त्रोतों के संरक्षण को भी बढ़ावा दिया गया है। इसमें नदी, झील, तालाब, नहर, नाला, बरसाती नालों जैसे विभिन्न जल स्त्रोतों के संरक्षण के लिए इनके सहारे आवश्यक न्यूनतक बफर आरक्षित किये जाने का प्रावधान रखा गया है।

युवराज, पी.आर.ओ., सीएमओ।

मतदाता सूची : 1952-नाम जोड़ो, 2025-नाम काटो, (52-25-संदर्भ - बिहार विधानसभा चुनाव)

रामनिवास बैरवा

पहले आम चुनाव मार्च-अप्रेल, 1952 में सम्पन्न हो चुके थे। उस समय की मतदाता सूची चर्चा आज 1925 में (बिहार चुनावों के संदर्भ में) भी आवश्यक है। जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 में बनाया गया था और 1951 में भी दूसरा कानून बनाया गया था। 1950 के कानून में मतदान क्षेत्रों का सीमांकन तथा मतदाता सूची आदि के संबंध में प्रावधान थे, तो 1951 के कानून में चुनाव संबंधी अन्य तामझाम का नियमन था जिसमें मतदाताओं की पात्रता-अपात्रता के अलावा चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों की योग्यता-अयोग्यता का जिक्र था। 1951 के जन प्रतिनिधित्वकानून का भाग सात, जिसका शीर्षक था "करप्ट एण्ड इल्लीगल प्रेक्टिसेज एण्ड इलेक्टोरल ओफेंसेज" था। 1957 के दूसरे आम चुनावों के ठीक छः महिने पहले, 28.08.1956 के संशोधन के द्वारा इसको बदलकर सिर्फ "करप्ट प्रेक्टिसेज एण्ड इलेक्टोरल ओफेन्सेज" करने के लिए 'इल्लीगल प्रेक्टिसेज' को हटाकर गैर-कानूनी काम करने वालों के लिए चुनाव लड़ने का रास्ता साफ किया गया था। इन संशोधनों के पीछे मतदाता सूचियों की भूमिका थी।

1952 के पहले 1951 में जनगणना हुई थी, उसी के साथ मतदाता सूचियां बनाने का काम भी किया गया था। करीब 17.5 करोड़ मतदाताओं की सूची बनाई गई थी। उस समय कई ग्रामीण स्त्रियां अपना नाम नहीं बतायीं- सामान्यत: स्त्रियों के नाम 'फलाने की पत्नी' या 'फलाने की पुत्री' के नाम से दर्ज की गई थी। तब उच्च अधिकारियों के ध्यान में यह तथ्य लाये जाने पर ऐसे नामों को हटा दिया गया था, पूरे देश की मतदाता सूचियों में से कुल 31 लाख से अधिक नाम हटाये गये थे। लेकिन, आज 2025 में मतदाता सूचियों में से अधिक से अधिक नाम कैसे हटाये जायें, चुनाव आयुक्तों का मुख्य कार्य बन गया है। प्रारम्भिक जानकारियों के अनुसार, मौजूदा बिहार में मतदाता सूचियों में से 37.50 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिये गये हैं, जबकि अभी लोगों से निर्धारित फार्म भरवाने का काम भी पूरा नहीं हुआ है। मतदाता सूचियों में से मतदाताओं के नाम हटाने-जोड़ने का कार्य सत्ता पर आसीन पाटियों और पार्टी के लोगों का लक्ष्य है जिससे कि वे सत्ता में अपना बहुमत सुनिश्चित कर सकें।

1957 के आम चुनावों के लिए पुरानी मतदाता सूचियों से संशोधन करके काम चलाया गया था। जहां उत्तर भारत में गैर-कानूनी कामों में लगे प्रत्याशी (अगस्त, 1956 के संशोधनों के आधार पर) बने थे जो कि पार्टी के नाम से चुनाव जीते थे। गांधी जी की कांग्रेस के साथ भावनात्मक लगाव के कारण उत्तर भारत के काफी ज्यादा संख्या में अशिक्षित पुरूष और महिलाएं बिना प्रत्याशी के चारित्रिक और कानूनी गुणदोषों के मूल्यांकन के मतदान करके जिताये गये थे। परन्तु केरल के शिक्षित मतदाताओं ने कांग्रेस के बदले भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के नम्बूदरीपाद को राज्य की सरकार बनाने के लिए चुना था। यह मतदाता और मतदान करने वाले व्यक्तियों का कमाल था। लेकिन, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष इन्दिरा गांधी और प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने 1959 में भारतीय कम्यूस्टि पार्टी की सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया था।

आगामी चुनावों के मतदाताओं के मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने और नाम काटने का अधिकार चुनाव आयोग को देने के लिए 1959 में "संसद (अयोग्यता से बचाव) अधिनियम" बनाया गया तथा 1960 में "मतदाताओं का पंजीकरण नियम" बनाये गये जिससे 1962 के चुनावों को तद्नुसार प्रभावित किया जा सके। 1971 के आम चुनावों के बाद 1977 के आम चुनाव 'आपातकाल' के साये से निकले मतदाताओं ने महत्वपूर्ण, लेकिन भावनात्मक रूप से कांग्रेस के विरूद्ध मतदान किया। जिसके परिणामस्वरूप गैर-कांग्रेसी जनता पार्टी की सरकार बनी।1984 के मध्यावधि चुनाव इंदिरा गांधी की हत्या के भावनात्मक वातावरण में हुए और राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को अप्रत्याशित बहुमत मिला। लेकिन भ्रष्टाचार के मामलों में कुछ कथित चरित्रवान नेता जनता के बीच कांग्रेस के खिलाफ जाने को थे। इसी सम्भावना को देखकर, आपात्काल के दौरान दिख रहे युवक कांग्रेस और एन.एस.यू.आई. के प्रभाव को भुनाने के लिए राजीव की कांग्रेस ने खास संशोधन करके मतदाताओं की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की कि नया खून नये जोश में अपेक्षाकृत युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व को समर्थन देंगे। साथ ही दल-बदल विरोधी कानून बनाने की आड़ में राजनीतिक पार्टियों को संवैधानिक दर्जा देकर योग्य व्यक्तियों को चुनने का अधिकार भी मतदाताओं से छीन लिया गया। लेकिन इन सबका फायदा कांग्रेस को नहीं मिला, इसके विपरीत नैतिकता, चारित्रिक सुचिता और राष्ट्रप्रेम के तहत गैर कांग्रेसी विश्वनाथ प्रताप सिंह को सत्ता के शिखर पर पहुंचाया जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भावनात्मक राष्ट्रवादी नारों के तहत काम कर रहे लागों का समर्थन भी था। वी.पी.सिंह ने ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करके हिन्दू-मुस्लिम के धार्मिक आधारों पर बंटे मतदाताओं को जातियों में भी बांटने का रास्ता साफ कर दिया। जातियों के आधार पर मतदाताओं के बंटने से क्षेत्रीय पार्टियां तो उभरीं। 2004 में समय से कुछ समय पहले चुनाव करवाये और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी। मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। गुजरात में नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते आर.एस.एस. की सभी नीतियों को बखूबी लागू किया- क्योंकि वह संघप्रचारक रह चुके थे। पर्याप्त धन इकट्ठा करने के साथ-साथ राजनीतिक ताने-बाने को तथा प्रशासनिक ढांचे को आर.एस.एस. की नीतियों के अनुसार ढालने में सफल रहे थे, अत: आगामी 2014 के आम चुनावों में नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया तथा प्रधानमंत्री बना दिया गया।

अब आर.एस.एस. और भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य रह गया था कि जैसे भी हो सरकार में बना रहने के लिए चुनावों को हमेशा अपने पक्ष में बनाना। इस काम में मतदाता सूचियां मुख्य भूमिका निभाती हैं, यह निर्विवाद है और जिसकी कुंजी चुनाव आयुक्त के पास होती है। इसीलिए, नरेंद्र मोदी ने सीधे जिला कलेक्टरों से मीटिंगें कीं। मध्यम और नीचे के आई. ए. एस. अधिकारी भावनात्मक रूप से इससे अपना बड़ा हुआ महत्व मानने लगे। चंडीगढ़ से लेकर महाराष्ट्र तक अपनी सफल भूमिका निभाने के बाद चुनाव आयुक्त पर विभिन्न राज्यों के चुनाव और फिर 2029 के लोकसभा चुनाव में इसे दोहराना बाकी है। फिलहाल, बिहार की विधानसभा के आम चुनावों में मतदाता सूचियों को मुख्य मुद्दा बनाकर आर.एस.एस. की नीतियों को सापेक्ष रूप से और भी सफल बनाने का आयोजन हाथ में ले लिया गया है।

काफी समय से मुसलमानों को अलग-थलग करने के प्रयास में एक प्रयास यह भी रहा है कि बांग्लादेशियों ने नाम से अधिक से अधिक संख्या में उनके नाम मतदाता सूचियों से हटाये जायें। दूसरा, बिहार में सभी जातियों में पिछड़ी और अछूत जातियों की बहुतायत क्षेत्रीय पार्टियों के पक्ष में है- लेकिन इन्हीं में से अधिक दूसरे राज्यों में मजदूरी के लिये गये होते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, लेकिन लोकतन्त्र के मतदान के अधिकार ने उनमें पर्याप्त जागरूकता पैदा की है, इसीलिए प्रत्येक चुनावों में वे अन्य राज्यों से आकर बिहार के अपने-अपने क्षेत्रों में मतदान करते हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी को बिहार में चुनावों में सफलता प्राप्त करने में काफी कठिनाई होती है। इसी को लक्ष्य करके अभी बिहार में मतदाता सूचियों में व्यापक संशोधन किया जा रहा है।

चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोर्स रूल्स, 1960 का सहारा लेकर मतदाता सूचियों में व्यापक संशोधन की निर्धारित प्रक्रिया को अपनाते हुए प्रत्येक मतदाता से दो प्रतियों में फार्म भरवाये जा रहे हैं लेकिन प्रशासन के बूथ लेवल ऑफिस (बी.एल.ओ.) जो कि ऊपर के आई.ए.एस. अधिकारियों, जिला कलेक्टरों के दिशा-निर्देश में काम करते हैं- दो की जगह एक ही फॉर्म दे रहे हैं और वो भी आधा-अधूरा भरवाकर इकट्ठा करके संबंधित मतदाता सूची पोर्टेल पर चढ़ाने की कसरत कर रहे हैं। फॉर्म भरवाने का काम अभी जारी है-परंतु चुनाव आयेग ने अपनी दक्षता का बखान करते हुए घोषणा कर दी कि करीब 37.5 लाख नाम मतदाता सूचियों में से हटा दिये गये हैं। प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही फैसला कर लिया गया? जाहिर है बांग्लादेशियों के नाम परमुसलमानों के तथा दूसरे राज्यों में मजदूरी के लिये गये बिहारियों को अनुपस्थित मानकर पहले ही योजनानुसार नाम हटा दिये गये हैं। इसका परिणाम बिहार विधानसभा के चुनावों में देखा जायेगा। विडंबना देखिए कि एन. आर. आई. लोगों को मतदाता सूचयों में जोड़ने के लिए 2011 में कानून में संशोधन किया गया वहीं दूसरे प्रांतों में रहने वालों के, जो कि मतदाता सूची संशोधन के समय अपने दिये गये पतों पर अनुपस्थित पाये जायें, उनके नाम हटाये जा रहे हैं। कैसी विडम्बना है, 1952 के चुनावों के समय जहां मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने की मुहिम चलाई गई थी, वहीं अब 2025 में नाम हटाने की मुहिम चलाई जा रही है। 1952 में भारत की जितनी आबादी थी यानि कि 37 करोड़, उससे ज्यादा नाम तो केवल बिहार की मतदाता सूचियों में से हर हटा दिये गये हैं। क्रमशः पूरे भारत में कितने नाम हटाये जायेंगे, देखना बाकी है।

- राम निवास बैरवा,
पूर्व क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

राशिफल मंगलवार 22 जुलाई, 2025

पंडित अनिल शर्मा

सावन मास, कृष्ण पक्ष, द्वादशी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2082, मृगशिरा नक्षत्र सायं 7:25 तक, शुक्र योग दिन 3:32 तक, तैतिल करण प्रात: 7:06 तक, चन्द्रमा प्रात: 8:15 से मिथुन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कर्क चन्द्रमा-वृष, मंगल-सिंह, बुध-कर्क, गुरू-मिथुन, शुक्र-वृष, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज द्विपुष्कर और राजयोग सूर्योदय से प्रात: 7:06 तक है। यमघट योग सायं 7:25 से सूर्योदय तक है। आज भद्रा रात्रि 4:40 से आरम्भ होगी। आज सायन सिंह में सूर्य प्रवेश सायं 7:00 पर होगा। आज भौम प्रदोष व्रत है। आज त्रयोदशी तिथि का क्षय हुआ है। आज मंगला गौरी पूजा, कैर पूजा है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:11 से 10:52 तक, लाभ-अमृत 10:52 से 2:14 तक। शुभ 3:55 से 5:35 तक।

राहूकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 5:50, सूर्यास्त 7:16

मेष

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। आज परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक यात्रा संभव है।

वृष

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त हो सकता है। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन

व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। सुख-सुविधाओं पर धन खर्च हो सकता है।

कर्क

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक/व्यक्तिगत कारणों से मन में असंतोष बना रहेगा। आज अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है।

सिंह

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

कन्या

व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

तुला

व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी।

वृश्चिक

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

धनु

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

मकर

स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अनहोनी की आशंका से बना हुआ मन का भय दूर होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा।

कुंभ

व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। महत्वपूर्ण कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।

मीन

घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

'आपदा की समस्या होने पर कंट्रोल रूम में सूचना दें'

करौला, (निंसं.) जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने बताया कि वर्तमान समय में वर्षा का मौसम जारी है वर्षा से संबंधित जिले में प्रशासन अलर्ट मोड पर कार्य कर रहा है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में नदीयों, तालाबों और जलाशयों के जल स्तर संबंधी एवं संभावित प्रभावित ईलाकों में सतत् निगरानी रखी जा रही है। इस संबंध में जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है जो कि 24 घंटे संचालित है। उन्होंने बताया कि नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नम्बर 07464-251335 रहेगा व उक्त नम्बर पर 1077 की सुविधा भी उपलब्ध भी रहेगी। इस संबंध मे उन्होने प्रभारी अधिकारी व अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी एवं नियंत्रण कक्ष हेतु कार्मिकों को नियुक्त कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिये है। इसके अलावा जल संसाधन विभाग का केन्द्रीय बाढ नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नम्बर 0141-2702480, भारत मौसम विज्ञान विभाग दूरभाष नं. 0141-2173733 व राज्य स्तरीय प्रभारी अधिकारी कार्यालय के दूरभाष नं. 0141-2227084 रहेगा।

पंचायत समिति नहीं कर रही ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई

करौली, (निंसं.) कैलादेवी के गत वर्ष लक्खी मेले के दौरान ग्राम पंचायत कैला देवी द्वारा बस और कार पार्किंग के टेंडर दिए गए थे जिनकी राशि आज तक जमा नहीं होने एवं ठेकेदार द्वारा ठेका की राशि के दिए गए चैको के अनादरन होने के बाद ग्राम पंचायत कैलादेवी और पंचायत समिति करौली द्वारा आज तक ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही नही की गई और ना ही उक्त मामले की चल रही जांच भी आज तक पूरी होने का नाम नहीं ले रही है।

श्री कैलादेवी चैत्र मेला 2024 में मेले की व्यवस्थाओं को लेकर बस पार्किंग का ठेका 11 लाख 15हजार रुपये की अधिकतम बोली रही इसी प्रकार कार पार्किंग की 21 लाख 11हजार रुपये अधिकतम बोली रही इसके अलावा मनोरंजन के लिए झूला का 2 लाख 15हजार रुपये कि अधिकतम बोली रही थी इस प्रकार ठेका की कुल राशि 35 लाख 38 हजार 500 रुपये थी जिसमें से ठेकेदार ने कुछ राशि चैक के जरिए जमा कर दी और शेष राशि करीब 22 लाख 15हजार रुपये के ग्राम पंचायत को चैक दे दिए थे जिसको लेकर तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी को जिला कलेक्टर ने 7 अप्रैल 2024 को निलंबित कर दिया था उसके करीब 15 दिन बाद यानी 23 अप्रैल को ग्राम पंचायत ने शेष ठेका की राशि 22 लाख 15हजार रुपये के चैको कि राशि प्राप्त करने के लिए बैंक में चैक लगा दिए लेकिन ठेकेदार के खाते में राशि का अभाव होने से बैंक ने चैक को अनादरन कर दिया इस बार फिर से ग्राम पंचायत ने उन्ही चैको को 12 जून को पुन: बैंक में लगाया जिसको भी बैंक में राशि के अभाव में अनादरन कर दिया था जो मामला आज तक बड़े चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि कैलादेवी के लक्खी मेला और नवरात्र मेला में हर वर्ष ग्राम पंचायत की आय बढ़ाने और मेले की व्यवस्थाओं के लिए ठेके होते चले आ रहे हैं मगर वर्ष 2024 के मेले में हुए ठेकों की राशि आज तक जमा नहीं हो पाई जिसकी जांच भी चल रही है लेकिन ठेकेदारों के चैक अनादरन होने के मामले को ग्राम पंचायत ने आज तक गंभीरता से नहीं लिया गया है ना ही पंचायत समिति करौली ने इसे गंभीरता से लिया है यही नहीं मामले के जांच अधिकारियों ने पूरे मामले को ठंडे बस्ते में बंद कर रखा है जो एक आम चर्चा का विषय बना हुआ है गंभीर जनक बात यह है कि इतनी बड़ी राशि के जमा नहीं होने के मामले में क्या ग्राम पंचायत का ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही करने की जिम्मेदारी नहीं बनती है और यदि जिम्मेदारी बनती है तो डेड वर्ष पूरे होने वाले हैं उसके उपरांत भी कोई कार्यवाही नहीं की जिससे ग्राम पंचायत प्रशासन की मिली भगत होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है इससे बड़ी गंभीरता यह भी देखी जा रही है कि मामले की जांच एक कछुआ चाल के तहत चल रही है जिस जांच को चलते 18 माह पूरे होने जा रहे हैं लेकिन जांच का परिणाम अभी तक सामने नहीं आ रहा है इधर ग्राम विकास अधिकारी ने निलंबित होने के बाद जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एवं करौली पंचायत समिति के विकास अधिकारी को लिखित में अपना निर्दोष होने का स्पष्टीकरण देने के साथ ही ग्राम पंचायत सरपंच एवं ठेकेदारों की मिली भगत का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई और कैलादेवी के मेले में आए हुए सभी राशि का हिसाब और ग्राम पंचायत की व्यवस्थाओं के लिए खर्च की गई राशि का भी लिखित में हिसाब मांगा ग्राम विकास अधिकारी को निलंबन से अब बहाल कर दिया गया है। इस मामले में पंचायत समिति करौली के विकास अधिकारी अजीत सिंह का कहना है कि हां मामला तो गंभीर है और उसकी जांच कमेटी गठित कर कराई जा रही है जांच कमेटी से मामले की अब शीघ्र जांच करने के भी निर्देश दिए हैं।

सार-समाचार

30 अवैध नल कनेक्शन काटे, अवैध कनेक्शनकर्ताओं को थमाए नोटिस

भरतपुर (निस)। चम्बल-धौलपुर-भरतपुर पेयजल परियोजना की पाईपलाइन में किये गये अवैध कनेक्शनों को काटकर अवैध कनेक्शन कर्ताओ नोटिस जारी किये गये हैं। अधिशाषी अभियन्ता जन स्वा. अभि. विभाग गोखलेस बसवाल ने बताया कि सोमवार को सेवर क्षेत्र के ग्राम मलाह से रामनगर को जाने वाली चंबल परियोजना की क्लस्टर पाइपलाइन में से अवैध कनेक्शन काटने के अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि विभागीय टीम द्वारा पाइपलाइन को क्षितग्रस्त करने वाले 30 अवैध कनेक्शनों को काटकर नोटिस जारी किये गये। अवैध कनेक्शनकर्ताओ को नोटिस जारी करते हुऐ समझाइश भी की गई कि अवैध कनेक्शन करके विभागीय सम्पत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाए। उन्होंने अवैध कनेक्शन कर्ताओं को बताया कि एक बार अवैध कनेक्शन काटने के बाद पुनः कनेक्शन पाए जाने पर लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। कनेक्शन काटने की कार्यवाही के दौरान सहायक अभियन्ता शैलेन्द्र सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता सतीश कुमार एवं फर्म प्रतिनिधि उमेश कटारा, अनिल लाटा एवं हरदयाल मौजूद रहे।

उपखंड अधिकारी सहित विभिन्न अधिकारियों ने जल भराव क्षेत्रों का जायजा लिया

करौली, (निंसं.) जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना के निर्देशों की पालना में उपखंड अधिकारी प्रेमराज मीणा, तहसीलदार, विकास अधिकारी करौली के द्वारा मामचारी बांध, खोहरी बांध का निरीक्षण किया गया एवं सुरक्षा के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश विभाग के अधिकारियों को दिये। वर्षा के मौसम को देखते हुए उन्होंने अधिकारियों को लगातार जल भराव क्षेत्रों के निरीक्षण करने के भी निर्देश दिये। इसके अलावा तहसीलदार सपोटरा के द्वारा विभिन्न बहाव क्षेत्रों जैसे हाडौती से आगे बनास की नदी की पुलिया सहित उसके आस पास जल भराव क्षेत्रों का निरीक्षण किया एवं आवश्यक दिशा निर्देश उपस्थित अधिकारियों को दिये। इसके पश्चात संभागीय आयुक्त के निर्देशों की पालना में रणगंवा ताल की साफ सफाई की गई एवं नियमित साफ सफाई के निर्देश उपस्थित अधिकारियों को दिये।

ब्राह्मण समाज ने पौध रोपे

सवाईमाधोपुर। पर्यावरण संरक्षण के तहत सोमवार को ब्राह्मण समाज के लोगों ने कुस्तला गौशाला के सामने महर्षि गौतम चैरिटेबल ट्रस्ट में वृक्षारोपण किया। इस दौरान तुलसी बेलपत्र, अशोक एवं कई औषधीय पौधे लगाए गए। पर्यावरण संरक्षण के बारे में लोगो को जागरूक किया किया और वर्षा ऋतु में अधिकाधिक पौधे लगाने का सब से आव्हान किया गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण बहुत जरूरी है। इसी से वातावरण शुद्ध रहता है। सब जगह हरियाली रहती है। इस अवसर पर अखिल भारतवर्षीय श्री गुर्जर गौड़ ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय महासचिव आचार्य पंडित ताराचंद शास्त्री, प्रदेश सूचना प्रसारण मंत्री सुरेंद्र शर्मा, संभाग अध्यक्ष प्रहलाद गौतम, वैध हंसराज शर्मा, विनोद शर्मा, मनोज शर्मा, भगवान सहाय पंडित चंद्रकांत गौतम उपस्थित रहे।

रात्रि चैपाल आज

करौली,(निंसं.) जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने बताया कि आज 22 जुलाई मंगलवार को सांय 6.30 बजे से मासलपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कोटा (छाबर) में रात्रि चैपाल का आयोजन कर जन परिवेदनाएं सुनी जांएगी और मौके पर उनका त्वरित निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक तैयारियों के साथ उपस्थित होने के निर्देश जारी किये।

भरतुपर में स्मैश मास्टर बनी एंथनी प्रीमियर लीग सीजन-1 की विजेता

भरतपुर, (निस)। भरतपुर स्थानीय जवाहर नगर स्थित एंथौनी एकेडमी ऑफ टेबिल टेनिस में आयोजित एंथनी प्रीमियर लीग का फाईनल मुकाबला, पारितोषिक वितरण व समापन समारोह का आयोजन किया गया। एकेडमी के कोच ए ए बैन्ग्रो ने बताया कि 17 से 20 मध्य आयोजित एंथनी प्रीमियर लीग का फाईनल मुकाबला, पारितोषिक वितरण व समापन समारोह के मुख्य अतिथि सत्येन्द्र चतुर्वेदी, रजिस्ट्रार, भरतपुर थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अभिषेक, जिला खेल अधिकारी ने किया। समारोह में होली मदर एजूकेशनल एण्ड चौरिटेबिल सोसायटी के अध्यक्ष राजेन्द्र कुन्तल, विभिन्न विद्यालयों के खेल शिक्षक, अभिभावक आदि मौजूद थे। उन्होने आगे बताया कि फाईनल मुकाबला पेडल फयूरी व स्मैश मास्टर टीमों के मध्य खेला गया तथा स्मैश मास्टर ने मुकाबला जीत कर एंथनी प्रीमियर लीग सीजन-1 के विजेता बने तीनो खिलाडियों रक्षत, सकक्षम व शौर्य को अतिथियों द्वारा ट्राफी प्रदान की गई। इस अवसर सभी खिलाडियों को व मेन्टरस को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।

संभागीय आयुक्त के पर्यवेक्षण में जिला स्तरीय जनसुनवाई सम्पन्न

करौली, (निंसं.) राज्य सरकार के निर्देशानुसार नवीन त्रिस्तरीय जनसुनवाई व्यवस्था की अनुपालना में आमजन की परिवेदनाओं की सुनवाई एवं उनके त्वरित निस्तारण के लिए प्रातः 11:00 बजे संभागीय आयुक्त टीना सोनी की अध्यक्षता में डीओआईटी के वीसी कक्ष में जिला स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई।

राज्य स्तर से मुख्य सचिव सुधांश पंत ने वीसी के माध्यम से जनसुनवाई का निरीक्षण किया एवं औसत निस्तारण समय एवं संतुष्टिकरण के निर्धारित मानकों के आधार पर परिवेदनाओं के निस्तारण प्रकिया की जिलेवार समीक्षा की। साथ ही त्वरित व गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये। मुख्य सचिव ने कहा कि शिकायत निवारण प्रक्रिया किसी भी सरकार की जनकल्याणकारी नीति का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। आवश्यक सेवाओं सहित आमजन की समस्त समस्याओं को सम्मानपूर्वक सुना जाकर उनका समय से नियमानुसार संतुष्टिपूर्वक निस्तारण इस व्यवस्था की गुणवत्ता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि आमजन को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़े और न ही उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पडे। जनसुनवाई के दौरान संभागीय आयुक्त ने जिले में लंबित जनसुनवाई के प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की और गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण के निर्देश दिये। उन्होंने समस्त अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिला स्तरीय जनसुनवाई में एक बार प्रार्थी का आवेदन प्राप्त हो जाता है और पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा उसे संबंधित अधिकारी को कार्यवाही हेतु मार्क किया जाता है तो उसे संबंधित सक्षम स्तर का आदेश समझा जाए और उसकी अनुपालना में त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित कर परिवादी को राहत दिलायी जाए। जब तक किसी प्रक्रिया में अतिरिक्त निर्धारित आवेदन की अनिवार्यता न हो तब तक संबंधित प्रकरण में प्रार्थी से पुनः आवेदन के नाम पर अनावश्यक औपचारिकताओं में उलझा कर देरी नहीं की जाए और न ही प्रार्थी को बेवजह सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगवाये जायें। उसी आवेदन पर संतुष्टिपूर्वक कार्यवाही कर समस्या का तुरंत नियमानुसार समाधान करें। संभागीय आयुक्त ने राजस्थान संर्पक पोर्टल एवं मुख्यमंत्री कार्यालय एवं अन्यं दर्ज प्रकरणों का समय सीमा में निस्तारण करने एवं बजट घोषणाओं को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिये। जनसुनवाई में अतिरिक्त जिला कलेक्टर हेमराज परिडवाल सहित समस्त जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने मुख्य सचिव एवं संभागीय आयुक्त द्वारा दिये गये निर्देशों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया।

जनसुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों के 33 परिवाद प्राप्त हुए जिन पर संभागीय आयुक्त ने प्रत्येक परिवाद की व्यक्तिगत सुनवाई करके उसके त्वरित निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। इस दौरान अवैध कब्जा हटाने, रास्ते से अतिक्रमण हटवाने, सडक मरम्मत करवाने, पानी की टूटी लाईन को ठीक करवाने, बिजली की लाईन को दूर शिफ्ट करवाने, चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटवाने सहित विभिन्न परिवाद प्राप्त हुए। संभागीय आयुक्त ने दिये मोहनपुर में रजिस्ट्री कार्य तुरंत शुरू करने के निर्देश - संभागीय आयुक्त की जनसुनवाई के दौरान मोहनपुर में खेत की रजिस्ट्री से संबंधित एक परिवाद प्राप्त हुआ जिसमें परिवादी द्वारा संभागीय आयुक्त को अवगत कराया गया कि मोहनपुर में प्रार्थी सहित आमजन के रजिस्ट्री संबंधित कार्य नही हो पा रहे है।

इस पर संभागीय आयुक्त ने संबंधित अधिकारी को तत्काल तलब कर जवाब मांगा तो संबंधित तहसीलदार ने बताया कि पूर्व में मोहनपुर का एलआर करौली के बजाय कैलादेवी में दर्शा रहा था। जिसके लिए सक्षम स्तर से संशोधन हेतु प्रस्ताव भिजवाया गया। जिस पर सक्षम स्तर द्वारा एलआर में संशोधन कर मोहनपुर का एलआर कैलादेवी से करौली करने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। इस पर संभागीय आयुक्त ने परिवादी को संबंधित रजिस्ट्री अधिकारी से मिलने के लिए कहा और संबंधित अधिकारी को परिवादी की परिवेदना का तत्काल निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया। संभागीय आयुक्त के निर्देशों की अनुपालना में संबंधित रजिस्ट्री अधिकारी ने आश्वस्त किया की आज से ही मोहनपुर में रजिस्ट्री के कार्य प्रारंभ कर दिये जाएंगे।

आशा सहयोगिनियों ने निकाली रैली, विरोध प्रदर्शन किया

झुंझुनूं, (निसं)। आशा सहयोगिनी यूनियन (सीटू) की साथिन सूचना केंद्र पर इकट्ठा हुई। जहां से रैली के रूप में चलकर रामदेव करणीराम पार्क से होते हुए भगत सिंह सर्किल से वापस घूमते हुए शहीद स्मारक के आगे से होते हुए जिला मुख्यालय पर पहुंची। जहां पर आशा सहयोगिनियों ने नारेबाजी के साथ जबरदस्त प्रदर्शन किया। इसके बाद रैली विशाल जनसभा में बदल गई। सभा को संबोधित करते हुए सीपीएम जिला सचिव कॉमरेड राजेश बिजारणिया ने कहां कि आशा सहयोगिनियों को वेज के रूप में बहुत ही कम राशि मिलती है। जो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। सरकार को कम से कम 26000 रुपए महीना वेज करना चाहिए जो इनका अधिकार है। आशा सहयोगिनी यूनियन सीटू की जिलाध्यक्ष मंजू लालपुरिया ने कहा कि उनसे टीबी मरीजों के बलगम के सैंपल लेने के लिए कहा जाता है जो कि आशा सहयोगिनियों का काम नहीं है। इसके लिए हर पीएससी पर एक प्रशिक्षित कर्मचारी नियुक्त है। उससे काम नहीं करवाकर आशा सहयोगिनियों से करवाया जाता। जो आशा सहयोगिनी टीबी मरीजों के बलगम का सैम्पल लेती। वहीं आशा सहयोगिनी फिर नवजात शिशुओं का टीकाकरण करती है। जिससे नवजात शिशु के संक्रमित होने का बहुत बड़ा खतरा होता है। इस लिए रैली में आई हुई सभी आशा सहयोगिनियों ने जिलाध्यक्ष का एक स्वर में समर्थन किया और भरोसा दिलाया कि नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिले में कोई भी आशा सहयोगिनी टीबी मरीजों के बलगम का सैंपल नहीं लेगी। यह का वही कर्मचारी करेगा। जो इस कार्य के लिए प्रशिक्षित है तथा जिम्मेदार है। संगठन की चिड़ावा ब्लॉक अध्यक्ष अनू पारीक ने कहा कि हमारा ड्यूटी का समय निर्धारित किया जाए व ड्यूटी समय के बाद काम के बाध्य नहीं किया जाए। यह बर्दाश्त से बाहर है। हमारे भी घर परिवार है और सामाजिक जिम्मेदारियां भी है। जिनका भी निर्वहन करना होता है। खेतड़ी ब्लॉक से पूनम ने कहा कि आशा सहयोगिनियों से उनका मूल काम न करवाकर एएनएम अपना काम करवाती हैं। जो सरासर गलत है। अगर ऑनलाइन काम आशा से करवाना है तो उसके नाम की आईडी बनाकर उससे काम करवाया जाए। आशा सहयोगिनी यूनियन (सीटू) की कोषाध्यक्ष बृजेश ने कहा कि आशा सहयोगिनियों का दस प्रतिशत बढ़ ाया गया।

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में वृक्षारोपण किया

भरतपुर (निस)। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय कार्यालय प्रांगण में वृक्षारोपण किया गया वृक्षारोपण में नीम, अशोक, बरगद, गुलमोहर, हेमेलिया, जामुन गुलाब, मोगरा, मीठा नीम आदि के इक्यावन वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया यह वृक्षारोपण सेवानिवृत्ति संयुक्त निदेशक इंदिरा सिंह त्यागी, सेवानिवृत्ति प्रधानाचार्य, केदारनाथ पाराशर एवं सेवानिवृत्ति प्रधानाचार्य रूप किशोर शर्मा के सौजन्य से निशुल्क उपलब्ध कराए गये।

वृक्ष की तीन से चार फीट की ऊंचाई के वितरित किए गए। वृक्षारोपण के समय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय सुरेंद्र गोपालिया ,अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी नीलिमा छावडा ,अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी श्याम सिंह सागर ,प्रधानाचार्य एवं रेसा के जिला अध्यक्ष दीनदयाल तिवारी , कार्यालय के मंत्रालय कर्मचारी तथा अशोक शर्मा सारस उपस्थित हुए यह वृक्षारोपण का कार्यक्रम एक वृक्ष मां के नाम व हरियालो भरतपुर स्वच्छ सुन्दर भरतपुर के अंतर्गत किया गया साथ में सभी से यह अपील की गई कि पौधों की सुरक्षा व संरक्षण की जिम्मेदारी सभी कर्मचारी संभालें तथा सभी ने अपने उत्तरदायित्व को निर्वाह करने की सहमति दी कार्यक्रम के पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र गोपालया ने सभी का धन्यवाद हुआ आभार व्यक्त किया।

- **यह वृक्षारोपण सेवानिवृत्ति संयुक्त निदेशक इंदिरा सिंह त्यागी, सेवानिवृत्ति प्रधानाचार्य, केदारनाथ पाराशर एवं सेवानिवृत्ति प्रधानाचार्य रूप किशोर शर्मा के सौजन्य से निशुल्क उपलब्ध कराए गये**

वर्षा के मौसम में अधिकारी एवं कर्मचारी मुख्यालय नहीं छोड़े : कलक्टर

करौली, (निंसं.) जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने कहा कि जिले में वर्तमान समय में बारिश का मौसम जारी है। जिले में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बांधों, नदी, नालों के जल स्तर में वृद्धि हुई है इस दौरान समस्त उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी आमजन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता समझते हुए सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करें एवं इस दौरान कोई भी अधिकारी एवं कर्मचारी बिना बताये मुख्यालय नहीं छोड़े व लापरवाही करने वाले कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

जिला कलेक्टर सोमवार को मुख्यमंत्री के द्वारा रविवार को वीसी के माध्यम दिये गये निर्देशों की पालना के संबंध में राजीव गांधी सेवा केन्द्र के डीओआईटी के वीसी कक्ष में जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने सभी अधिकारियों को सरकार की मंशा के अनुसार कार्य करने, पेंडिंग चल रहे कार्यों का निस्तारण करने, सहायता के प्रकरणों का निस्तारण करने, बारिश के दौरान शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में जल भराव संबंधी समस्याओं का निस्तारण करने, जल भराव क्षेत्रों में आवश्यक संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता और आवश्यक सेवाओं को सुचारू रखने, इस दौरान प्रभावित लोगों को पेयजल व खाद्य सामग्री सहित जरूरी वस्तुओं की कमी नही होने देने, फील्ड भ्रमण करने, स्कूल, समाज कल्याण, आंगनबाडी केन्द्रों पर वर्षा के दौरान क्षितग्रस्त भवनों की सूचना शीघ्र भिजवाने, बनास, कालीसिल एवं पार्वती नदी के ओवरफ्लो के दौरान चंबल नदी के आसपास सपोटरा व मंडरायल वाले प्रभावित क्षेत्रों पर नजर रखने, राजस्थान संपर्क पोर्टल के प्रकरणों का संतुष्टिपूर्ण निस्तारण करने, आपदा राहत के संबंध में शॉर्ट एवं लॉन्गटर्म प्लान बनाने, ग्रामीण क्षेत्र में नदी, नालों, तालाबों के आसपास चेतावनी बोर्ड लगाने तथा आपदा प्रबंध में जिला प्रशासन द्वारा किये जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी आमजन तक पहुंचाने, आकाशीय बिजली एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओ से बचाव हेतु पुरी तरह सतर्क रहने, बाढ ग्रस्त मार्गों, नदी, नालों पुलों को पार करने से बचने के निर्देश उपस्थित संबंधित अधिकारियों को दिये।

जिला कलेक्टर ने बैठक में सीएमएचओ को वर्षा के मौसम में चिकित्सालयों में दवाईयों की उपलब्धता बनाये रखने, मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए घरों में जमा पानी को निकालने के संबंध में आमजन को जागरूक करने सहित सतर्क एवं सक्रिय रहकर कार्य करने के निर्देश दिये। उन्होंने वन विभाग के अधिकारी को हरियाली तीज 24 जुलाई को जिला स्तर पर पौधारोपण के संबंध में कार्यक्रम करने एवं वन विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, शिक्षा, चिकित्सा सहित अन्य विभागों की सहभागिता सुनिश्चित करने, दिये गये पौधारोपण के लक्ष्यों को 31 अगस्त तक पूर्ण करने, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अपूर्ण कार्यों को समय पर पूर्ण करने, राजस्व कार्यों का समय पर निस्तारण करने, समस्त उपखंड अधिकारी एवं जिला स्तरीय अधिकारियों को प्रत्येक माह में प्रथम,द्वितीय व तृतीय गुरूवार को होने वाली जनसुनवाई में शामिल होने, समस्त उपखंड अधिकारी एवं सानिवि के अधिकारी एक व दो दिन में 90 व 100 एमएम बारिश के दौरान टूटी हुई सडकों के मरम्मत के प्रस्ताव भिजवाने, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित खबरों को शीघ्र संज्ञान में लेकर कार्यवाही करने एवं पालना रिपोर्ट संबंधित विभाग को भिजवाने के निर्देश दिये।

'विभागीय योजनाओं में वंचितों को जोड़े'

- **समन्वित प्रयासों से जिले को विकास के पथ पर अठासर करें : संभागीय आयुक्त**

सवाई माधोपुर, । सम्भागीय आयुक्त भरतपुर डॉ. टीना सोनी की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार फ्लैगशिप योजनाओं, बजट घोषणा (2024-25 एवं 2025-26), राजस्थान सम्पर्क पोर्टल, आपदा राहत एवं विकास कार्यो की प्रगति समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में सम्भागीय आयुक्त भरतपुर डॉ. सोनी ने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी नियमित, सक्रिय व समन्वित प्रयासों से जिले को विकास के पथ पर अठासर करें। उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं से वंचित पात्र व्यक्तियों को प्राथमिकता से जोड़ा जाए ताकि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप अंतिम पंक्ति तक लाभ पहुँचाया जा सके। बजट घोषणाओं की समयबद्ध क्रियान्विति पर जोर देते हुए उन्होंने पीएचईडी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चिकित्सा, विद्युत व अन्य विभागों को उनके अधीन कार्यों की सतत मॉनिटरिंग कर निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए, जिससे जनहित की परियोजनाएं समय पर समर्पित की जा सकें। संभागीय आयुक्त ने मानसून के दौरान जनधन/पशुधन, आवासीय क्षित की जानकारी लेते हुए तत्काल राहत सुनिश्चित करने एवं जिले अतिवृष्टि वाले क्षेत्रों, बनास नदी पर आने वाली रपटों, झरनों, बांधों व पिकनिक स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर सतर्क निगरानी रखने के निर्देश भी पुलिस प्रशासन को दिए। वर्षा ऋतु के दौरान मौसमी बीमारियों को दृष्टिगत रखते हुए विशेष रणनीति बनाने, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा यूडीआईडी कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनिल कुमार जैमिनी को दिए। साथ ही वर्षा काल में अधिकाधिक पौधारोपण करने की अपील भी की। डॉ. सोनी ने पीएचईडी विभाग को जिले में शुद्ध पेयजल व्यवस्था सुचारु रखने तथा जल जीवन मिशन के अंतर्गत लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। विद्युत विभाग को एसटीपी, एमआरएफ प्लांट्स के लंबित कनेक्शन जोड़ने, बकाया कृषि व घरेलू कनेक्शनों के निस्तारण तथा समुचित विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश दिए। पंचायती राज विभाग को मनरेगा एवं सांसद/विधायक निधि से संचालित कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने, तथा आंगनबाडी केन्द्रों पर पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के निर्देश :- बैठक में संभागीय आयुक्त डॉ. टीना सोनी द्वारा राज्य सरकार की प्रमुख कल्याणकारी एवं विकासपरक योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, पंच गौरव, लाडो प्रोत्साहन योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएम विश्वकर्मा, पीएम स्वनिधि, पीएम कुसुम, एनएफएसए, अटलज्ञान केन्द्र, मिशन हरियालो राजस्थान, आरएसएलडीसी सहित अन्य योजनाओं की वर्तमान प्रगति की बिंदुवार समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिला कलक्टर काना राम ने आश्वस्त किया कि बैठक में दिए गए सभी निर्देशों की शत-प्रतिशत पालना कराई जाएगी।

दो बीघा भूमि दान देकर पेश की मानवता की मिसाल

भुसावर भरतपुर (निस)। भुसावर के गांव बिजवारी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण हेतु ग्राम बिजवारी निवासी स्वर्गीय गोरधन सिंह की पत्नी गायत्री देवी व उनके सुपुत्र सतवीर सिंह, अजीत सिंह, प्रवीण सिंह द्वारा 2 बीघा जमीन दान दी गई।

इस नेक कार्य हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिजवारी के समस्त कर्मचारियों द्वारा उनके घर पर उपस्थित होकर उनका स्वागत किया गया स्वागतकर्ताओं में डॉ किरन मीना, मुकेश शर्मा (सीनियर नर्सिंग ऑफिसर), हरिकिशन सैनी (नर्सिंग ऑफिसर), विजेन्द्र मीना(नर्सिंग ऑफिसर), मनीष पाराशर, नरेन्द्र सिंह (फार्मासिस्ट) मनोज कासौटिया (कंप्यूटर ऑपरेटर), पूनम (एएनएम), नीरज (एएनएम), ममता कुमारी (एएनएम), मुरारी लाल इस कार्य मे विशेष सहयोगकर्ता सुनील पाण्डेय (सीनियर लैब टेक्नीशियन) मौजूद रहे ।

लॉयन्स क्लब, इन्टरनेशनल की रीजनल मीट का आयोजन

भरतपुर (निस) लॉयन्स क्लब इन्टरनेशनल के डिस्ट्रिक 3233 ई-1 के रीजन 8 की रीजनल मीट का आयोजन रीजनल चेयरमैन लॉयन विनोद गर्ग की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष लायन विनोद गर्ग, रीजन फर्स्ट लेडी एमजेएफ नीता गर्ग एवं अतिथियों के रुप में रीजन एडवाईजर लॉयन ओमप्रकाश गुप्ता, रीजन एडमिनिस्ट्रेटर लॉयन महेन्द्र गोठी, जोन चेयरपर्सन जोन 1 एमजेएफ लॉयन पंकज वंसल, जोन 2 चेयरपर्सन लॉयन रेनूदीप गौर, जोन 3 चेयरपर्सन लॉयन मंजू गुप्ता, रीजन सेकेट्री लॉयन जितेन्द्र अठावाल एवं रीजन पी.आर.ओ लॉयन डॉ0 रजत आर्य रहे।

रीजन पीआरओ लॉयन डॉ0 रजत आर्य नें वताया कि इस रीजनल मीट का उद्देश्य रीजन में शामिल सभी नौ क्लवों के द्वारा साल भर किये जानें वाले कार्यक्रमों की रुपरेखा तैयार करनें, एवं सभी को रीजन के सामाजिक कार्यो के विजन से अवगत कराना था। कार्यक्रम का शुभारम्भ सभी अतिथियों द्वारा दीप प्रज्जवन से किया गया, अध्यक्ष द्वारा सभा प्रारम्भ की घोषणा के साथ एमजेएफ लॉयन नीता गर्ग द्वारा ध्वज वंदना का वाचन किया, सभी के द्वारा विश्व शांति के लिये मौन एवं राष्ट्रगान किया गया। अतिथियों के स्वागत के पश्चात रीजन सचिव लॉयन जितेन्द्र अठावाल द्वारा सचिविय प्रतिवेदन का वाचन किया गया।

रीजन अध्यक्ष 2025-26 द्वारा डिस्ट्रिक कार्यकारिणी में शामिल सभी सदस्यों का एवं रीजनल कार्यकारिणी को मंच पर वुलाकर परिचय कराया गया एवं सभी को उनके पद वताते हुये माला एवं दुपट्टे से स्वागत कराया गया। रीजन में शामिल भरतपुर एवं हिन्डौन के नौ क्लवों के अध्यक्ष, सचिव एंव कोषाध्यक्षों का भी परिचय करा कर उनका स्वागत किया गया, एवं सभी क्लवों के अध्यक्षों द्वारा किये गये कार्य एवं वर्ष पर्यन्त किये जानें वाले कार्यक्रमों से सदन को अवगत कराया गया । रीजन के तीनों जोनचेरयपर्सनों नें अपनें उद्बोधनों में अपनें जोन में आनें वाले क्लबों के समक्ष वर्ष 2025-26 के किये जानें वाले सेवा कार्यो का विजन रखा। कार्यक्रम के अध्यक्ष रीजन चेयरपर्सन लॉयन विनोद गर्ग नें अपनें उद्बोधन में साल भर किये जानें वाले कार्यक्रमों की रुपरेखा प्रस्तुत की , रीजन के विजन से सभी को अवगत कराया एवं समाज सेवा के कार्यो में वढचढ कर हिस्सा लेनें की वात कही , रीजन के सभी क्लवों के साथ लॉयन्स ऑफ भरतपुर द्वारा सामूहिक सेवा कार्य करनें पर जोर दिया जिससे सभी क्लब मिलकर रीजन 8 को प्रांत एवं जिले में प्रथम पायदान पर रख सके। सचिव के द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया एवं अध्यक्ष द्वारा सभा समाप्ति की घोषणा कर सभी को भोजन के लिये आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में पीएमजेएफ लॉयन रामकुमार गुप्ता, लॉयन विनोद सिंघल, एमजेएफ लॉयन प्रवीण फौजदार, पीएमजेएफ लॉयन प्रेमपाल सिंह, एमजेएफ लॉयन मोहन माहेश्वरी लॉयन डॉ0 अशोक गुप्ता , लॉयन ओ.पी. मंगल, लॉयन श्रीनाथ शर्मा एडवोकेट, लॉयन जे.पी. अठावाल, लॉयन हरीशंकर गोयल, लॉयन कृष्ण मुरारी अठावाल, एमजेएफ लॉयन आर.पी शर्मा , लॉयन मनोज झालानी , लॉयन भारत अठावाल, लॉयन धवल व्यास, लॉयन सत्यदेव आर्य, लॉयन जी.सी. गोयल, लॉयन सतीश गुप्ता, लॉयन श्यामसुंदर गुप्ता, लॉयन राकेश मित्तल, लॉयन लक्ष्मण पाठक, लॉयन योगेश अठावाल, लॉयन मधु गोयल, लॉयन शंकर गुप्ता, लॉयन राजेन्द्र सिंघल, लॉयन राकेश वंसल, लॉयन सतीश मित्तल, लॉयन प्रहलाद गुप्ता, लॉयन हरीचरन शर्मा, लॉयन सत्यव्रत आर्य, लॉयन अशोक ताम्बी, लॉयन राकेश गुप्ता, लॉयन कपिल गुप्ता , आदि मौजूद रहे ।

महिला कार्यकर्ताओं से संवाद कर सदस्यता अभियान को गति दी

भरतपुर (निस)। राजस्थान महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष एवं भरतपुर जिला प्रभारी लीना शर्मा ने भरतपुर में महिला कांग्रेस की निवर्तमान जिलाध्यक्ष रिक्की सिंह के नेतृत्व में महिला कार्यकर्ताओं से संवाद कर महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की

इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा एवं प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह द्वारा महिलाओं के हक में चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रभारी लीना शर्मा द्वारा साझा की गई। महिला सशक्तिकरण के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए, प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह के निर्देशानुसार भरतपुर जिला प्रभार मिलने पर भरतपुर जिले की महिलाओं को सदस्यता अभियान से जुड़ने का आव्हान किया मौके पर ही कई महिलाओं ने महिला कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर संगठन को मजबूती दी।

इस मौके पर परवीन बानो, नजमा खान, लक्ष्मी देवी, चांदबाई, कमलेश, मुमताज, आदि महिला कार्यकर्ता उपस्थित रही।

देवनानी ने अजमेर शहर में जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा कर हालात जाने

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने प्रशासन को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए

अजमेर, (कासं)। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सोमवार को अजमेर शहर में जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि राहत कार्यों में तेजी लाई जाए।

जानकारी के अनुसार अजमेर में हुई भारी बरसात के बाद हुए जलभराव क्षेत्रों का एक बार फिर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जिला कलेक्टर लोकबंधु सहित अफसरों के साथ दौरा कर हालात जाने। यहां मेडिकल कॉलेज सहित अन्य क्षेत्र में भरे पानी को निकालने के लिए मड पंम्प की संख्या बढ़ाने व आनासागर से हो रही पानी निकासी के दौरान बाधित हो रहे मार्ग की पुलिया की ऊंचाई बढ़ाने के निर्देश भी दिए। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी पहले जेएलएन मेडिकल कॉलेज पहुंचे और यहां भरे पानी को निकालने के लिए मड पम्प बढ़ाने के निर्देश दिए। देवनानी ने यहां पर मेडिकल कॉलेज में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जर्जर सीढ़ियों को हटाया जाए। इसके बाद सूचना केन्द्र चौराहे के पास आगरा गेट की तरफ आनासागर पानी निकासी के कारण रोके गए मार्ग का अवलोकन किया और निर्देश दिए कि केसरबाग चोकी के पास पुलिया व पहचान शोरूम की पुलिया को ऊंचा किया जाए। इस दौरान नगर निगम आयुक्त देशलदान, अतिरिक्त जिला कलेक्टर गजेन्द्र सिंह राठौड़, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉ. अनिल सामरिया, अधीक्षक डॉ. अरविंद खरे सहित अन्य अफसर भी मौजूद रहे।

वासुदेव देवनानी ने अजमेर शहर में जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया।

- मेडिकल कॉलेज सहित अन्य क्षेत्र में भरे पानी को निकालने के लिए मड पंम्प की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए
- देवनानी ने सूचना केन्द्र चौराहे के पास आगरा गेट की तरफ आनासागर पानी निकासी के कारण रोके गए मार्ग का अवलोकन किया

फैक्टरी में सुविधाओं के अभाव में श्रमिक की मौत

भीलवाड़ा, (निसं)। फैक्टरी में सुविधाओं के अभाव में श्रमिक की मौत हो गई। हादसे को लेकर आक्रोशित भीड़ ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया। परिजन मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।

- हादसे के बाद मांगों को लेकर आक्रोशित भीड़ का थाने के बाहर प्रदर्शन किया

जानकारी के अनुसार शहर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र स्थित रीको एरिया में सर्वोदय फैक्टरी में कार्यरत एक श्रमिक दिलीप (48) पिता बिंदेश्वरी सिंह बिलिया खुर्द निवासी मूलत: बिहार का रहना वाला है, जो कि फैक्टरी में काम रहा था। 16 जून को दिलीप की काम के दौरान ही अत्यधिक गर्मी और वातानुकूलन की व्यवस्था नहीं होने के चलते बीपी बढ़ गई और वह बेहोश होकर गिर गया। तत्काल साथी श्रमिकों ने उसे शहर के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया, जहां ब्रेन हेमरेज होने का पता चला। 20 जुलाई को उपचार के दौरान दिलीप की मौत हो जाने के बाद आक्रोशित साथी श्रमिकों और परिजनों ने पहले फैक्टरी उसके बाद प्रताप नगर थाने के बाहर और अब एमजी मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिजन उचित मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।

बुजुर्ग की सड़क हादसे में मौत

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के मांडलगढ़ थाना क्षेत्र में खेत से घर लौट रहे बुजुर्ग की बाइक की टक्कर से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, पुरानी आबादी मांडलगढ़ निवासी कन्हैयालाल (70) पुत्र नारायण तेली जोकि खेत पर फसल में दवा छिड़कने गया था। वहां से लौटने के दौरान कन्हैयालाल को एक बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्हें पहले मांडलगढ़ व बाद में एमजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया।

ERCP Eastern Rajasthan Canal Project Corporation Limited
Sinchai Bhawan, JLN Marg, Jaipur 302017 Tel: 0141-2709667 Email: ceercpc@gmail.com
No. :- 2342 Date :- 17/07/2025
NIB No. - ERCPCL/22/2025-26
Managing Director, ERCPCL invites bid for " obtaining wildlife clearance from Ministry of Environment, Forest & Climate change (MOEF&CC) for the construction of Brahmani barrage" from interested bidders up to 28.07.2025 (06.00 PM). Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal **(https://sppp.rajasthan.gov.in/sppp/ and http://eproc.rajasthan.gov.in)** of the state. The approximate value of the procurement is Rs 13.40 Lacs.
NIB Code : ERP2526A0026, UBN No: ERP2526SLOB00027
Raj.Samwad/C/25/6506 MD cum Chief Engineer

Rajasthan Urban Drinking Water Sewerage and Infrastructu Corporation Ltd. (RUDSICO)
(A Government of Rajasthan Undertaking)
Near Police Headquarter, Behind Nehru Place, Lal Kothi, Tonk Road, Jaipur
Ph.-0141 – 2742240, 2742538, 2742263 Fax No. 141 – 2740771
E-mail: ruifdco@gmail.com CIN : U74999RJ2004SGC019961
संख्याः रूडसिको/स्टोर/2025–26/5451 दिनांकः 16.07.2025
बोली आमंत्रण सूचना/2024–25
रूडसिको के जयपुर स्थित कार्यालय में कम्प्यूटर ऑपरेटर (मशीन रहित) के लिए निविदा राशि रू. 13.20 लाख की आमंत्रित की गई है। निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण एवं निविदा प्रपत्र https://sppp.rajasthan.gov.in व eproc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
NIB No. - RDP2526A0015
UBN No. - RDP2526SLOB00031
राज.संवाद/सी/25/6487 महाप्रबन्धक (वित्त)

जवाई बांध का गेज 31.30 फीट पहुंचा

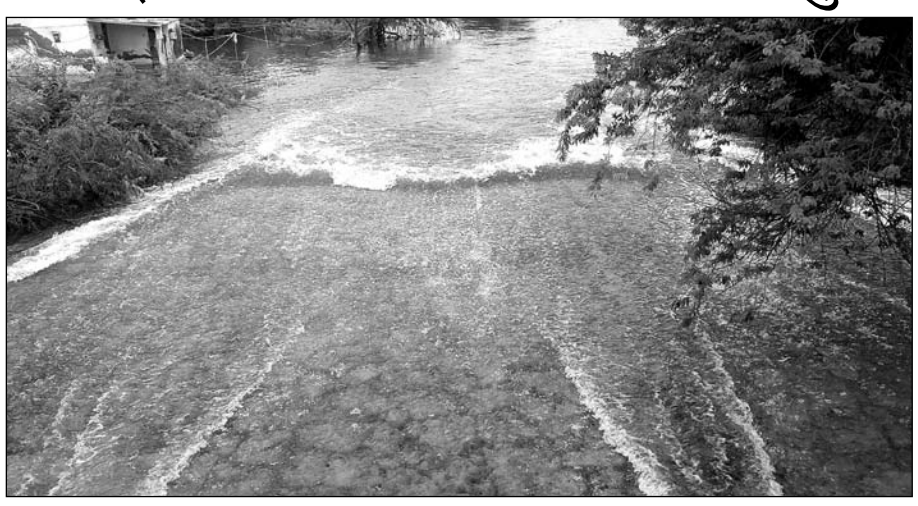

पाली में सोमवार को भी कई जगह पर पानी भरा हुआ है।

पाली, (निसं)। पहले सोमवार को झमाझम दूसरे सोमवार को जिले में कहीं-कहीं बारिश हुई। हालांकि मानसून कमजोर पड़ गया है, लेकिन अभी तक नदियां चल रही है, जिसके कारण पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जवाई बांध का गेज सोमवार को 31.30 फीट पहुंच गया। बांध की भराव क्षमता 61.30 फीट है।

वहीं पाली के निकट हेमावास बांध 26 फीट तक पहुंच गया है, 28 फीट होते ही बांध ओवरफ्लो हो जाएगा। लाखोटिया तालाब की चादर पिछले 5-6 दिन से लगातार चलने से यहां की निचली बस्ती आशापुरा नगर, रामदेव रोड, विकास नगर सहित बस्तियों में अभी भी दो फीट पानी भरा हुआ है। लोग पानी में से होकर गुजर रहे हैं। मौसम विभाग अनुसार आगामी 27- 28 जुलाई को फिर से मानसून सक्रिय होगा।

जमीन विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई को गोली मारी, मौत

भरतपुर, (निसं)। भरतपुर के लखनपुर थाना क्षेत्र के गांव पिंगौरा में जमीन विवाद को लेकर एक शर्मसार करने देने वाली घटना सामने आई है, जहां बड़े भाई ने छोटे भाई को गोली मार दी। घायल भाई को आरबीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है और आगे की जांच में जुट गई है।

- बड़ा भाई विजेंद्र राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल से रिटायर्ड है, छोटा भाई किसानी का काम करता है
- यह विवाद जमीन को लेकर था, जबकि हिस्से की जमीन छोटे भाई ने दे रखी थी, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ा भाई दुश्मनी रखता था
- जब बड़ा भाई भागने लगा तो उसे दौलत राम ने पकड़ लिया, लेकिन हाथ छुड़ाकर भाग गया

मृतक के बड़े भाई राजेंद्र उर्फ रज्जो ने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर दोनों भाइयों के बीच में विवाद था। बड़ा भाई विजेंद्र जो राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल से रिटायर्ड है, छोटा भाई दौलत किसानी का काम करता है। देर रात साढ़े 8.30 बजे में और दौलतराम घर पर थे। उसी दौरान बड़ा भाई विजेंद्र घर पर आया और उसने दौलतराम पर देसी कट्टे से फायर कर दिया। गोली सीने में लगी। जब बड़ा भाई आरोपी विजेंद्र भागने लगा तो उसे दौलत राम ने पकड़ लिया लेकिन फिर वह हाथ छुड़ाकर भाग गया। यह विवाद जमीन को लेकर था, जबकि उसके हिस्से की जमीन दौलत राम ने दे रखी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वह दुश्मनी रखता था। फिलहाल कोई बातचीत नहीं थी, कोई विवाद नहीं था, लेकिन उसने घर आते ही भाई को सीधे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया।

लखनपुर थाने के एएसआई रामसहाय ने बताया कि देर शाम को सूचना मिली थी कि एक भाई ने जमीनी विवाद के चलते दूसरे को गोली मार कर हत्या कर दी है। घटनास्थल पर पहुंचे उसके बाद आरबीएम हॉस्पिटल पहुंचे हैं, जहां मृतक का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मामला दर्ज हो चुका है, आगे करवाई की जा रही है।

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
PWD DIVISION AMET (RAJSAMAND)
File No. 443 Date: 10.07.2025
Notice Inviting Bid
Bids for Nit No 10/2025-26, (Road works) 1 Nos. are invited from interested bidders upto Date 25.07.2025, 06.00 P.M. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.raj.nic.in) of the state. and departmental website. The is Rs. 172.66 Lacs. approximate value of the procurement
NIB No. PWD2526A1883
UBN No. 1. PWD2526WSOB06750
DIPR/C/9913/2025 EXECUTIVE ENGINEER PWD DIVISION AMET

कार्यालय उप वन संरक्षक, बीकानेर
ई-मेल-dfobkn@gmail.com & dcf.bknr.forest@rajasthan.gov.in
पब्लिकपार्क, बीकानेर फोन-0151-2544951
क्रमांक-एफ()भण्डार/उवसंवी./2025-26/4278 दिनांक-14.07.2025
Notice Inviting Bid No. 09/2025-26
Bids for Fenching Work (with Material and Labour) along with NH-II Bikaner-Falodi Block Range Kolayt, Division Bikaner are invited from interested bidders on 05.00 P.M. Date 06.08.2025. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal http:/sppp.rajasthan.gov.in, http://eproc.rajasthan.gov.in website.The approximate value of the procurement is Rs. 271.60 lakh.
NIB- FOR2526A0782, UBN NO. - FOR2526GLOB00979
Deputy Conservator of Forest Bikaner
DIPR/C/9943/2025

OFFICE OF THE PRINCIPAL
RUHS COLLEGE OF MEDICAL SCIENCES, Sector – 11, Kumbha Marg, Pratap Nagar, Jaipur - 302033, Ph. : 0141-2795624, 634 Email : principalruhscms@ruhsraj.org
No. :- RUHS CMS/Store/2025-26/4481 Date :- 19/07/2025
ई-निविदा सूचना
राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय परिसर में स्थित शैक्षणिक व अशैक्षणिक भवन, शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारी आवास, छात्रावासों, खेल संकुल इत्यादि में साफ–सफाई कार्य (कार्य की प्रकृति के आधार पर सेवाओं के उपापन) हेतु ऑनलाईन निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। (कुल अनुमानित लागत राशि रू. 90.00 लाख) **(UBN : CMS2526SLOB00060)**

1.	Bid Download Start Date/Time	19/07/2025 at 05.00 PM
2.	Bid Submission Start Date/Time	19/07/2025 at 05.00 PM
3.	Bid Submission End Date/Time	28/07/2025 at 05.00 PM
4.	Technical Bid Opening Date/Time	29/07/2025 at 11.00 PM

Details may be seen in the Bidding Document at **https://eproc.rajasthan.gov.in** or **https://sppp.rajasthan.gov.in** or on RUHS CMS Jaipur. Principal,
Raj.Samwad/C/25/6498 RUHS College of Medical Sciences, Jaipur

उदयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान
No. :- F-2(01)Acct/Contract/2025-26/102 - 104 Date : 17/07/2025
ई-निविदा सूचना संख्या : 27/2025-26
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर द्वारा निम्नलिखित कार्यो मय डिफेक्ट लाईबिलिटी अवधि के लिये जो कि निविदा प्रपत्र में अंकित है के लिये उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदको से निर्धारित प्रपत्र में ई–टेण्डरिंग के माध्यम से ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है :–

निविदा कार्यो की कुल लागत	:	रूपये 2943.15 लाख (07 कार्य)
ऑनलाईन निविदा प्रपत्र डाउनलोड/अपलोड करने की अवधि	:	21.07.2025 को प्रातः 10.00 बजे से 11.08.2025 को सांयः 6.00 बजे तक
Online EMD, Tender Fee & Processing Fee जमा कराने की तिथी	:	21.07.2025 को प्रातः 10.00 बजे से 11.08.2025 को सांयः 6.00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा खोलने की तिथी	:	12.08.2025 को प्रातः 11:00 बजे

विस्तृत विवरण वेबसाईट urban.rajasthan.gov.in/uitudaipur, www.eproc.rajasthan.gov.in व www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।
UBN No. : ITU2526WLOB00175 To ITU2526WLOB00181
राज.संवाद/सी/25/6496 अधिशाषी अभियन्ता - तृतीय उदयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
प्रभास्मि शशि सूर्ययोः कार्यालय संभागीय मुख्य अभियंता (भरतपुर संभाग) पावर हाउस के पास, मोतीझील, भरतपुर
(ई-मेल - zcebz@jvvnl.org फोन नं.-05644-236080)
ई-निविदा सूचना
टी.एन.–50 एवं टी.एन.–51 के लिए योग्य निविदादाताओं ऑनलाईन–निविदा दो भागों (तकनीकी–वाणिज्यिक), में श्रम दर पर आमंत्रित किऐ जाते है। सहायक अभियन्ता (एच.टी.एम.), जयपुर डिस्कॉम, हिण्डौन के अन्तर्गत करौली वृत में 33/11 केवी सब–स्टेशन महस्वा का निर्माण मय 33 केवी लाईन व 11 केवी लाईन खीचने एवं भूमिगत केबल का कार्य निगम एआरसी दर पर करने के लिये। सहायक अभियन्ता (एच.टी.एम.), जयपुर डिस्कॉम, करौली के अन्तर्गत करौली वृत में 33/11 केवी सब–स्टेशन खुंडा का निर्माण मय 33 केवी लाईन व 11 केवी लाईन खीचने एवं भूमिगत केबल का कार्य निगम एआरसी दर पर करने के लिये। योग्य निविदादाता सम्पूर्ण निविदा सम्बन्धित दस्तावेज ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल **http://www.eproc.rajasthan.gov.in** पर दिनांक 21.07.2025 से डाउनलोड कर सकते है। निविदाऐं ऑनलाईन ई–पोर्टल पर दिनांक 12.08.2025 (सायं 5:00 बजे) तक ही स्वीकार की जावेगी। निविदा सम्बन्धी जानकारी, कार्य का विवरण इत्यादि जयपुर विद्युत वितरण निगम की वेब साईट **www.energy.rajasthan.gov.in/jvvnl, http://www.sppp.rajasthan.gov.in & http://www.eproc.rajasthan.gov.in** से प्राप्त की जा सकती है।
(TN-50, UBN : VVN2526WSOB00308) (TN-51, UBN : VVN2526WSOB00309)
राज.संवाद/सी/25/6491 जेपी.आर - 3037 (2025) संभागीय मुख्य अभियन्ता (भरतपुर संभाग)
बिजली शिकायतों के लिए टोल फ्री नम्बर 1800 180 6507

गड्ढे में गिरने से मासूम बालिका की मौत

बौंली-बामनवास, (निसं)। क्षेत्र के बाटोदा थाना अंतर्गत सुंदरी गांव में एक दो वर्षीय बालिका खेलते हुए पानी के गड्ढे में गिर गई, इससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। सुंदरी गांव के ग्रामीणों व परिजनों ने बताया कि दो वर्षीय अंशु मीना पुत्री मुनेश घर के बाहर आंगन में खेल रही थी। इसी दौरान खेलते-खेलते वह घर के बाहर स्थित पानी के गड्ढे के पास चली गई एवं डूब गई। बालिका के आंगन में नहीं मिलने पर परिजनों ने उसे तलाश किया तो बालिका घर के बाहर पानी के गड्ढे में डूबती नजर आई। परिजन बालिका को पानी से बाहर निकालकर बरनाला चिकित्सालय ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

विद्यालय में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की मांग, धरना पांचवें दिन भी जारी

राजलदेसर, (निसं)। राजलदेसर तहसील के निकटवर्ती ग्राम आलसर बास में राजकीय विद्यालय में विभिन्न मांगों को लेकर विद्यालय के बच्चों व ग्रामीणों का धरना सोमवार को पांचवें दिन भी जारी रहा। आक्रोशित ग्रामीणों ने विद्यालय के अध्यापकों को अंदर नहीं जाने दिया व मुख्य गेट पर ताला लगा दिया। उन्होंने कहा जब तक मांग पूरी नहीं होगी, तब तक उनका धरना विद्यालय के आगे अनवरत जारी रहेगा एवं ताला नहीं खोला जाएगा।

- राजलदेसर तहसील के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आलसर बास में स्कूल के मुख्य गेट पर ग्रामीणों व बच्चों ने ताला लगाया

ग्रामीणों ने बताया कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश पर 23/03/2022 की अनुपालना में उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया था। वर्तमान में विद्यालय में प्रधानाचार्य-1, अध्यापक 2, शारीरिक शिक्षक 1 के पद स्वीकृत है, जिसमें से प्रधानाचार्य व अध्यापक एल (2) अंग्रेजी का पद रिक्त है। विद्यालय में 2020-21 से क्रमोन्नति के पश्चात आज तक द्वितीय श्रेणीअध्यापक (हिन्दी, अंग्रेजी व सामाजिक विज्ञान), व्याख्याता (भुगोल, हिन्दी साहित्य और राजनीतिक विज्ञान) कनिष्ठ लिपिक तथा कम्प्यूटर शिक्षक आदि के पद स्वीकृत नहीं किए गए हैं, जिससे विद्यालय का नामांकन निरंतर गिर रहा है तथा कक्षा 9,10,11 व 12 माध्यमिक विद्यालय की स्वीकृति होते हुए भी बच्चों को निजी विद्यालय या सरकारी विद्यालय के लिए गांव से पांच किलोमीटर से अधिक दूर जाना पड़ रहा है। इस मौके पर प्रशासक सरपंच भानीराम मेघवाल, रामचंद्र, हरिराम, अनूप सिंह, मोहनराम, जीवनराम, दिनेश, रामदयाल, मोहनलाल, शंकरनाथ, शंकर सुथार, रामचंद्र स्वामी सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

स्कूल के बच्चे व ग्रामीण विद्यालय के आगे टेंट लगाकर पांच दिन से मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं।

बाँसवाड़ा सहकारी उपभोक्ता थोक भण्डार लि., बाँसवाड़ा
उदयपुर मेन रोड केन्द्रीय विद्यालय के पास, बाँसवाड़ा-327001 (राजस्थान)
क्रमांक :- एफ/25-26/347 दिनांक :- 14/07/2025
संशोधित ई-निविदा सूचना वर्ष 2025-26
बांसवाडा सहकारी उपभोक्ता थोक भण्डार लि. बांसवाडा अर्न्तगत Supply Of High Quality Grocery Items हेतु इच्छुक बोलीदाताओं से दिनांक 14.07.2025 को प्रातः 11 बजे तक ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसे अपरिहार्य कारणो से दिनांक 24.07.2025 को प्रातः 11 बजे तक बढाया जाता है, निविदा में वर्णित कार्य से सम्बन्धित विवरण व अन्य शर्ते बेवसाईड **http://eproc.rajasthan.gov.in** एवं **http://sppp.rajasthan.gov.in** पर देखी जा सकती है। उपापन हेतु **NIB Code- CMF2525A0053, UBN No.CMF2526GLOB0076** है।
राज.संवाद/सी/25/6504 महाप्रबंधक

Office Of Superintending Engineer
PHED Circle Jhalawar (Rajasthan)
NOTICE INVITING Bid No. 19/2025-26 Item No. 1 and 2
Bids for Annual Rate Contract for Providing, Laying, Jointing, testing and commissioning of pipe line & allied works at various schemes under jurisdiction of Division Jhalawar and Bhawani Mandi, 18.00 Hours. Other DISTT. JHALAWAR are invited from interested bidders upto 30.07.2025, particulars of the bid may be visited on the www.dipr.rajasthan.gov.in, http://rajwater.gov.in. http://sppp.rajasthan.gov.in and http://eproc.rajasthan.gov.in. Departmentai websites.
NIB No. PHE2526A2259
UBN NO-PHE2526W50B04579, PHE2526WSOB04580
Superintending Engineer
DIPR/C/10015/2025 PHED Circle Jhalawar

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड मालपुरा
क्रमांक-710 दिनांक-14.07.2025
निविदा सूचना संख्या- 12/2025-26 खण्ड मालपुरा
राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से खण्ड मालपुरा में सड़क/भवन निर्माण हेतु उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान एवं राज्य सरकार के अन्य विभागों तथा केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संचार विभाग/रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के "ए" व "एए", "बी", "सी", "डी" श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से कार्यों हेतु ई-टेण्डरिंग के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावेगी। निविदा से संबंधित विवरण वेबसाईट साईट www.dipronline.org व www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।
NIB CODE: PWD2526A1958 (1) PWD2526SLRC07006, (2) PWD2526SLRC07007, (3) PWD2526SLRC07008
अधिशाषी अभियन्ता
DIPR/C/9981/2025 सा.नि.वि. खण्ड मालपुरा

Office Of Superintending Engineer, PHED Circle Jhalawar (Rajasthan)
NOTICE INVITING Bid No. 18/2025-26 Item No. 1-A to 1-C
Bids for Annual Rate contract for Construction & commissioning of 200 mm dia tube wells with submersible pump sets etc. complete work in all types of strata & laying, jointing, testing, commissioning of HDPE pipe line including defect liability period of PANCHAYAT SAMITI AKLERA, MANOHARTHANA, JHALARAPATAN, KHANPUR, BAKANI, BHAWANI MANDI, DAG & PIRAEA of PHED Division Jhalawar/ Bhawani Mandi, District Jhalawar (With Material Complete) are invited from interested bidders upto 28.07.2025 at 18.00 Hours. Other particulars of the bid may be visited on the http://sppp.rajasthan.gov.in and www.dipr.rajasthan.gov.in, http://rajwater.gov.in, http://eproc.rajasthan.gov.in. Departmental websites.
NIB No. PHE 2526A2254
UBN No. PHE2526W50B04559, PHE2526WSOB04560, PHE 2526WSOB04561
Superintending Engineer
DIPR/C/9964/2025 PHED Circle Jhalawar

डूंगा की नांगल की प्रशासक को पद से हटाया

पाटन, (निसं)। पंचायत समिति पाटन के अंतर्गत ग्राम पंचायत डूंगा की नांगल की प्रशासक बिमला देवी को पद से हटा दिया है। यह कार्रवाई उनके कार्यकाल के दौरान सामने आई कई अनियमितताओं और जिला परिषद सीकर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है।

जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ग्राम पंचायत में कराए गए निर्माण कार्यों के लिए अनिवार्य सूचनात्मक बोर्ड नहीं लगाए गए, जबकि इन बोर्डों की लागत का भुगतान पहले ही कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, सरकारी कार्यालयों को भूमि पट्टे जारी करने में भी गंभीर नियम उल्लंघन सामने आया है। नियम संख्या 162 के अंतर्गत पट्टे दिए जाने चाहिए थे, लेकिन उन्हें नियम 158 के तहत जारी किया गया, जो प्रक्रियात्मक त्रुटि मानी गई है। उल्लेखनीय है कि बिमला देवी को 16 जनवरी 2025 को जिला कलेक्टर, सीकर के आदेशानुसार ग्राम पंचायत का प्रशासक नियुक्त किया गया था, लेकिन राज्य सरकार द्वारा 11 फरवरी 2025 को जारी विभागीय आदेश के अनुसार, उन्हें पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। यह आदेश अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव इन्द्रजीत सिंह द्वारा जारी किया गया है। प्रशासन का कहना है कि ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ऐसी कार्रवाई आवश्यक है, ताकि जनहित से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश न रहे।

- कार्रवाई प्रशासक के कार्यकाल के दौरान सामने आई कई अनियमितताओं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई

न्यायिक कर्मी अवकाश पर

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के समस्त न्यायिक कर्मचारी अध्यक्ष, राजस्थान न्यायिक संघ के आदेशानुसार अनिश्चितकालिन सामूहिक अवकाश पर रहे। अध्यक्ष दिल बहादुर सिंह ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालयों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पदस्थापित सामान्य संवर्ग व आशुलिपिक संवर्ग का केडर पुनर्गठन की अधिसूचना के प्रस्ताव उच्च न्यायालय द्वारा सरकार को भिजवाया जा चुका है लेकिन आज तक भी राज्य सरकार द्वारा दो साल बाद भी आदेश पारित नहीं किया गया है।

मंदिर परिसर में अपशिष्ट फेंका

भीलवाड़ा, (निसं)। शहर के उपनगर पुर में देर रात मंदिर परिसर में अपशिष्ट फेंकने को लेकर विवाद हो गया। अज्ञात असामाजिक तत्व ने मंदिर में अपशिष्ट फेंक दिया, जिसके कारण क्षेत्र में माहौल गरमा गया। सूचना पर थाना प्रभारी पुष्पा कसौटियां मौके पर पहुंची और समझाइश के प्रयास किए। बताया जा रहा है कि पुर के माली मोहल्ले में हनुमानजी की प्रतिमा पर अपशिष्ट फेंके जाने के बाद आक्रोश फैल गया और आक्रोशित हिन्दू समाज के लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन किया।

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) बीकानेर
क्रमांक :- राजकाज 16629685 दिनांक :- 17/07/2025
ई-बोली आमंत्रण सूचना 04/2025-26
कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज)बीकानेर द्वारा ई–नाम परियोजना के संचालन के लिए उपापन ठेका पद्धति द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए अनुभवी फर्मो/ठेकेदारों/सदभावी व्यवहारियों से ई–नाम परियोजना हेतु ई–टेण्डरिंग के अन्तर्गत ऑनलाईन बोली आमंत्रण सम्बन्धित विवरण एवं शर्तो को वेबसाइट **http://sppp.rajasthan.gov.in** तथा **www.eproc.rajasthan.gov.in** पर देखा जा सकता है।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित ठेका राशि (लाखों में)	बिड डाउनलोड करने की दिनांक	ऑनलाईन बिड अपलोड की दिनांक	ऑनलाईन बिड खोलने की दिनांक	ई–प्रोसेसिंग शुल्क	बोली प्रतिभूति राशि रू.	निविदा शुल्क
1	ई–नाम परियोजना के समस्त कार्य जॉब बेसिस पर करवाने हेतु	20.00	28.07.2025 दोपहर 03:00 बजे तक	28.07.2025 सायः 05:00 बजे तक	29.07.2025 दोपहरः 12:00 बजे से	1000 रू.	40,000	1180 रू.

बोली की शर्तें:– कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) बीकानेर के मुख्य मण्डी प्रांगण एवं गौण मण्डी प्रागण पूगल रोड़/छतरगढ़ में विभिन्न मदों हेतु रजिस्टर्ड फर्मों से निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्योरमेंट **(eproc.rajasthan.gov.in)** के माध्यम से ऑनलाईन निविदाऐं आमत्रित की जाती है। बोली सम्बन्धित नियम/शर्ते किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में प्राप्त कर सकतें है। बोली दस्तावेजों को राज्य उपापन पोर्टल **http://sppp.rajasthan.gov.in UBN No.- DAM2526SLOB00514** पर भी देखा जा सकता है। तकनीकी बोली दस्तावेज के साथ बोली प्रपत्र शुल्क, प्रतिभूति राशि का डी.डी. एव ई–टेण्डरिंग के लिए ई प्रोसेसिंग शुल्क का चालान बोली जमा करने की निर्धारित दिनांक व समय तक कार्यालय में जमा करवाया जाना अनिवार्य है एवं देर से प्राप्त होने वाले दस्तावेजों/शुल्क को स्वीकार नहीं किया जावेगा। बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रतिभूति राशि के अभाव में ई–निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा।
सचिव
राज.संवाद/सी/25/6503 कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) बीकानेर

जयपुर को वैश्विक मान्यता मिलने पर उपमुख्यमंत्री ने जताई प्रसन्नता

जनसुनवाई में आमजन को तुरंत राहत

जयपुर। राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज सिविल लाइंस स्थित अपने कार्यालय पर जनसुनवाई की, जिसमें प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याएं रखीं। अतिक्रमण, पुलिस से संबंधित मामले और स्थानीय विकास से जुड़ी अनेक समस्याएं प्रमुख रहीं। उपमुख्यमंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों से संवाद कर कई मामलों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया।

उन्होंने कहा, ''हम हर सोमवार और मंगलवार को जनसुनवाई कर रहे हैं ताकि आमजन की समस्याओं का तुरंत समाधान हो सके। डबल इंजन की सरकार पूरी जवाबदेही के साथ कार्य कर रही है, जिससे हर नागरिक को राहत मिले।''

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने जयपुर को 2025 में विश्व के शीर्ष 5 पर्यटन शहरों में स्थान मिलने पर हर्ष और संतोष व्यक्त किया, और इसे राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के लिए एक उपलब्धि बताया।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सिविल लाइंस स्थित अपने कार्यालय पर जनसुनवाई की।

- **उपमुख्यमंत्री ने जयपुर को 2025 में विश्व के शीर्ष 5 पर्यटन शहरों में स्थान मिलने पर हर्ष और संतोष व्यक्त किया, और इसे राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के लिए एक उपलब्धि बताया**

उन्होंने कहा, यह सफलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच, डबल इंजन सरकार की नीतियों और राजस्थान सरकार के सतत प्रयासों का परिणाम है। इसमें आमजन की सहभागिता भी उतनी ही महत्वपूर्ण रही है।

उपमुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा पर्यटन अवसंरचना, सांस्कृतिक संरक्षण और आधुनिक सुविधाओं के विकास के लिए चल रही योजनाओं से राजस्थान को अंतरराष्ट्रीय मंच पर नई पहचान मिली है।

उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, यह मान्यता उन सभी लोगों की मेहनत का प्रतिफल है, जो राजस्थान की अतिथि परंपरा, सांस्कृतिक धरोहर और सौंदर्य को दुनिया के समक्ष प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमें पर्यटन स्थलों की स्वच्छता और सौंदर्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

'वक्फ बोर्डों की संपत्ति का डेटा संग्रहण और प्रबंधन के लिए शुरू हुआ उम्मीद पोर्टल'

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक फैसले के बाद वक्फ बोर्डों की संपत्ति का डेटा संग्रहण और प्रबंधन के लिए 6 जून को उम्मीद केंद्रीय पोर्टल शुरू किया गया है। पोर्टल शुरू करने के साथ ही देशभर में राज्यों द्वारा वक्फ संपत्तियों का डेटा अपडेट करना भी शुरू कर दिया। यह पोर्टल वक़्फ़ संपत्तियों के बेहतर, पारदर्शी, सक्षम और सुविधाजनक प्रबंधन में क्रांतिकारी और ऐतिहासिक कदम साबित होगा। यह जानकारी राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के सवाल के जवाब में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने सदन में दी।

राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि एकीकृत वक्फ प्रबंधन,दक्षता, सशक्तिकरण और विकास अधिनियम के तहत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने उम्मीद केंद्रीय पोर्टल-2025 को शुरू किया। पोर्टल शुरू करने के साथ ही महज डेढ़ माह में राज्यों ने इस पर डेटा अपडेट करना शुरू कर दिया। इस पोर्टल पर आंध्र प्रदेश, दिल्ली,राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने डेटा अपडेट करना शुरू दिया। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल के उपयोग से वक़्फ़ संपत्ति का गुपचुप तरीके से दुरुपयोग रुकेगा। पहले जानकारी के अभाव में मुट्ठी भर लोगों के अलावा किसी को पता ही नहीं होता था कि कौन-कौन सी संपत्ति वक्फ की है। अब सभी को सब पता रहेगा। मंत्रालय पोर्टल शुरू करने के साथ-साथ इसका फॉलोअप भी करेगा। सेंट्रल वक़्फ़ काउंसिल, राज्यों के वक्फ बोर्ड और मंत्रालय की तकनीकी टीम ने इस पोर्टल को समावेशी बनाने में कड़ी मेहनत की है।

मदन राठौड़ ने बताया कि उम्मीद पोर्टल और डाटाबेस, रिकॉर्ड पर आने वाली प्रत्येक वक्फ संपत्ति के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या को स्वचालित रूप से उत्पन्न करेगा। इसका उपयोग भविष्य के सभी संदर्भों और संपत्तियों की ट्रैकिंग व निगरानी के लिए किया जाएगा। अधिसूचित नियमों के अनुसार, मुतवल्ली अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल का उपयोग करके पोर्टल और डाटाबेस पर इन्हें नामांकित करेंगे।

- **राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र सहित राज्यों ने संपत्तियों का डेटा अपडेट करना किया शुरू : राज्यसभा सांसद मदन राठौड़**

नव-निर्वाचित जिलाध्यक्ष का स्वागत

जयपुर। बिरला ऑडिटोरियम परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में ब्यावर जिले के नव - निर्वाचित राजस्थान नर्सेज एसोसियेशन संगठन के जिलाध्यक्ष जेठाराम का प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा माला व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में प्यारेलाल चौधरी प्रदेश अध्यक्ष ,रमेश सैनी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष,प्रदेश महिला मंत्री मालती शर्मा,प्रदेश महामंत्री जेपी कसवा एवं प्रदेश प्रवक्ता सुनील शर्मा आदि ने जिलाध्यक्ष जेठाराम , पदाधिकारी ओमप्रकाश, प्रेम सहित अन्य सदस्यों का जोरदार स्वागत अभिनन्दन किया।

जेठाराम ने संकल्प लिया कि नर्सेज संगठन हेतू जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है उसे पूर्ण- निष्ठा से निभाएंगे और शीघ्र ही ब्यावर जिला कार्यकारिणी का गठन करेंगे।

'यू.पी.आई. धोखाधड़ी से सावधान'

जयपुर । डिजिटल लेनदेन के बढ़ते दायरे के साथ-साथ साइबर अपराधी भी नए-नए तरीके अपना रहे हैं। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने आमजन को एक नए प्रकार की यूपीआई आधारित साइबर धोखाधड़ी के प्रति आगाह किया है। इस धोखाधड़ी में अपराधी आपके खाते में छोटी राशि भेजकर आपको फंसाते हैं और एक फर्जी लिंक के जरिए आपके मोबाइल का नियंत्रण हासिल कर लेते हैं। एसपी साइबर क्राइम शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि साइबर अपराधी एक संदिग्ध नंबर से आपके यूपीआई खाते में बहुत कम राशि भेजते हैं, जैसे 1 रुपये या 10 रुपये। इसके तुरंत बाद आपको एक एसएमएस प्राप्त होता है, जिसमें बताया जाता है कि आपके यूपीआई खाते में धनराशि जमा हो गई है। इस एसएमएस में यूपीआई बैलेंस चेक करने के लिए एक लिंक भी दिया होता है। धोखेबाज जानते हैं कि लोग अपने खाते में पैसे आने पर उत्सुक हो जाते हैं।

सामूहिक शिवलिंग पूजन में हो रहा आस्था से खिलवाड़

जयपुर। श्रावण मास के शुभ अवसर पर जहां एक ओर शिवालयों में हर-हर महादेव और बोल बम के उद्घोष गूंज रहे हैं, श्रद्धालु गहरी भक्ति से भोलेनाथ का जलाभिषेक और पूजन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ज्यादातर स्थानों पर सामूहिक पार्थिव शिवलिंग अभिषेक आयोजनों के नाम पर आस्था और धार्मिक मर्यादाओं का खुला उल्लंघन हो रहा है। शास्त्रों में पार्थिव शिवलिंग अभिषेक के लिए नदियों, सरोवरों के तट, मंदिर प्रांगण या पवित्र वृक्षों की छाया को ही उपयुक्त स्थान माना गया है। लेकिन आज ये आयोजन एसी होटल, रिसॉर्ट और सामुदायिक भवनों में धड़ल्ले से हो रहे हैं। इन स्थानों पर सुविधाएं सहज उपलब्ध हो जाती है। हाल ही में मुरलीपुरा स्थित एक समाज भवन में रविवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं से प्रति जोड़े 2500 की दक्षिणा लेकर अभिषेक कराया गया, जिसमें भोजन जैसी सुविधाएं भी जोड़ी गईं। इस आयोजन में हवामहल विधायक बालमुकुंदाचार्य भी उपस्थित रहे।

- **नदी में करने थे पार्थिव शिवलिंग विसर्जित, कचरे के कट्टे में डाल दिए**

लेकिन कार्यक्रम के बाद जो दृश्य सामने आया, उसने आस्था को शर्मसार कर दिया। सोमवार दोपहर तक पूजन सामग्री जहां-तहां बिखरी रही। पार्थिव शिवलिंग प्लास्टिक के कट्टे में कचरे के साथ पड़े मिले। कई पार्थिव शिवलिंग खुले में इधर-उधर फैले हुए थे। न तो विधिवत विसर्जन हुआ, न ही किसी प्रकार की धार्मिक मर्यादा का पालन किया गया। रोली, मोली, चावल, पुष्प सहित पूजन सामग्री पूरे फर्श पर बिखरी हुई थी।

इसके अलावा मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग को गलने से बचाने के लिए उन पर चांदी की वर्क चढ़ाई गई। जानकारों के अनुसार चांदी की वर्क गाय की खाल में कूट-कूट कर बनाई जाती है, जो धार्मिक दृष्टि से न केवल आपत्तिजनक है बल्कि शिव भक्ति की मूल भावना के खिलाफ है। पार्थिव शिवलिंग के अभिषेक के दौरान ज्यादातर आयोजक चांदी की वर्क के बजाय प्लास्टिक की पतली पन्नी का उपयोग करते हैं।

दक्षिणा के साथ प्रायोजक भी करते हैं सहयोग:- ऐसे आयोजनों में स्वयंसेवी संगठनों और कथित धार्मिक समूहों द्वारा भारी दक्षिणा लेकर धर्म को व्यावसायिक रूप दे दिया गया है। श्रद्धालु भक्ति में रमे रहते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ लोगों द्वारा आस्था को बाजार बना दिया गया है। यजमानों से दक्षिणा के साथ-साथ ये लोग भामाशाहों से भी सहयोग के नाम पर मोटी राशि ले लेते हैं।

शिविर में 240 मरीजों की नेत्र जांच

जयपुर। शेखावाटी अग्रवाल समाज संस्था के तत्वावधान में व संजय एंड ज्योति अग्रवाल फाउंडेशन के सौजन्य से 150 वां निशुल्क लैंस प्रत्यारोपण शिविर विद्याधर नगर, सेक्टर-7 स्थित महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में आयोजित किया गया।240 मरीजों ने आंखों की जांच की गई,साथ ही 182 व्यक्तियों को चश्मे वितरण किए गए। इस मौके पर सुरेश अग्रवाल, अरुण काबरा, राजेंद्र मोदी , अनिल शर्मा , मुकेश बंसल, दिनेश टेकरीवाल, मुकेश मीणा व राजेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।

दक ने विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों को संबोधित किया

जयपुर। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने कहा कि विगत 17 जुलाई को केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित हुआ 'सहकार एवं रोजगार उत्सव' राज्य के सहकारी सेक्टर को मजबूत बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि हमें राज्य में सहकारी सेक्टर को और अधिक मजबूत करने के लिए एकजुट होकर पूरे मनोयोग से प्रयास करने होंगे।

दक सोमवार को अपेक्स बैंक सभागार में 'सहकार एवं रोजगार उत्सव' के सफल आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभी को धन्यवाद देते हुए कहा कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी ने अपना श्रेष्ठ योगदान दिया। सभी लोगों ने टीम भावना के साथ समन्वय बनाकर कार्य किया, जिसके अच्छे परिणाम आए और कार्यक्रम का सफल आयोजन सुनिश्चित हो सका। आयोजन में 90 प्रतिशत से भी अधिक भागीदारी सहकारी आन्दोलन से जुड़े लोगों की रही और कार्यक्रम के माध्यम से राजस्थान के सहकारी आन्दोलन का पूरे देश में एक अच्छा मैसेज गया। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार सहकारी सेक्टर को सशक्त बनाने के लिए पूरा सहयोग दे रही है और हमें भी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अंतर्गत पुरजोर प्रयास करते हुए 'को-ऑपरेटिव बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड' के ध्येय वाक्य को साकार करना होगा। उन्होंने उम्मीद जताई की केन्द्रीय सहकारिता मंत्री की मंशा के अनुरूप राजस्थान आगामी समय में सहकारिता में देश में सर्वश्रेष्ठ होगा।

शासन सचिव पर्यटन ने दो दिवसीय तीज उत्सव के आयोजन की रूप रेखा पर चर्चा की

जयपुर। प्रमुख शासन सचिव पर्यटन, कला एवं संस्कृति व पुरातत्व राजेश यादव की अध्यक्षता तथा पर्यटन आयुक्त रूकमणि रियाड़ एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति में तीज का उत्सव और अधिक भव्यता से मनाने और तीज माता की शोभायात्रा की व्यवस्थाओं की तैयारी के सम्बन्ध में सोमवार को जयपुर स्थित पर्यटन भवन में बैठक आयोजित की गई।

प्रमुख शासन सचिव पर्यटन राजेश यादव ने कहा कि इस बार 27 एवं 28 जुलाई को जयपुर में इस बार दो दिवसीय तीज उत्सव का आयोजन पहले से और अधिक भव्य और आकर्षक रूप में किया जाएगा।जिसमें राजस्थान की रंग-बिरंगी संस्कृति और परम्पराएं अद्भुत व आकर्षक रूप से प्रदर्शित होंगी। तीज उत्सव में जयपुर के आम नागरिक और देशी विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में सम्मिलित होंगे।

प्रमुख शासन सचिव पर्यटन ने दो दिवसीय तीज उत्सव के सम्पूर्ण आयोजन की रूप रेखा पर चर्चा करते हुए बताया कि तीज माता के शौभायात्रा में इस बार राजस्थान की लोक कलाओं में उत्कृष्ट रूप से पारंगत लगभग 200 लोक-कलाकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन करेंगे।

- **प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव की अधिकारियों की उपस्थिति में तीज माता की शोभायात्रा की व्यवस्थाओं की तैयारी के सम्बन्ध में में बैठक ली**

उन्होंने कहा मेले में महिलाओं के द्वारा तैयार सामान का क्राफ्ट मार्केट लगाया जाएगा। मेले में फूड स्टाल्स् के साथ महिलाओं के लिए झूले, मेहन्दी माण्डणे की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि पॉण्ड्रीक पार्क में लोक कलाकारों द्वारा कला प्रदर्शन किया जाएगा। इसी प्रकार छोटी चौपड पर तीज माता की पूजा की जाएगी एवं कलाकारों द्वारा रोचक प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव ने कहा कि राजस्थान जयपुर के इस अत्यंत लोक प्रिय तीज उत्सव के आयोजन का विभिन्न विभागों की वेबसाईट,पर्यटन विभाग की वेबसाईट और सोशल मीडिया प्लेटेफॉर्म्स पर वृहद प्रचार प्रसार किया जाए। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजन की कवरेज प्रिन्ट मीडिया,इलेक्ट्रोनिक मीडिया के साथ ही सोशल मीडिया इम्फलुएन्सर्स के द्वारा करवाया जाना सुनिश्चित करने के लिए पर्यटन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इस बार तीज उत्सव का लाइव प्रसारण जयपुर शहर में स्थित स्क्रीन्स एवं सर्पूण राजस्थान में डीओआईटी के माध्यम से प्रसारण करवाया जाएगा। प्रमुख शासन सचिव ने शोभायात्रा में लवाजमा हेतु हाथी, ऊंट, घोड़े, बैल, बैण्ड, शहनाई-नगाड़ा, आदि की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने देशी-विदेशी पर्यटकों के बैठने हेतु हिन्द होटल के टेरेस एवं निचे बरामदों में बैठने की व्यवस्था करने, वहां टेण्ट एवं वाटर प्रूफ शामियाना भी लगवाने के लिए पर्यटन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। प्रमुख शासन सचिव पर्यटन राजेश यादव की ओर से बैठक में जयपुर नगर निगम (हैरिटेज) आयुक्त को तीज माता की सवारी मार्ग में आने वाले पेड़ो की छटाई, बिजली के तार एवं अन्य केबल तार जो की सवारी मार्ग में झूल रहे है उन्हें दुरस्त करवाने के निर्देश दिए गए।

पुस्तक रजवाड़ों के जांबाज का लोकार्पण

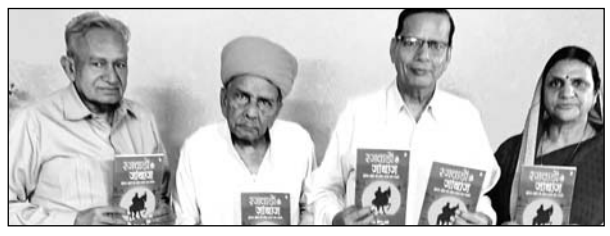

राजेन्द्र मोहन शर्मा की पुस्तक रजवाड़ों के जांबाज का लोकार्पण किया।

जयपुर । राजस्थान की रेत के कण कण में भक्ति का शंखनाद और रक्त के हर अणु में देशभक्ति का नाद सदियों से गुंजायमान है। यहां के बलिदानी नायक नायिकाओं ने अपनी मिट्टी की , अपनी धरती मां की रक्षा के लिए बड़े बड़े सूरमाओं को धूल चटाई है विशेषकर आततायी मुगल शासकों को जिस तरह रजपूताने के सूरवीरों ने खदेड़ा था वह रोमांचकारी था। बड़ी से मुगल बड़ी सेना के पांव भी इस धरती पर कांपते थे। सुप्रसिद्ध वरिष्ठ साहित्यकार प्रदीप सैनी आज जयपुर में स्वरांजली द्वारा आयोजित समारोह में वरिष्ठ लेखक एवं चिन्तक राजेन्द्र मोहन शर्मा की पुस्तक रजवाड़ों के जांबाज का लोकार्पण करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा दिल्ली से प्रकाशित यह पुस्तक आज की युवा पीढ़ी के लिए न केवल प्रेरणादायक है अपितु राष्ट्र के प्रति समर्पण क्या होता है सिखाने वाली है। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमें अपने इतिहास को पुन: विवेचित कर सही तथ्यों को युवा पीढ़ी के सामने लाने की आवश्यकता है और यह धर्म राजेन्द्र मोहन शर्मा ने इस पुस्तक लेखन के माध्यम से बखूबी निभाया है।

इस अवसर पर इतिहास के सुप्रसिद्ध समालोचक डॉ एम.एम. शर्मा ने कहा अतीत में वामपंथी विचारधारा से ग्रसित इतिहासकारों ने जगह जगह मुगल शासकों के गलत तथ्य प्रस्तुत कर देश को अक्षम्य रूप से गुमराह किया है । इसके निवारण हेतु राजेन्द्र मोहन शर्मा ने इस पुस्तक के माध्यम से महत्वपूर्ण कार्य किया है।

न्यायिक कर्मचारियों का आंदोलन जारी

जयपुर । प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में कार्यरत कर्मचारियों का राज्य सरकार की ओर से कैडर पुनर्गठन नहीं करने के विरोध में सोमवार को सामूहिक अवकाश जारी रहा। इसके चलते अदालतों में अधिकतर मामलों में तारीखें दी गई। कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश पर होने के चलते नए मुकदमे भी दायर नहीं हो पा रहे हैं।

जब तक कैडर पुनर्गठन का आदेश उनके हाथ में नहीं आएगा, तब तक उनका सामूहिक अवकाश जारी रहेगा। प्रांतीय अध्यक्ष सुरेन्द्र नारायण जोशी ने बताया कि हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से 25 जुलाई को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक का हवाला देते हुए सामूहिक अवकाश समाप्त करने को कहा गया था, लेकिन अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा। दूसरी ओर दी बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष संदीप लुहाडिया ने राज्य सरकार व हाईकोर्ट प्रशासन से न्यायिक कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने का आग्रह किया है। कर्मचारी संघ के प्रांतीय संरक्षक बद्रीलाल चौधरी ने बताया कि अध्यक्ष सुरेन्द्र नारायण जोशी व पूर्व जिलाध्यक्ष बृजेश शर्मा की भूख हडताल आठवें दिन भी जारी रही।

लाइब्रेरियन भर्ती में शामिल करने के आदेश, मांगा जवाब

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने कट ऑफ से अधिक अंक लाने के बावजूद भी अभ्यर्थी को लाइब्रेरियन भर्ती-2024 की चयन प्रक्रिया से बाहर करने पर शिक्षा सचिव, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश सायर चौधरी की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने 14 फरवरी, 2024 को लाइब्रेरियन ग्रेड द्वितीय के पदों पर भर्ती निकाली थी। याचिकाकर्ता ने ओबीसी वर्ग में भाग लेकर 212 अंक प्राप्त किए, जबकि इस वर्ग की कट ऑफ 179 आई थी। याचिकाकर्ता के एक प्रश्न पत्र में चालीस फीसदी अंक के बजाए 39.34 अंक आने पर उसे चयन से वंचित कर दिया गया। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने 7 फरवरी, 2024 को परिपत्र जारी कर राजस्थान शिक्षा सेवा नियम में संशोधन किया था। संशोधन के तहत लाइब्रेरियन ग्रेड द्वितीय और तृतीय के लिए हर प्रश्न पत्र में न्यूनतम चालीस फीसदी अंक लाने के प्रावधान को हटा दिया गया था। याचिका में कहा गया कि प्रत्येक प्रश्न पत्र में चालीस फीसदी अंक लाने की अनिवार्यता नहीं होने के बावजूद याचिकाकर्ता को चयन से बाहर कर दिया गया, जबकि उसके कट ऑफ से काफी अधिक अंक हैं। ऐसे में उसे चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है।

- **अदालत ने याचिकाकर्ता अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश सायर चौधरी की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए**

सीवेज लाइन डालने से पूर्व करें सुरक्षा और समयबद्धता की प्लानिंग : आवासन मंत्री

जयपुर । अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और सीवेज के काम की प्लानिंग आमजन की ज़रूरतों, सुरक्षा और सुव्यवस्थित नगरीय विकास को ध्यान में रखकर की जाए। यह कहना है नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा का।

सोमवार को डीएलबी मुख्यालय के सभागार में आयोजित हुई रुडसिको की 60 वी बोर्ड बैठक की खर्रा अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में पिछली बोर्ड बैठक के कायो द्वारा केन्द्र एवं राज्य पोषित योजना की समीक्षा की गई तथा योजनाओं को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्वक कार्य करवाने के लिए निर्देश दिये गये।

मंत्री झाब्बर सिंह खर्रा ने कहा की सीवेज का काम शुरू करने से पहले ही उसकी निर्माण अवधि , गुणवत्ता और नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्ययोजना बनाई जाए ताकि किसी प्रकार की कोई जान माल की हानि ना हो। सीवेज के इनलेट और आउटलेट के निर्माण का विशेष ध्यान रखा जाए । सीवरेज ड्रेनेज परियोजना की डी.पी.आर. निर्माण के समय विशेष ध्यान रखें तथा क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कमी न रहे। डी.पी.आर. की शुद्धता एवं उसके क्रियान्वयन के लिए संबंधित तकनीकी अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

झाब्बर सिंह खर्रा ने (बीच में) डीएलबी मुख्यालय पर रुडसिको की बोर्ड बैठक ली ।

इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले संवेदकों को भी नोटिस जारी कर उनपर जुर्माना लगाया जाए ताकि भविष्य में ऐसी कोई समस्या ना आए । उन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर भी अधिकारियों को निर्देशित किया, खर्रा ने कहा की लंबे समय से अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का काम लंबित होना चिंतनीय है । उन्होंने निर्देश दिए की कार्ययोजना तैयार कर जल्द से जल्द आम जन के आवास के सपने को साकार किया जाए ।

इसी के साथ ही इस बैठक में रूडसिको के दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का भी अनुमोदन खर्रा द्वारा किया गया । सुमन शर्मा और सूर्या प्रकाश चौपड़ा को नियमानुसार रुडसिको का स्वतंत्र निदेशक बनाया गया है ।

- **इस बैठक में पिछली बोर्ड बैठक के कायो द्वारा केन्द्र एवं राज्य पोषित योजना की समीक्षा की गई तथा योजनाओं को गुणवत्तापूर्वक कार्य करवाने के लिए निर्देश दिये**

इस बैठक में नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव डॉ देबाशीष पृष्टि ,स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन, पीएचईडी विभाग के मिशन निदेशक रवीन्द्र गोस्वामी, आवासन आयुक्त डॉ रश्मि शर्मा, रुडसिको के कार्यकारी निदेशक हरि मोहन मीणा, डीएलबी निदेशक प्रतीक जुईकर, वित्तीय सलाहकार उम्मेद सिंह, मुख्य अभियंता अरुण व्यास, प्रदीप गर्ग सहित अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित रहे ।

'स्वच्छ सर्वेक्षण में जियो फेंसिंग और मोबाइल ऐप से होगा डेटा संग्रह'

जयपुर। स्वच्छ भारत मिशन फेज-2 के तहत शुरू किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में इस बार जियोफेंसिंग और मोबाइल एप से डेटा संग्रह किया जाएगा। इतना ही नहीं, स्वच्छता मापदंडों पर नागरिकों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए भारत सरकार की ओर से इस बार नागरिक प्रतिक्रिया एप्लिकेशन विकसित की गई है। डेटा संग्रहण साफ्टवेयर में जियो फेंसिंग को शामिल करने के साथ परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग भी की जाएगी। यह जानकारी राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ के सवाल के जवाब में केंद्रीय राज्य जल शक्ति मंत्री वी.सोमण्णा ने सदन में दी।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 में इस बार देशभर के 34 राज्य एवं संघ राज्यों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही देशभर के 761 जिले और 21000 गांवों को शामिल किया गया है। गांवों के स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान सेवा स्तरीय प्रगति, गांवों में स्वच्छता का प्रत्यक्ष अवलोकन, संयंत्रों की कार्यशीलता का प्रत्यक्ष अवलोकन और नागरिक प्रतिक्रिया को शामिल किया गया है। सर्वेक्षण में कुल 1 हजार अंकों में से मूल्यांकन किया जाएगा।

'जयपुर में बाढ़ नियंत्रण एवं आपदा प्रबंधन के लिए हर संभव प्रयास हो सुनिश्चित'

जयपुर। मानसून सीजन में जलभराव एवं बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए जयपुर जिला प्रशासन द्वारा व्यापक एवं योजनाबद्ध तैयारी की गई है। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के नेतृत्व में प्रशासन ने बाढ़ नियंत्रण की दिशा में समय पर कार्यवाही कर संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिला कलक्टर के निर्देश पर सभी विभागों को अलर्ट मोड में रखा गया है । साथ ही, 24 घंटे नियंत्रण एवं निगरानी के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी स्वयं स्थिति की नियमित मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सभी उपखंड अधिकारियों, नगर परिषद, जन स्वास्थ्य, विद्युत, जलदाय, पुलिस, आपदा प्रबंधन सहित अन्य संबंधित विभागों को संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशों की अनुपालना में जिला स्तर पर चौबीसों घंटें कार्यरत कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां आमजन अपनी समस्याएं सीधे रिपोर्ट कर सकते हैं। किसी भी आपात स्थिति, जलभराव, सड़क क्षित, बिजली गड़बड़ी या अन्य समस्या की सूचना जिला आपदा नियंत्रण कक्ष, जयपुर कंट्रोल रूम नंबर 0141-2204475, 0141-2204476 के साथ-साथ टोल फ्री नंबर 1077 पर दी जा सकती है।

- **जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने अधिकारियों को दिये सख्त निर्देश**

इसके अतिरिक्त जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शहर में 9, नगर निगम जयपुर ग्रेटर द्वारा 4, नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा 3 नियंत्रण कक्षों का निरंतर संचालन किया जा रहा है। वहीं, पुलिस विभाग, विद्युत विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, मौसम विभाग, जयपुर मैट्रो, रेलवे, एयरपोर्ट, एसडीआरएफ एवं राज्य स्तरीय ईओसी के साथ साथ तहसील स्तर पर भी प्रशासन द्वारा नियंत्रण कक्षों का प्रभावी संचालन किया जा रहा है।

हर आपदा से निपटने के लिए मुस्तैद है टीम जयपुर जिला प्रशासन

प्रशासन ने निचले इलाकों, जलभराव प्रभावित क्षेत्रों तथा पुराने बाढ़-प्रभावित इलाकों की पहचान कर विशेष निगरानी टीमों का गठन किया है। प्रत्येक टीम को निर्धारित क्षेत्र में जल निकासी व्यवस्था, जनसंपर्क एवं आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

नगर निगम एवं जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से नालों और जल निकासी मार्गों की पूर्व सफाई कराई गई, जिससे बारिश के पानी का तुरंत बहाव सुनिश्चित हो सके। सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ, नगर निगम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीमें तैनात की गई हैं, जो आपदा की स्थिति में तुरंत राहत पहुंचा सकें। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने स्वयं प्रभावित क्षेत्रों का नियमित निरीक्षण कर रहे हैं एवं साथ ही अतिरिक्त जिला कलक्टर सहित जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी भी फील्ड में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं।

सड़कों पर घटिया सड़कें बनाये जाने की शिकायत पर फिर जांच शुरु

सार्वजनिक निर्माण विभाग के दो अधिकारी बोरावड़ पहुंचे और सड़कों की नाप ली

मकराना, (निसं)। प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा सड़कों पर सड़कें नहीं बनाये जाने के निर्देश दिये जाने के बावजूद बोरावड़ में सड़कों पर सड़कें बनाये जाने का क्रम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सड़कों पर सड़कें और वो भी घटिया निर्माण सामग्री के साथ बनाये जाने के मामले में पूर्व में जिला कलेक्टर से की गई शिकायत पर बुधवार को सार्वजनिक निर्माण विभाग के दो अधिकारी बोरावड़ पहुंचे। उनके साथ शिकायतकर्ता राजेन्द्र खर्रा सहित स्थानीय नगरपालिका के जेईएन नरेन्द्र सारस्वत तथा ठेकेदार के प्रतिनिधि जांच के दौरान उपस्थित रहे। जांच अधिकारियों द्वारा सड़कों के नाप लिये जाने पर बोथरा बास, हवाई अड्डा से सरावगी मोहल्ला होते हुए अग्रवाल मेडिकल तक, रानाबाई टेंट हाऊस के सामने, गाडिया लोहारों की बस्ती आदि में अनेक स्थानों पर सड़कों की मोटाई दो से तीन इंच तक ही पायी गई। अनेक स्थानों पर सड़कें बनने के साथ ही टूट जाने की स्थिति भी देखी गई। इससे पहले इस मामले में एसडीएम मकराना के आदेश पर नगर परिषद मकराना की एईएन ने भी सड़कों की जांच की थी, मगर उनके

सड़कों की जांच के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग के दो अधिकारी बोरावड़ पहुंचे। इस दौरान शिकायतकर्ता राजेन्द्र खर्रा सहित पालिका के जेईएन नरेन्द्र सारस्वत उपस्थित रहे।

द्वारा की गई लीपापोती के बाद एक ही बरसात में घटिया सामग्री की सड़कें जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है। अब जांच एजेंसी के बदलने के बाद एक बार फिर जनता की नजर निष्पक्ष जांच की ओर है।

मामले के अनुसार बोरावड़ निवासी राजेन्द्र खर्रा सहित रतनाराम, ओमसिंह, चेतन सोनी व अन्य लोगों ने संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त शिकायत जिला कलेक्टर डीडवाना-कुचामन तथा उपखण्ड अधिकारी मकराना अुशंल सिंह को प्रेषित कर ठेकेदार द्वारा बिना पीसीसी किए पुरानी सीसी सड़कों पर ही बिना मापदण्ड एवं घटिया सामग्री से सड़कों के निर्माण के आरोप लगाते हुए ग्यारह सड़कों के निर्माण की थर्ड पार्टी जांच करवाने तथा गुणवत्ता की जांच होने तक सड़कों के निमार्ण कार्य का भुगतान रोके जाने की गुहार की।

उन्होंने शिकायत के माध्यम से जिला कलेक्टर को अवगत कराया कि शहर में सात पुरानी व खराब हो रखी सड़कों को तोड़कर पहले पीसीसी की जाती है, उसके बाद सीसी सड़क का निर्माण किया जाना था, जबकि 25 लाख की लागत से बनने वाली विभिन्न स्थानों की सड़कों को एक ही स्थान पर एक ही वार्ड नंबर 21 में खर्च कर दिया गया जो कि पार्षदों के साथ भेदभाव है, उस सड़क में जो सीमेंट की मात्रा होनी चाहिए, वह नहीं डाली गई तथा 2 इंच पीसीसी करके ऊपर सीसी का वर्क कर दिया गया। शिकायत में बताया गया है कि बोरावड़ के वार्ड नंबर 20 में 2 इंच पीसीसी डालकर सीसी घटिया सामग्री कम मात्रा में सीमेंट डालकर सड़क बना दी गई, इसी प्रकार बोथरा बास, मुथा बास में पीसीसी भी नहीं करते हुए सीधा सीसी डालकर कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि अग्रवाल मेडिकल स्टोर से हवाई अड्डा पॉइंट तक बनने वाली सड़क को बिना तोड़फोड़ करके बिना पीसीसी किये 4 इंच सीसी डालकर लीपापोती की गई। उन्होंने पालिका प्रशासन व ठेकेदार पर फंड का जमकर दुरुपयोग किये जाने का आरोप लगाते हुए बताया कि बोरावड़ में लम्बे समय के इंतजार के बाद सड़कों के निर्माण में भारी अनियमितताएं बरतने से स्थानीय जनता में रोष व्याप्त है।

सूने मकान में हुई चोरी का पर्दाफाश, चार गिरफ्तार

पावटा, (निसं)। विराटनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सूने घर से चोरी करने वाले चार चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरों के पास से चोरी किए गए कूलर, गैस सिलेंडर, कूलर मोटर बरामद किए हैं। यह सफलता थाना प्रभारी सोहनलाल के नेतृत्व में

- पुलिस ने चोरों के पास से चोरी किए गए कूलर, गैस सिलेंडर, कूलर मोटर बरामद की

मिली है।

राजन दुष्यंत उप महानिरीक्षक पुलिस सह जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वर्तमान में संपत्ति संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक कोटपूतली वैभव शर्मा के निर्देशन एवं वृत्ताधिकारी वृत्त विराटनगर शिप्रा राजावत के सुपरविजन व विराटनगर थाना प्रभारी विराटनगर सोहनलाल के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए प्रकरण में मुल्जिमों की तलाश की गई। घटना क्षेत्र के आसपास व संभावित स्थानों के सीसीटीवी कैमरे खंगालते हुए पुलिस ने अज्ञात बदमाशों की तलाश की जाकर

पुलिस ने चोरी का माल सहित आरोपियों को गिरफ्तार किया।

कूलर, गैस सिलैंडर, कूलर मोटर चोरी की घटना का पर्दाफाश किया। पुलिस ने अजय हरिजन पुत्र ज्ञानचंद निवासी वार्ड नं. 25 विराटनगर, भूपेंद्र कुमार उर्फ मनोज सैनी पुत्र रामस्वरूप निवासी वार्ड नं. 23 झालरा की ढाणी विराटनगर को गिरफ्तार किया, जिन्होंने चोरी के बाद चोरी का माल बाबूलाल, महेश को बेचना बताया, जिस पर बाबूलाल पुत्र फूलचंद बीजाला की ढाणी विराटनगर, महेश कुमार पुत्र किशोरी लाल निवासी वार्ड नं. 18 किले के पास विराटनगर को गिरफ्तार कर चोरी का खरीदा माल कूलर, गैस सिलैंडर, कूलर मोटर बरामद की। वृत्ताधिकारी वृत्त विराटनगर शिप्रा राजावत ने बताया कि 12 जुलाई को जोगेश कुमार पुत्र प्रभुदयाल अग्रवाल ने मामला दर्ज करवाया था कि रात्रि में अज्ञात चोर मेरे पुस्तैनी ने मकान से कूलर, गैस सिलैंडर, कूलर मोटर चोरी कर ले गए।

ग्राम पंचायत मांकड़ी मे अंतिम यात्रा गहरे पानी से गुजरी, लोगों में रोष

पाटन, (निसं)। जल भराव की समस्या जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी-यह कहावत उस समय साकार हो गई, जब ग्राम पंचायत मांकड़ी की ढाणी साधुवाला निवासी सुरेश सैनी की पत्नी लीलावती की अंतिम यात्रा रेलवे ट्रैक के अधीनस्थ अंडरपास से गुजरी, जिसमें लगभग दो से तीन फीट गहरा पानी भरा हुआ था। अंतिम संस्कार के इस भावुक क्षण में ग्रामीणों को शव यात्रा के साथ पानी में उतरना पड़ा। सैकड़ों लोग इस जलमग्न रास्ते से गुजरते हुए प्रशासनिक अनदेखी के खिलाफ आक्रोशित नजर आए।

स्थानीय युवा हवासिंह मांकड़ी ने बताया कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में तीन अंडरपास हैं, जो वर्षा ऋतु में पूरी तरह जलमग्न हो जाते हैं। इनसे प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की आवाजाही होती है, लेकिन इसके बावजूद शासन-प्रशासन की ओर से कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया। हवासिंह ने बताया कि पंचायत क्षेत्र बीते पांच वर्षों से राजनीतिक उपेक्षा का शिकार रहा है। जनप्रतिनिधि चुनावों के बाद जनता की

सैकड़ों लोग जलमग्न रास्ते से गुजरते हुए प्रशासनिक अनदेखी के खिलाफ आक्रोशित नजर आए।

समस्याओं से मुंह मोड़ लेते हैं और राजनीतिक मेहमाननवाजी में व्यस्त रहते हैं। वर्तमान में पंचायत के सरपंच (जो प्रशासक के रूप में कार्यरत थे)

- अंतिम यात्रा रेलवे ट्रैक के अधीनस्थ अंडरपास से गुजरी, जिसमें लगभग दो से तीन फीट गहरा पानी भरा हुआ था

को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने दिन बीत जाने के बावजूद अब तक किसी नए प्रशासक या प्रतिनिधि को चार्ज नहीं सौंपा गया है।

गांव के लोगों का कहना है कि नालियों की सफाई नहीं होती, अंडरपास की नियमित निकासी व्यवस्था नहीं है और न ही जल निकासी की कोई ठोस योजना बनाई गई है। नतीजतन, बारिश के दिनों में आमजन से लेकर शव यात्राओं तक को जलमग्न रास्तों से गुजरना पड़ता है। हवासिंह मांकड़ी ने शासन और प्रशासन से मांग की है कि ग्राम पंचायत की समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए, अन्यथा क्षेत्र की जनता आंदोलन के लिए बाध्य होगी।

परीक्षा केन्द्र बनवाने व परिवर्तन के लिए 31 तक आवेदन

अजमेर, (कासं)। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा वर्ष 2026 के लिए परीक्षा केन्द्र बनाने अथवा अपने विद्यालय का परीक्षा केन्द्र परिवर्तन कराने के इच्छुक विद्यालयों से 31 जुलाई तक आवेदन पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय के माध्यम से आमंत्रित किए गए है। सचिव कैलाश चन्द्र शर्मा ने बताया कि 10 किलोमीटर से अधिक दूरी पर आवंटित परीक्षा केन्द्र वाले विद्यालय भी निकटतम परीक्षा केन्द्रों का विकल्प देते हुए केन्द्र परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप परीक्षा केन्द्रों पर स्थान उपलब्धता के आधार पर केन्द्र परिवर्तन अथवा नया परीक्षा केन्द्र बनाने पर विचार किया जाएगा। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। सभी जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय प्राप्त आवेदन पत्रों के संबंध में उचित प्रस्ताव तैयार कर मेल करें।

स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ आक्रोश

रतनगढ़, (निसं)। रतनगढ़ कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) और अखिल भारतीय किसान सभा तहसील कमेटी रतनगढ़ ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ आक्रोश रैली निकालकर प्रदर्शन किया। 'राज्य सरकार होश में आओ, स्मार्ट मीटर नहीं चलेगा' जैसे नारे लगाते हुए निकाली गई रैली को कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन दिया। किसान सभा के अध्यक्ष मदनलाल जाखड़, राजलदेसर अध्यक्ष भादर भामू, वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया के नेतृत्व में हुए आंदोलन में पूरे परिक्षेत्र से सैकड़ों की संख्या में किसान शामिल हुए।

संयोजक रामकिशन भामू ने बताया कि किसान मजदूर भवन में हुई सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि पहले से घरों में डिजिटल मीटर लगे हुए हैं, उसमें कोई खराबी नहीं है, उसके बावजूद स्मार्ट मीटर के नाम पर लूट का खेल जारी है। किसान सभा के बिरजू खीचड़, बिशन लाल रूलानिया, भादरसिंह राठौड़, रामकिशन भामू, मनीष जाखड़, कांग्रेस के कल्याण सिंह, मोहम्मद अनवर कुरैशी, किसान सभा के हनुमान ढाका, लेखूराम, देवाराम ढाका, नौरंग सारण, विनोद सिंह राठौड़, खींवाराम ख्यालिया, हनुमान

स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया।

मुहाल ने संबोधित करते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर बिजली विभाग को निजी हाथों में सौंपने की साजिश है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि फसल बीमा क्लेम खरीफ 2023 अभी बकाया पड़ा है, फसल का उचित भाव किसान को नहीं मिल रहा है, सौर ऊर्जा टावर खेतों में लगाए जा रहे हैं जिसका मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल टंकियों की सफाई नहीं की जा रही है, गांवों में सामूहिक सरकार द्वारा लगाए गए आरओ लगभग सभी गांवों में खराब पड़े हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर किसानों में जबरदस्त आक्रोश है, अगर वक्त रहते किसानों की सभी मांगों का उचित समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा जिसका सरकार को गंभीर परिणाम भुगतना होगा। इस अवसर पर इदरिस, मनोज गुर्जर, शफीक मोहम्मद, लियाकत अली, ओंकारमल सैनी, बीरबल राम चाहर, रामगोपाल शर्मा, पूनमचंद जाखड़, भागीरथसिंह, नदीम, विजय भामु, हरिराम, खुमाराम सहित सैकड़ों की संख्या में किसान उपस्थित थे।

चोरी की आरोपी महिला गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। गुमानपुरा पुलिस टीम ने ज्वैलर्स की दुकान से पायल चोरी के मामले में कार्यवाही करते हुए महिला आरोपी^ पिंकी (24) को गिरफ्तार किया है। शहर पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि 25 जनवरी को फरियादी चेतन कुमार ने गुमानपुरा थाने में रिपोर्ट दी। फरियादी ने रिपोर्ट में कहा कि चेतन ज्वैलर्स के नाम से शारदा चौक छावनी में उसकी ज्वैलर्स की दुकान है। रिपोर्ट में कहा कि कुछ महिलाएं उसकी दुकान पर पायल खरीदने के लिये आई और पायल दिखाते समय उससे नजर चुराकर दो जोड़ी पायल चुरा कर ले गई और बिना कुछ खरीदे महिलाएं चली गई। फरियादी ने रिपोर्ट में कहा कि जब पायल वापस जमाने लगा तब दो जोड़ी पायल गायब मिली।

15 पाताल तोड़ कुओं से जल जमाव से निजात

बीकानेर, (निसं)। नगर निगम और बीकानेर विकास प्राधिकरण की ओर से शहर के 15 जगह खोदे गए भूजल रिचार्ज वाले कुएं जलभराव वाले इलाकों का आधा पानी खींच रहे हैं। यही वजह है कि जो पानी 8 से 10 घंटे तक भरा रहता था वो पानी अब चार से छह घंटे में निकल रहा है। निगम इस बारिश में जमीन के अंदर पानी जाने के बाद भूजल विभाग से पोस्ट मानसून रिपोर्ट लेकर पता लगाएगा कि इससे कितना पानी रिचार्ज हुआ, अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो अगले मानसून से पहले शहर में करीब एक दर्जन से ज्यादा कुएं और खोदे जाएंगे।

दरअसल पूरे राजस्थान में सबसे

- जो पानी 8 से 10 घंटे तक भरा रहता था, वो पानी अब चार से छह घंटे में निकल रहा है

निचले स्तर पर पानी बीकानेर में ही है। सबसे ज्यादा जलभराव भी बीकानेर में ही है। सूरसागर से लेकर कीर्ति स्तंभ चौराहा, श्रीगंगानगर चौराह, गजनेर रोड, वल्लभगार्डन, खुदखुदा, कालीमाता मंदिर के पास, कलेक्ट्रेट समेत शहर में 29 ऐसे केन्द्र हैं जहां बारिश में तालाब जैसे हालात होते हैं। मानसून से पहले निगम और बीडीए ने 8-8 पातालतोड़ कुएं बनाने शुरू किए। मानसून शुरू होने से पहले 16 में से 15 कुएं शुरू हो गए। बीकानेर में सबसे बड़ी बारिश सावन के पहले दिन 62 एमएम हुई थी। 2024 में भी बड़ी बारिश हुई थी लेकिन पानी निकलने में करीब 8 घंटे लग गए थे, मगर इस साल पानी 4 से 6 घंटे में निकल गया था। सड़क के निचले हिस्सों में जहां चारों तरफ ऊंचाई रही वहीं भरा रहा। इसलिए निगम का ये दावा सही है कि कुओं से पानी खिंच रहा है। हालांकि एक कुआं अभी बनना बाकी भी है। कलेक्ट्रेट परिसर में भी पिछले साल की बारिश में 12 घंटे तक पानी नहीं निकला था मगर इस साल चार घंटे में पानी कम हो गया।

नीमकाथाना व पाटन का वन क्षेत्र अवैध खनन की चपेट में

पाटन, (निसं)। सीकर जिले का सबसे बड़ा वन क्षेत्र पाटन व नीमकाथाना रेंज, जो कि हरियाणा सीमा से सटा हुआ है, लंबे समय से अवैध खनन और वन विनाश की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। खासतौर पर राजस्व ग्राम स्यालोदड़ा

- पाटन रेंज में कर्मचारियों व संसाधनों का भारी अभाव, जबकि नीमकाथाना रेंज की हालत भी ऐसी ही है
- इन कर्मचारियों के पास न तो पर्याप्त वाहन हैं, न वायरलेस संचार की सुविधा और न ही गश्त के लिए पर्याप्त सुरक्षा है

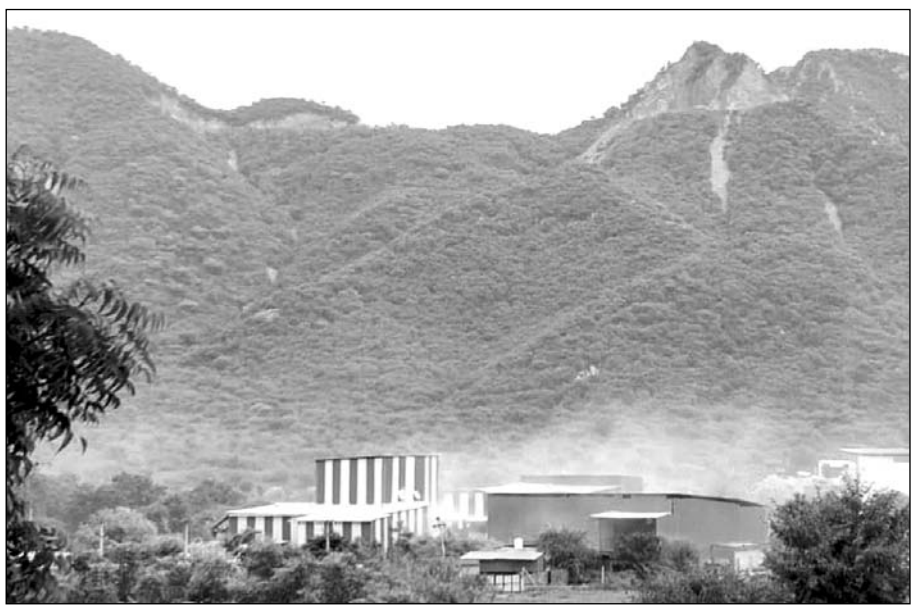

जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने र

स्थित चिड़ीमार पहाड़ (खसरा नंबर 72) और लादीकाबास पर लगातार हो रहे खनन ने पूरे क्षेत्र के पर्यावरण संतुलन को खतरे में डाल दिया है। पाटन रेंज, जो कि अरावली पर्वतमाला का एक हिस्सा है, वर्षों से हरियाणा की सीमा से लगे होने के कारण बाहरी खनन माफियाओं के निशाने पर रहा है। यहां वन विभाग के पास ना तो पर्याप्त कर्मचारी हैं और ना ही संसाधन, जिससे क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन को रोकना लगभग असंभव बनता जा रहा है।

पाटन रेंज जैसे बड़े व संवेदनशील वन क्षेत्र में सिर्फ 7 से 8 वनकर्मी कार्यरत हैं, जबकि नीमकाथाना रेंज की हालत भी कुछ अलग नहीं है। इन कर्मचारियों के पास न तो पर्याप्त वाहन हैं, न वायरलेस संचार की सुविधा और न ही गश्त के लिए पर्याप्त सुरक्षा। जबकि दूसरी ओर, सीकर जिला मुख्यालय, जहां वन क्षेत्र बहुत कम है, वहां 60 से अधिक कर्मचारी और भरपूर साधन उपलब्ध हैं।

स्थानीय ग्रामीणों व पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि चिड़ीमार पहाड़ अब लगभग समाप्ति की कगार पर है। यहां न केवल पत्थरों का अवैध खनन जारी है, बल्कि इसके कारण घने जंगल उजड़ रहे हैं, जंगली जीवों का प्राकृतिक आवास खत्म हो रहा है और क्षेत्र का पारिस्थितिकी तंत्र चरमरा रहा है। स्थानीय लोगों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पर्यावरणविदों की एकजुट मांग है कि पाटन व नीमकाथाना रेंज में तत्काल अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किए जाएं, सीकर मुख्यालय से अतिरिक्त संसाधन और कर्मचारी इन संवेदनशील क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाएं, बॉर्डर क्षेत्र पर निगरानी और सुरक्षा के लिए मोबाइल गश्त दल, वायरलेस संचार, ड्रोन आदि की व्यवस्था की जाए,अवैध खनन पर कठोर कार्रवाई हो और दोषियों को दंडित किया जाए।यदि यह मांगें शीघ्र पूरी नहीं की गईं, तो आने वाले कुछ वर्षों में पाटन रेंज का पूरा वन क्षेत्र इतिहास बन सकता है।

बुजुर्ग दंपती की हत्या मामले में चौथा आरोपी गिरफ्तार

आरोपी का बेटा पहले पकड़ा जा चुका है, दो फरार

बीकानेर, (निसं)। मुक्ता प्रसाद नगर थाना क्षेत्र में बुजुर्ग पति-पत्नी की हत्या मामले में अब एक और गिरफ्तारी हो गई है। आरोपी का बेटा पहले ही पकड़ा जा चुका है। अब तक पिता-पुत्र सहित चार को पकड़ा है। मामले में दो जने फरार है। दो आरोपियों को रिमांड पर लिया गया है। महिला आरोपी को जेल भेज दिया गया है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौरभ तिवाड़ी ने बताया कि बुजुर्ग दम्पती गोपाल वर्मा और निर्मला वर्मा की हत्या के मामले में अब विजय बंसल को गिरफ्तार किया है। विजय बंसल पहले से गिरफ्तार रोहित बंसल का पिता है। हत्या के समय वो भी इस गैंग में शामिल था। हत्या के बाद लूटे गए जेवर और नगदी लेकर फरार होने वालों में विजय बंसल भी शामिल था। उसे उत्तरप्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी दह जने प्री-प्लान तरीके से दम्पती के घर पहुंचे थे। यूपी से आए लोगों ने अपनी कार को श्रीडूंगरगढ़ में ही खड़ा कर दिया था। वहां ईशु नामक एक शख्स को खड़ा कर दिया था। उससे कार की लोकेशन मंगवाई। बीकानेर से एक कार किराए पर करके लोकेशन के आधार पर इशु के पास पहुंच गए, जहां से गाजियाबाद भाग गए। पुलिस अभी इस मामले में कर्मवरी और सुमित की तलाश कर रही है। कर्मवीर हत्याकांड में शामिल महिला आरोपी प्रिया सिसोदिया का पिता है। उसी की भूमिका इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा संदिग्ध मानी जा रही है। उसी ने स्वयं को तांत्रिक बताते हुए वर्मा दम्पती से संपर्क बनाकर रखा था।

डीडवाना में आवारा श्वान ने दो दर्जन लोगों को काटा

डीडवाना, (निसं)। डीडवाना शहर में एक आवारा श्वान (कुत्ते) ने सोमवार शाम को कोहराम मचा दिया। अजमेरी गेट से लेकर भगत सिंह सर्किल, नागौरी गेट, बस स्टैंड, फव्वारा सर्किल और नागौर रोड जैसे प्रमुख इलाकों में इस श्वान ने राह चलते लोगों पर हमला कर दिया। करीब दो दर्जन से अधिक लोगों को उसने काटकर घायल कर दिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह कुत्ता लगातार अलग-अलग स्थानों पर दौड़ते हुए लोगों पर झपट रहा था। अधिकतर पीड़ित आम नागरिक, छात्र और बाजार में खरीदारी कर रहे लोग थे, जिन पर अचानक हमला हुआ। बिना किसी उकसावे के हुए इन हमलों से लोग बुरी तरह घबरा गए। घायलों को तुरंत राजकीय जिला चिकित्सालय डीडवाना लाया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। पीएमओ डॉ. अजीत सिंह ने बताया कि सभी घायलों की स्थिति फिलहाल स्थिर है। ज्यादातर को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। श्वान के काटने के मामलों को देखते हुए अस्पताल में त्वरित चिकित्सा व्यवस्था की गई।

डॉ. सिंह ने जानकारी दी कि शाम का समय होने के बावजूद अस्पताल प्रशासन ने तत्परता दिखाई। चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ को आपात स्थिति में बुलाया गया और सभी घायलों को एंटी रेबीज इंजेक्शन व दवाएं उपलब्ध करवाई। पीएमओ ने यह भी स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर अस्पताल में दवाओं की कमी और उपचार में लापरवाही जैसी अफवाहें फैल रही हैं, जो भ्रामक और निराधार हैं। अस्पताल में सभी आवश्यक दवाओं और इंजेक्शनों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। शहर में इस प्रकार की घटना के बाद नगर परिषद और पशुपालन विभाग की लापरवाही पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि शहर में आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित किया जाए और ऐसे हमलावर श्वानों को जल्द पकड़ा जाए।

जानलेवा हमले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। रेलवे कॉलोनी पुलिस टीम ने इलाके के नोर्दन बाईपास पर व्यक्ति के उपर हुए जानलेवा हमले के मामले में कार्यवाही करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। शहर पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि 30 दिसम्बर 2024 को फरियादी सुरेश कुशवाह ने रेलवे कॉलोनी थाने में रिपोर्ट दी थी। फरियादी ने रिपोर्ट में कहा था कि वह नोर्दन बाईपास पर निवास करता है उसके पास दो जने आये और उससे मोबाइल मांगा। नहीं देने पर अपशब्द कहने लगे। उसी दौरान समझाइश कराने के लिये अनिल केवट आया। फरियादी ने रिपोर्ट में कहा कि उस समय तो मामला शांत हो गया लेकिन दो घंटे बाद आठ-दस जने हथियार लेकर आये और उससे व उसके परिवार के लोगों से मारपीट कर जानलेवा हमला किया। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया। मामले में आरोंपियों की गिरफ्तारी के लिये रेलवे कॉलोनी थानाधिकारी रामस्वरूप मीणा के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। शहर एसपी ने बताया कि गठित टीम ने तकनीकी व मुखबीर की सहायता से कार्यवाही करते हुए भदाना निवासी भोले केवट (24) को भदाना से डिटेन कर पूछताछ के बाद प्रकरण में गिरफ्तार किया। शहर एसपी ने बताया कि पुलिस टीम ने इस मामले में पूर्व में नयानोहरा निवासी धर्मराज (27) को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया है। पकड़े गये आरोपी भोले केवट से अनुसंधान जारी है।

भारतीय क्रिकेटर भी मैच न खेल पाने से निराश हैं और उन्होंने शिखर धवन को जिम्मेदार ठहराया, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी। उन्होंने धवन को सड़ा अंडा कहा और उन पर बाकी भारतीय खिलाड़ियों को खराब करने का आरोप लगाया। - शाहिद आफरीदी

पूर्व पाक क्रिकेटर, भारत-पाक मैच रद्द को लेकर।

खेल जगत

आज का खिलाड़ी — जसप्रीत बुमराह

भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का चौथा मैच बुधवार से मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में शुरू होगा। मेजबान इंग्लैंड पांच मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे है। भारत को लॉर्ड्स में पिछले मुकाबले में 22 रनों से करीबी हार झेली पड़ी थी। भारत की मैनचेस्टर में धमाकेदार वापसी पर नजर होगी। वहीं, इस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह इतिहास रच सकते हैं। उनके निशाने पर वसीम अकरम का दमदार रिकॉर्ड होगा। दरअसल, बुमराह इंग्लैंड में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले वहीं बुमराह इंग्लैंड में जारी सीरीज में अच्छी लय में दिखे हैं। वह दो मैचों में 12 विकेट ले चुके हैं।

क्या आप जानते हैं ?... ओवेन पर्दापण मैच में अर्धशतक जड़ने वाले तीसरे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज है। उन्होंने अपनी 50 रनों तूफानी पारी में छह छक्के लगाये।

पर्दापण मैच में अर्द्धशतक जड़ने वाले ओवेन तीसरे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज

नई दिल्ली, 21 जुलाई। ऑस्ट्रेलिया के मिच ओवेन ने सोमवार को अपने पर्दापण टी-20 अंतराष्ट्रीय मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ 27 गेंदों में अर्धशतक जड़ा। उन्होंने अपनी 50 रनों तूफानी पारी में छह छक्के लगाये। इसी के साथ वह तीसरे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बन गये जिन्होंने अपने पर्दापण मैच में यह कारनामा किया है। ओवेन पर्दापण मैच में अर्धशतक जड़ने वाले तीसरे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज है। इससे पहले रिकी पोंटिंग ने 2005 में न्यूजीलैंड के विरुद्ध नाबाद 98 रन और डेविड वार्नर ने 2009 में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध 89 रन बनाकर यह कारनामा किया था अब इस विशिष्ट क्लब में ओवेन शामिल हो गए।

भारतीय बैडमिंटन मिश्रित टीम ने जीता ऐतिहासिक कांस्य पदक

राइन-रुहर (जर्मनी), 21 जुलाई। भारत की मिश्रित टीम ने रविवार को जर्मनी के राइन-रुहर में चल रहे एफआईएसयू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में बैडमिंटन में ऐतिहासिक कांस्य पदक अपने नाम किया। यह इस स्पर्धा में भारत का बैडमिंटन में पहला पदक है। एफआईएसयू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में बैडमिंटन को 2007 से शामिल किया गया था, लेकिन यह पहली बार है जब भारत ने इस खेल में पोडियम पर जगह बनाई है। भारत ने क्वार्टरफाइनल में मलेशिया को कड़े मुकाबले में 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया, जिससे कांस्य पदक पक्का हो गया। प्रतियोगिता में दोनों सेमीफाइनल हारने वाली टीमों को कांस्य पदक दिया जाता है। यह इस बार के एफआईएसयू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत का पहला पदक भी है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला चीनी ताइपे से हुआ। पुरुष एकल में भारत के सतीश कुमार करुणाकरण ने पहला मैच खेला, लेकिन वे सु ली यांग से 1-2 से हार गए। इसके बाद महिला एकल में देविका सिहाग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हुआंग चिंग पिंग को 2-0 से हराकर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। हालांकि, इसके बाद चीनी ताइपे ने बढ़त बना ली। पुरुष युगल में सनीथ दयानंद और सतीश कुमार करुणाकरण की जोड़ी को चेन झी-रे और लिन यू चिएह के खिलाफ 0-2 से हार का सामना करना पड़ा।

सुमित ने जीता 60 किग्रा ग्रीको-रोमन वर्ग में रजत पदक

बुडापेस्ट 21 जुलाई। अंडर-23 एशियाई चैंपियन सुमित ने पॉलीक इमरे और वर्गा जानोस मेमोरियल 2025 कुश्ती चैंपियनशिप के 60 किग्रा ग्रीको-रोमन वर्ग में रजत और अनिल मोर ने 55 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक जीता। टूर्नामेंट में भारत ने तीन स्वर्ण, तीन रजत और चार कांस्य सहित कुल 10 पदकों के साथ अपने अभियान का समापन किया। चैंपियनशिप के आखिरी दिन रविवार को हुए फाइनल मुकाबले में भारतीय पहलवान को अजरबैजान के यूरोपीय चैंपियन और गैर-ओलंपिक 60 किग्रा वर्ल्ड चैंपियन निहात माम्मदली से 1-5 से हार के साथ रजत पदक से संतोष करना पड़ा। सुमित ने प्री-क्वार्टर फाइनल में सादिक लालाईव को 9-3, क्वार्टर फाइनल में कोरिया के डेहयूम किम को 7-4 से फॉल के जरिए शिकस्त दी थी और सेमीफाइनल में कजाकिस्तान के गालिम कबदुनास्सारोव को 10-1 से हराया। वहीं, भारत के अनिल मोर ने ग्रीको-रोमन 55 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक जीता। उन्होंने उज्बेकिस्तान के इक्थियोर बोटिरोव को 7-4 से हराया। इससे पहले अनिल ने मई में उलानबतार ओपन में इसी कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता था।

भारत-ए पुरुष हॉकी टीम को नीदरलैंड 2-8 से हराया

आइंडहोवन, (नीदरलैंड) 21 जुलाई। भारत ए पुरुष हॉकी टीम को यूरोपीय दौरे के अपने आखिरी मुकाबले में नीदरलैंड के खिलाफ 2-8 से हार का सामना करना पड़ा। रविवार को खेले गये यूरोपीय दौरे अंतिम मैच में भारतीय मिडफील्डर राजिंदर सिंह और फॉरवर्ड सेल्वम कार्थी ने अपनी टीम के लिए एक-एक गोल किए। भारत ए ने इससे पहले 18 जुलाई को नीदरलैंड के खिलाफ अपना पिछला मैच 0-3 के स्कोर से गंवा दिया था। भारत ए ने 8 जुलाई, 2025 को अपने यूरो दौरे की शुरुआत की थी और इस दौरे के दौरान पाँच यूरोपीय टीमों के खिलाफ कुल आठ मैच खेले। इस दौरान भारत की ए टीम ने दुनिया की कुछ शीर्ष हॉकी टीमों, जिनमें विश्व की नंबर वन नीदरलैंड और विश्व की नंबर तीन बेल्जियम के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तीन शहरों की यात्रा की। इस दौरान भारतीय टीम ने आठ मैचों में से तीन में जीत दर्ज की। भारत ए के कोच शिवेंद्र सिंह ने कहा, हालाँकि इस यूरोपीय दौरे में हमें जीत से ज्यादा हार मिली होगी, लेकिन यह नतीजों के बारे में नहीं था, बल्कि एक टीम के रूप में इस दौरे से मिली सीख और अनुभव के बारे में था। उन्होंने कहा, भारत ए में सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों का मिश्रण था और उन्होंने पिछले दो हफ्तो दौरान बहुत मूल्यवान अनुभव प्राप्त किया। अब जब हम भारत वापस आ रहे हैं, मुझे विश्वास है कि ये सभी खिलाड़ी इस मूल्यवान अनुभव का उपयोग करेंगे और अपने भविष्य के सभी मैचों में अपने खेल को बेहतर बनाने के लिए इसका उपयोग करेंगे।

इंग्लैंड के खिलाफ भारत को तगड़ा झटका, नीतीश रेड्डी चोटिल होने के कारण सीरीज से हुए बाहर

मैनचेस्टर, 21 जुलाई। भारतीय ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी घुटने की चोट के कारण एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के शेष मैचों से बाहर हो गये हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने सोमवार को बताया कि नीतीश कुमार रेड्डी को बाएं घुटने में चोट लगी है। यह चोट उन्हें रविवार को मैनचेस्टर में जिम में अभ्यास के दौरान लगी और स्कैन में लिगामेंट डैमेज की पुष्टि हुई है।

बुधवार से शुरु होने वाले तीसरे टेस्ट से पहले भारत को नीतीश कुमार के चोटिल होने से एक और झटका लगा है। इससे पहले तेज गेंदबाज आकाश दीप और अर्शदीप सिंह भी चोटिल हैं और इनमें से अर्शदीप चौथे टेस्ट से बाहर हो चुके हैं। इस बीच अंशुल कम्बोज को तेज गेंदबाजी विकल्प के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। लीड्स में पहले टेस्ट से बाहर रहने के बाद रेड्डी ने दूसरा और तीसरा टेस्ट खेला। बर्मिंघम में वह खास असर नहीं छोड़ पाए। उन्होंने मैच में केवल दो रन बनाए और छह ओवर की गेंदबाजी में उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। हालांकि लॉर्ड्स में उन्होंने इंग्लैंड के शीर्षक्रम के विकेट चटकाए। पहली पारी में इंग्लैंड के दोनों सलामी बल्लेबाज बेन डकेट और जैक क्रॉली को एक ही ओवर में आउट किया और दूसरी पारी में फिर से क्रॉली को आउट किया। इसके बाद उन्होंने बल्ले से 30 और 13 रन भी बनाए।

भारत ने अब तक तीनों टेस्ट में तेज गेंदबाज ऑलराउंडरों को खिलाया है। बर्मिंघम में खेले गये पहले टेस्ट में नीतीश की जगह शार्दूल ठाकुर को खिलाया गया था। नीतीश के चोटिल होने के बाद अब प्रबंधन को शार्दूल ठाकुर पर फिर से भरोसा दिखाना होगा। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह पर वर्कलोड को लेकर प्रबंधन की चिंताएं बनी हुई हैं। उल्लेखनीय है कि इंग्लैंड इस समय सीरीज में 2-1 से आगे है।

जसप्रीत बुमराह चौथा टेस्ट मैच खेलेंगे : सिराज

मैनचेस्टर, 21 जुलाई। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ बुधवार से शुरू होने वाले चौथे टेस्ट मैच में खेलेंगे। मोहम्मद सिराज ने सोमवार को मैच से पहले संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वह चौथे टेस्ट के लिये उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने कहा, भगवान ने मुझे स्वस्थ रखा है। मैं मौकों का पूरा फायदा उठाना चाहता हूं और देश के लिए ज्यादा से ज्यादा मैच खेलना चाहता हूं। जब आप देश के लिए खेलते है तो सबसे बड़ी प्रेरणा यही होती है कि आप देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जब भी मैं भारत के लिए खेलता हूं, मैं बस अपना शत-प्रतिशत देना चाहता हूं।

भारतीय टीम के ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी घुटने की चोट के कारण श्रृंखला से बाहर हो गए हैं, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह हाथ में चोट के कारण चौथे टेस्ट से बाहर हैं, आकाश दीप को कमर में चोट लगी है और ऋषभ पंत के बाएं हाथ की उंगली में चोट है। ऐसे में भारत ने हरियाणा के नए तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज को टीम में शामिल किया है और वह मैनचेस्टर में टीम से जुड़ गए हैं। बुमराह अब तक लीड्स और लॉर्ड्स में खेले गए तीन में से दो टेस्ट मैचों में खेल चुके हैं। बुमराह ने अब तक दो टेस्ट मैचों में 21.00 की औसत से 12 विकेट लिए हैं। इसमें दो बार पारी में पांच विकेट भी शामिल हैं और वह अब तक दूसरे सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं बुधवार को होने वाले चयन के लिए तेज गेंदबाज बुमराह और सिराज उपलब्ध रहेंगे। हालाँकि आकाश दीप इस मैच में खेलेंगे या नहीं यह अभी तय नहीं है। रेड्डी की चोट के कारण भारत को कम से कम एक बदलाव करना होगा।

इंग्लैंड से मैनचेस्टर टेस्ट खेलेंगे स्पिनर डॉसन

मैनचेस्टर, 21 जुलाई। इंग्लैंड ने एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के मैनचेस्टर टेस्ट के लिए प्लेइंग-11 रिलीज कर दी है। टीम में एक ही बदलाव हुआ। इंजर्ड स्पिनर शोएब बशीर की जगह लेफ्ट आर्म स्पिनर लियम डॉसन को मौका मिला। बाकी 10 प्लेयर्स वही हैं, जो लॉर्ड्स टेस्ट में खेले थे।

5 टेस्ट की सीरीज में इंग्लैंड 2-1 से आगे है। टीम ने पहला और तीसरा टेस्ट जीता था। भारत ने बर्मिंघम में दूसरा टेस्ट जीता। चौथा टेस्ट जीतकर टीम इंडिया सीरीज को 2-2 से बराबर कर सकती है। पांचवां टेस्ट 31 जुलाई से लंदन के द ओवल स्टेडियम में होगा। चौथा टेस्ट 23 जुलाई से खेला जाएगा।

8 साल बाद टेस्ट खेलेंगे डॉसन लियम डॉसन 8 साल बाद इंग्लैंड के लिए टेस्ट मैच खेलते नजर आएंगे। इससे पहले 2017 में उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ नॉटिंघम में आखिरी टेस्ट खेला था। उन्होंने 2016 में चेन्नई के मैदान पर भारत के खिलाफ ही टेस्ट डेब्यू किया था।

बशीर बॉलिंग के दौरान इंजर्ड हो गए थे डॉसन प्लेइंग-11 में ऑफ स्पिनर शोएब बशीर की जगह लेंगे। जो लॉर्ड्स टेस्ट में बॉलिंग के दौरान पहली पारी में इंजर्ड हो गए थे। वे रवींद्र जडेजा को बॉलिंग कर रहे थे, जडेजा ने सामने की ओर शॉट खेला। बशीर ने गेंद रोकने की कोशिश की, लेकिन अपना बायां हाथ इंजर्ड कर बैठे। वे फिर पारी में दोबारा बॉलिंग नहीं कर सके। बशीर दूसरी पारी में बॉलिंग करने उतरे। उन्होंने ही मोहम्मद सिराज के रूप में भारत का 10वां विकेट लेकर इंग्लैंड को 22 रन के अंतर से करीबी जीत दिलाई थी। मुकाबले के बाद मेडिकल टीम ने उन्हें सीरीज से बाहर होने की सलाह दी। जिसके बाद डॉसन को स्क्वॉड में जगह मिली।

डॉसन के नाम 371 फर्स्ट क्लास विकेट लियम डॉसन के नाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 371 विकेट हैं। 2021 के बाद से वे 12 बार पारी में 5-विकेट ले चुके हैं। जिनमें 3 बार मैच में 10 विकेट लेने का कारनामा भी शामिल है। उन्होंने करियर में 15 बार पारी में 5-विकेट लिए हैं। वे पिछले 5 साल में 9 शतक भी लगा चुके हैं। इस प्रदर्शन की बदौलत उन्हें 2024 में डोमेस्टिक प्लेयर ऑफ द ईयर का अवॉर्ड मिला था।

3 साल बाद टी-20 टीम में भी जगह बनाई 35 साल के डॉसन ने पिछले महीने ही वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 खेला था। यह उनका पिछले 3 साल में पहला ही टी-20 इंटरनेशनल था। जिसमें उन्होंने महज 20 रन देकर 4 विकेट झटक लिए थे। मैनचेस्टर टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग-11 जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जैमी स्मिथ, लियम डॉसन, ब्रायडन कार्स, जोफ्रा आर्चर और क्रिस वोक्स।

चोटिल ड्रेपर ने टोरंटो और सिनसिनाटी टूर्नामेंट से नाम वापस लिया

लंदन, 21 जुलाई। ब्रिटेन के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी जैक ड्रेपर ने बाँह की चोट के कारण टोरंटो और सिनसिनाटी में होने वाले आगामी टूर्नामेंटों से नाम वापस ले लिया है। ड्रेपर ने सोशल मीडिया मंच पर कहा, विंबलडन के बाद मेरे बाएँ हाथ में चोट लग गई, कोई गंभीर बात नहीं है। मुझे यह सुनिश्चित करना है कि बाकी सीजन के लिए यह पूरी तरह से ठीक हो जाऊं। दुर्भाग्य से, मैं टोरंटो और सिनसिनाटी में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाऊँगा। न्यूयॉर्क शहर में मिलते है। कैनेडियन ओपन 26 जुलाई से तथा सिनसिनाटी ओपन चार अगस्त से शुरू होगा। कैनेडियन ओपन से हटने वाले वह अकेले खिलाड़ी नहीं है, विंबलडन चैंपियन जैनिक सिनर और 24 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता नोवाक जोकोविच ने भी पुष्टि की है कि वे नहीं खेलेंगे।

अक्टूबर-नवंबर में भारत में आयोजित होगा फिडे वर्ल्ड कप 2025

नई दिल्ली, 21 जुलाई। इस साल अक्टूबर-नवंबर में शतरंज वर्ल्ड कप का आयोजन भारत की मेजबानी में होगा। वहीं इस आयोजन के लिए मेजबान शह का नाम अभी घोषित नहीं किया गया, खेल की वैश्विक शासी संस्था फिडे ने सोमवार को इसकी घोषणा की। वहीं इस टूर्नामेंट में 206 खिलाड़ी प्रतिष्ठित खिताब और 2026 फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालीफिकेशन स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। भारत ने पिछली बार 2002 में हैदराबाद में इस आयोजन की मेजबानी की थी, जहां विश्वनाथन आनंद ने खिताब जीता था। साथ ही खिलाड़ी नॉकआउट प्रारूप में प्रतिस्पर्धा करेंगे, जहां प्रत्येक राउंड में हारने वाला खिलाड़ी सीधे तौर पर बाहर हो जाएगा। फिडे ने कहा कि, इस आयोजन में पिछले कुछ वर्षों में कई प्रारूपों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन 2021 से इसमें एकल-उन्मूलन प्रारूप अपनाया गया है। प्रत्येक दौर तीन दिनों तक चलता है- पहले दो दिन दो क्लासिक खेल, और जरूरत पड़ने पर तीसरे दिन टाई-ब्रेक।पहले दौर में शीर्ष 50 खिलाड़ियों को बाई मिलती है। जबकि 51 से 206 तक के खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिसमें जोड़ी शीर्ष आधे बनाम उलट निचले आधे के सिद्धांत पर आधारित होती है।

एशिया कप 2025 हॉकी : टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम को भारत नहीं भेजेगा पाकिस्तान, सुरक्षा कारणों का दिया हवाला

नई दिल्ली, 21 जुलाई। पाकिस्तान हॉकी महासंघ ने खेल की वैश्विक नियामक संस्था एफआईएच को सूचित किया है कि सुरक्षा चिंताओं के कारण उसके लिए महीने होने वाले एशिया कप के लिए अपनी टीम को भारत भेजना मुश्किल होगा। पीएचएफ के प्रमुख तारिक बुगती ने कहा कि उन्होंने एफआईएच और एशियाई हॉकी महासंघ को पत्र लिखकर टीम को भारत भेजने को लेकर अपने फैसले से अवगत करा दिया है।उन्होंने कहा कि, हमने उन्हें सूचित किया है कि मौजूदा परिदृश्य में हमारी टीम को भारत में खेलते समय सुरक्षा संबंधी खतरों का सामना करना पड़ सकता है। हमने उन्हें बता दिया है कि हमारे खिलाड़ी एशिया कप के लिए भारत जाने के इच्छुक नहीं हैं। एशिया कप वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग टूर्नामेंट भी है। पीएचएफ प्रमुख ने कहा कि अब प्रतियोगिता और पाकिस्तान के मैचों के बारे में निर्णय लेने की जिम्मेदारी एफाईएच और एएचएफ पर है। उन्होंने कहा कि, हमने उनसे पूछा है कि हमें बताएं कि क्या गारंटी है कि हमारे खिलाड़ी भारत में सुरक्षित रहेंगे और टूर्नामेंट पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। पाकिस्तान सरकार ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है लेकिन हाल ही में एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा था कि टीम भारत नहीं जाएगी इससे पहले भारतीय खेल मंत्रालय के सूत्रों ने स्पष्ट किया था कि वह पाकिस्तान हॉकी टीम को अगले महीने भारत में होने वाले एशिया कप में शामिल होने से नहीं रोकेंगे। खेल मंत्रालय के सूत्र ने बताया कि वे बहु-राष्ट्रीय टूर्नामेंट में किसी टीम के शामिल होने के खिलाफ नहीं हैं। हॉकी एशिया कप का आयोजन 27 अगस्त से सात सितंबर तक बिहार के राजगीर में होना है।

कोनेरू हम्पी फिडे महिला शतरंज विश्वकप के सेमीफाइनल में

बटुमी (जॉर्जिया), 21 जुलाई। भारतीय ग्रैंडमास्टर कोनेरू हम्पी ने चीनी खिलाड़ी के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए फिडे महिला शतरंज विश्वकप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसी के साथ हम्पी इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुँचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गईं। हम्पी ने रविवार को खेले गये मुकाबले में चीन की आईएम युक्सिन सोंग के खिलाफ पहले गेम में जीत के बाद, दूसरे गेम में ड्रॉ खेलकर अंतिम चार में जगह बनाई। हम्पी का अब सेमीफाइनल में चीन की लेई टिंगजी से मुकाबला होगा। अंतिम चार में हम्पी के पहुंचने के साथ यह पक्का हो गया कि उन्हें शीर्ष तीन में पहुंचने के दो मौके मिलेंगे जिससे उन्हें अगले महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में जगह भी मिल जाएगी जिसके लिए शीर्ष तीन खिलाड़ी क्वालिफाई करेंगी।

विश्व चैम्पियनशिप से पहले चाइना ओपन में सात्विक-चिराग की नजरें दमदार प्रदर्शन पर

नई दिल्ली, 21 जुलाई। सात्विक साइराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारत की शीर्ष पुरुष युगल जोड़ी मंगलवार से शुरू हो रहे चाइना ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट में आगामी विश्व चैंपियनशिप के लिए लय हासिल करने के लक्ष्य के साथ कोर्ट पर उतरेगी। चाइना ओपन पेरिस में 25 से 31 अगस्त तक होने वाली विश्व चैंपियनशिप से पहले अंतिम प्रमुख प्रतियोगिता है। इसलिए प्रत्येक खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बेताब होगा।

वर्तमान में विश्व में 15वें स्थान पर काबिज सात्विक और चिराग इस सत्र में तीन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं लेकिन अभी तक फाइनल में जगह बनाने में नाकाम रहे हैं। यही नहीं उन्हें पिछले सप्ताह जापान ओपन में पेरिस ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन के लियांग वेई केंग और वांग चांग से हार का सामना करना पड़ा था। विश्व की पूर्व नंबर एक भारतीय जोड़ी पहले दौर में जापान के केन्या मित्सुहाशी और हिरोकी ओकामुरा का सामना करेगी। एकल वर्ग में लक्ष्य सेन, एचएस प्रणय और पीवी सिंधू 20 लाख डॉलर इनामी प्रतियोगिता में अपनी फॉर्म वापस पाने की उम्मीद करेंगे।

पिछले कुछ समय से फॉर्म में वापसी करने के लिए संघर्ष कर रहे लक्ष्य पिछले सप्ताह जापान ओपन में दूसरे दौर से आगे नहीं बढ़ पाए थे। यहां उनका पहला मुकाबला चीन के पांचवीं वरीयता प्राप्त ली शी फेंग से होगा।

भारत के एक अन्य खिलाड़ी प्रणय पहले दौर में जापान के कोकी वतनबे का सामना करेंगे। अब 16वीं रैंकिंग पर काबिज सिंधू के लिए इंडिया ओपन में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचना इस साल उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है।

पिछले सप्ताह वह कोरिया की सिम यू जिन से हार गईं थी। यह इस वर्ष पांचवा अवसर था जबकि वह पहले दौर से आगे नहीं बढ़ पाई थी। सिंधू का पहला मुकाबला जापान की छठी वरीयता प्राप्त 18 वर्षीय पूर्व विश्व जूनियर चैंपियन तोमोका मियाजाकी से होगा। महिला एकल में ही इस वर्ष की शुरुआत में ताइपे ओपन सेमीफाइनलिस्ट रहीं उन्नित हुड्डा का पहले दौर में स्कॉटलैंड की क्रिस्टी गिलमोर से मुकाबला होगा, जबकि अनुपमा उपाध्याय का सामना चीनी ताइपे की लिन सियांग टी से होगा।

ऑस्ट्रेलिया ने टी-20 में विंडीज को 3 विकेट से हराया

किंगस्टन, 21 जुलाई। बेन ड्वारशिवस (चार विकेट) की बेहतरीन गेंदबाजी के बाद कैमरन ग्रीन (51) और मिचेल ओवेन (50) की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने सोमवार को पहले टी-20 मुकाबले में वेस्टइंडीज को सात गेंदे शेष रहते तीन विकेट से हरा दिया। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने पांच मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। मिचेल ओवेन को उनके शानदार प्रदर्शन के लिये 'प्लेयर ऑफ द मैच' के पुरस्कार से नवाजा गया। 190 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने दूसरे ही ओवर में जेक फ्रेजर-मक्गार्क (दो) का विकेट गवां दिया। ऑस्ट्रेलिया का दूसरा विकेट कप्तान मिचेल मार्श 17 गेंदों में (24) रन के रूप में गिरा। इसके बाद जॉश इंग्लिस आठ गेंदों में (18) रन बनाकर पवेलियन लौट गये। ग्लेन मैक्सवेल (11) रन बनाकर आउट हुये।

राजस्थान कोर्फबॉल टीम घोषित

जयपुर, 21 जुलाई। 30वीं राष्ट्रीय जूनियर कोर्फबॉल प्रतियोगिता 24-27 जुलाई 2025 तक चैन्नई, तमिलनाडु में आयोजित होने जा रही है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली राजस्थान टीम की घोषणा राज्य संघ द्वारा की गई जो कि कल रेल द्वारा चैन्नई, तमिलनाडु के लिए रवाना होगी। टीम निम्न प्रकार है: अर्पित मीना (जयपुर), रुचिका चौधरी, चरित जांगिड़, तनज, रोहित पाल, नेहल खान, मो0 शरफ अली, अल्शिफा बानो, मो0 नोमान, कोमल शेखावत, देवेश मेहरा, अर्श नासिर खान, परसराम शर्मा (कोच), आफताब (मैनेजर)।

प्रथम अंडर-15 राजस्थान बॉयज क्लब फुटबॉल लीग का आगाज

जयपुर, 21 जुलाई। राजस्थान फुटबॉल संघ के तत्वाधान में विद्याधर नगर स्थित फुटबॉल मैदान पर रविवार से इतिहास में पहली बार अंडर - 15 राजस्थान बॉयज क्लब फुटबॉल लीग 2025 का आगाज राजस्थान फुटबॉल संघ सचिव दिलीप सिंह शेखावत एवं ब्रिगेडियर जितेंद्र सिंह शेखावत द्वारा किया गया। संघ सचिव दिलीप सिंह शेखावत ने बताया कि अंडर - 15 खिलाड़ियों की यह लीग राजस्थान में पहली बार आयोजित की जा रही है जो तीन महीने तक चलेगी जिसमें राज्य के 10 पेशेवर फुटबॉल क्लब कुल 90 मैच खेलेंगे।

संघ का उद्देश्य ग्रासरूट फुटबॉल को डवलप करना है उसी आधार पर पहले अंडर -13 तथा अब अंडर -15 लीग का आयोजन किया जा रहा है एवं आगामी दिनों में अंडर - 17 फुटबॉल लीग खेली जाएगी। इससे कम उम्र के खिलाड़ी खेल से जुड़ेंगे तथा लगातार प्रतियोगिताओं से राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान को लाभ मिलेगा। रविवार से शुरू हुई लीग में पहले दिन चार मैच खेले गए

पहला मैच रेड स्टोन सिटी फुटबॉल क्लब एवं जयपुर बॉयज एंड गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी के मध्य खेला गया जिसमें जयपुर बॉयज एंड गर्ल्स फुटबॉल क्लब 2 - 0 से विजयी रहा, विजेता टीम की तरफ से हर्ष सिंह और अरमान ने एक - एक गोल किया,

दूसरा मैच जयपुर फ़ुट्सल एवं मेवाड़ स्पोर्ट्स फाउंडेशन के बीच खेला गया जिसमें मेवाड़ स्पोर्ट्स फाउंडेशन 12 - 1 से विजयी रहा, विजेता टीम की तरफ से मस्तकीम ने 6, अनस ने 3, जोरीइंग, प्रेम और यश ने एक - एक गोल किया एवं जयपुर फ़ुट्सल की तरफ से एकमात्र गोल श्रेष्ठ ने किया। **तीसरा मैच** फुटबॉल क्लब ब्रदर्स यूनाइटेड एवं चैंपियन मेकर फुटबॉल क्लब के मध्य खेला गया जिसमें ब्रदर्स यूनाइटेड ने 18 - 0 से एकतरफा जीत हासिल की, विजेता टीम की तरफ से वीरेन और अयान ने 4 - 4, इंद्र, सैजान एवं प्रवीण ने 2 - 2, एलेक, देवांशू, कानूराम एवं दिव्यांशु ने 1-1 गोल किया।

चौथा मैच राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब एवं जयपुर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के बीच खेला गया, इस संघर्षपूर्ण मुकाबले में राजस्थान यूनाइटेड ने 2 - 1 से जीत हासिल की, विजेता टीम की तरफ से प्रिंस शर्मा और ध्रुव सांखला ने 1 - 1 गोल किया वहीं जयपुर यूनाइटेड की तरफ से एकमात्र गोल अभय प्रताप ने किया। मैच में भैरू रतन ओझा ने मैच कमिश्नर तथा विष्णु गेनण, रूपेंद्र सिंह राठौड़, विकास चौधरी, अवकाश दायमा, सिमरनजीत सिंह ने निर्णायक की भूमिका निभाई।

राजस्थान स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन की एजीएम सम्पन्न : निष्क्रिय और विवादित खेल संघों की मान्यता समाप्त की गई

जिला ओलंपिक संघों को छह माह के भीतर नये विधान के तहत चुनाव कराने के निर्देश

जयपुर, 21 जुलाई। राजस्थान स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन की साधारण सभा की वार्षिक बैठक (एजीएम) रविवार को यहां संपन्न हुई। राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष तेजस्वी सिंह गहलोत की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में प्रदेश में खेलों के विकास और खेल संघों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता के लिए कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में राजस्थान ओलंपिक संघ से एफिलिएटेड मेम्बर्स, गैर ओलंपिक खेलों के प्रतिनिधि और जिला ओलंपिक संघों के प्रतिनिधि शामिल हुए। राजस्थान खेल परिषद के सचिव राजेन्द्र सिंह सिसोदिया भी अतिथि के रूप में एजीएम में मौजूद रहे। बैठक में राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन के स्पोंसर पार्टनर को सम्मानित किया गया जिनमे अमित गोयल गुस्तुरा प्राइवेट लिमिटेड, संजीव गोड डायरेक्टर ऑरिएन्टल एडुमेड, दीपेंद्र सिंह एवं देवनारायण गुर्जर को विशेष सहयोग के लिए सम्मानित किया गया।

बैठक के बाद एसोसिएशन के सचिन सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि करीब तीन घंटे से ज्यादा चली बैठक में एजेंडा के अनुसार कार्रवाई हुई, जिसे सभी सदस्यों ने ध्वनिमत के साथ पारित कर दिया। एजेंडा के अनुसार अगले वित्तीय वर्ष के लिए ऑडिटर की नियुक्ति और उसका पारिश्रमिक तय करने का अधिकार अध्यक्ष को सचिव को सौंपा गया। इस दौरान सदस्यों ने अपनी समस्याएं भी उठाईं, जिन्हें सदन में चर्चा के साथ अध्यक्ष ने उनका समाधान निकालने का आश्वासन दिया। सदस्यों की मुख्य समस्या राजस्थान खेल परिषद की ओर से विगत दिनों निकाले एक सर्कुलर को लेकर थी, जिसमें सहकारिता विभाग में रजिस्ट्रेशन के बिना राजस्थान नाम का उपयोग नहीं करने की हिदायत दी गई थी। इस पर एजीएम में मौजूद राजस्थान खेल परिषद के सचिव राजेन्द्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि राजस्थान में खेल कानून लागू है और उसकी पालना सभी को करनी होगी। उन्होंने कहा कि कुछ खेल, जो ओलंपिक में शामिल हैं, स्पोर्ट्स एक्ट की सूची में शामिल होने से रह गए थे। ऐसे खेल संघों को जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है लेकिन यह बदलाव विधानसभा में ही होगा। राजस्थान खेल परिषद इसके लिए प्रयास कर रही है।

अध्यक्ष तेजस्वी सिंह ने कहा कि बैठक में सभी जिला ओलंपिक संघों को हिदायत दी गई है कि वे राजस्थान ओलंपिक संघ के विधान के अनुरूप अपने विधान में बदलाव करें और उसके बाद जल्द अपने नये चुनाव कराएं। सदन की अनुमति से इसके लिए छह माह का समय निर्धारित किया गया है। इस दौरान सभी जिला संघ इस कार्रवाई को पूरा कर लेंगे। अध्यक्ष की सहमति से उठाए कुछ अन्य अहम मुद्दों के बारे में तेजस्वी सिंह ने कहा कि राजस्थान में जूडो के समानांतर दो दो संघ बने हैं, वहीं भारतीय हैंडबॉल संघ की मान्यता भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से समाप्त कर दी गई है।

राजस्थान तैराकी संघ भी पिछले काफी समय से न तो ओलंपिक संघ की गतिविधियों में हिस्सा ले रहा है और न ही उन्होंने वार्षिक फीस जमा कराई है। ऐसे में उक्त तीनों राज्य खेल संघों की मान्यता समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। तेजस्वी सिंह ने कहा कि कुछ खेल संघ काफी समय से निष्क्रिय पड़े हैं। इनकी ओर से न कोई खेल गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, और न ही उनकी ओर से संचालित गतिविधियों की जानकारी राजस्थान ओलंपक संघ को दी जा रही है। राजस्थान याचिंग एसो., राजस्थान रोलबॉल एसो. और राजस्थान थ्रोबाल एसो. की मान्यता भी निलंबित की गई है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्रीराम कलपाती राजेन्द्रन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। राजभवन में आयोजित समारोह में मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

राज्यपाल ने के.आर. श्रीराम को मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई

वे राजस्थान हाईकोर्ट के 43 वें मुख्य न्यायाधीश हैं

- राजस्थान आने से पहले के.आर. श्रीराम मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे।

जयपुर, 21 जुलाई। राजभवन में आयोजित गरिमापूर्ण समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े ने न्यायमूर्ति के आर श्रीराम को राजस्थान के चीफ जस्टिस (सीजे) पद की शपथ दिलाई। वे मद्रास हाईकोर्ट से ट्रांसफर होकर आए हैं। उन्होंने हाईकोर्ट के 43 वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने राज्यपाल की अनुमति लेकर राष्ट्रपति की ओर से जारी नियुक्ति वारंट पढ़ा।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद और हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश सहित, न्यायिक अधिकारी व वकील मौजूद रहे। शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल और दिया कुमारी सहित अन्य लोगों ने सीजे श्रीराम को बधाई दी। गौरतलब है कि हाल ही में हाईकोर्ट के सीजे एमएम श्रीवास्तव का मद्रास हाईकोर्ट और वहां सीजे रहे न्यायमूर्ति केआर श्रीराम का राजस्थान हाईकोर्ट में तबादला किया गया था। राजस्थान हाईकोर्ट में सीजे श्रीराम का कार्यकाल 69 दिनों का रहेगा।

28 सितंबर, 1963 को मुंबई में जन्मे सीजे केआर श्रीराम ने मुंबई विश्वविद्यालय से एलएलबी करने के बाद लंदन से मैरीटाइम लॉ में एलएलएम किया। वहीं, वे जुलाई 1986 को महाराष्ट्र एवं गोवा बार कौंसिल में वकील के रूप में पंजीकृत हुए। बतौर वकील, उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उपभोक्ता आयोगों, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण और कंपनी कानून बोर्ड में वकालत की और काफी सफल रहे। उन्हें 21 जून, 2013 को बॉम्बे हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 2 मार्च 2016 को इस पद पर स्थायी कर दिया गया। जस्टिस श्रीराम को 21 सितंबर 2024 को मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत किया गया। दूसरी ओर, व्यक्तिगत जीवन में सीजे श्रीराम सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल होते थे। उन्होंने कई सालों तक एक एनजीओ में उपाध्यक्ष के तौर पर कार्य किया। यह एनजीओ दिवंगत लोगों के लिए अंतिम संस्कार और श्राद्ध करने की व्यवस्था करता है। इसके अलावा उन्हें गोल्फ खेलना भी पसंद है।

कोटा में संरक्षित प्रजाति का दुर्लभ ''स्ट्रीक्ड कुकरी स्नेक'' मिला

यह सांप जहरीला नहीं होता है, कोटा और हाड़ौती क्षेत्र में बहुत ही कम देखने को मिलता है

- इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंज़र्वेशन ऑफ नेचर ने धारीदार कुकरी सांप को संरक्षित प्रजाति माना।

कोटा शहर के बोरखेड़ा इलाके में दुर्लभ प्रजाति का ''स्ट्रीक्ड कुकरी स्नेक'' (धारीदार कुकरी सांप) मिला है। यह सांप जहरीला नहीं होता है और कोटा और हाड़ौती क्षेत्र में बहुत ही कम देखने को मिलता है।

कोटा, 21 जुलाई (निसं)। शहर के बोरखेड़ा इलाके में दुर्लभ प्रजाति का रेयर ''स्ट्रीक्ड कुकरी स्नेक'' (धारीदार कुकरी सांप) मिला है। यह सांप जहरीला नहीं होता है लेकिन कोटा और हाड़ौती क्षेत्र में बहुत ही कम देखने को मिलता है। नगर निगम के राकेश सेन ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से बारां रोड स्थित जय हिन्द नगर में एक घर से सांप के बच्चे के निकलने की सूचना मिल रही थी। जब वे मौके पर गए तो उन्हें एक कुकरी स्नेक नज़र आया, जिसे उन्होंने रैस्क्यू किया। मकान मालिक ने बताया कि कुछ सांपों के बच्चे झाड़ू से बाहर निकाल दिए गए। यह ''धारीदार कुकरी सांप,'' जिसे अंग्रेजी में ''स्ट्रीक्ड कुकरी स्नेक'' कहते हैं, आमतौर पर 15 से 18 इंच लंबा होता है। इस सांप का ऊपरी हिस्सा भूरे रंग का और नीचे का हिस्सा सफेद रंग का होता है। यह सांप एक बार में 5 से 8 अंडे देता है।

कोटा के सर्प विशेषज्ञ विष्णु श्रृंगी ने बताया कि यह सांप कोटा में बहुत कम पाया जाता है। कोटा में इस सांप को लगभग 3 से 4 बार ही रेस्क्यू किया गया है। पर्वतीय इलाकों में पाए जाने वाले ये सांप शर्मीले होते हैं, लेकिन छेड़े जाने पर काट लेते हैं। श्रृंगी ने बताया कि स्ट्रीक्ड कुकरी स्नेक को ''ऑलिगोडन टेनिओलेटास'' जीन्स के सांपों के रूप में भी जाना जाता है। अलग-अलग रंग होने के कारण इन्हें कुकरी स्नेक कहा जाता है। भारत, नेपाल और पाकिस्तान में मिलने वाले ये सांप, भारत में मुख्य तौर पर केरल, कर्नाटक व तमिलनाडु में पाए जाते हैं। ये सांप जहरीले नहीं होते हैं लेकिन इसकी विशेषता यह है कि कुकरी चाकू के तरह इनके दांत मुड़े हुए होते हैं, जिनका उपयोग ये अंडों को खाने के लिए करते हैं। इन सांपों का मुख्य भोजन छिपकली, कीड़े और सरीसृप के अंडे होते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंज़र्वेशन ऑफ नेचर ने इसे संरक्षित प्रजाति माना है।

अमरिकन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

समाचार पत्र की रिपोर्ट में कहा गया कि इनमें से लगभग 50 मामले ट्रम्प प्रशासन द्वारा कुछ विदेशी छात्रों को उनके इमिग्रेशन रिकॉर्ड और आपराधिक रिकॉर्ड में अनियमितताओं के कारण निष्कासित करने के प्रयासों का हिस्सा थे। वाइट हाउस ऐसे 90 प्रतिशत से अधिक मामलों में हार गया।

ट्रंप की पहल के खिलाफ फैसला सुनाने वाले जज मुख्य रूप से पूर्व राष्ट्रपतियों, बराक ओबामा और जो बाइडेन द्वारा नियुक्त जज हैं। अखबार की रिपोर्ट के अनुसार,उन्होंने ट्रंप के रुख के खिलाफ 125 से ज़्यादा बार फैसला सुनाया है।

अपनी अवहेलना से दु:खी धनखड़ ने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जानकारी मिली है कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिये थे।

लेकिन सरकार चाहती थी कि विपक्ष लोकसभा में भी हस्ताक्षर करे। लेकिन विपक्ष ने यह कहते हुये इनकार कर दिया कि राज्यसभा में तो पहले ही ज़रूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

सूत्रों के अनुसार, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सरकार को सलाह दी थी कि यह प्रस्ताव दोनों सदनों में एक साथ लाया जाए, लेकिन इसने एक समस्या का रुप ले लिया।

अगर ऐसा होता, तो दोनों सदनों के अध्यक्ष इसे खारिज नहीं कर सकते थे और इसे स्वीकार करना होता।

सरकार की ओर से धनखड़ को लेकर कई तरह की बातें फैलाई जा रही थीं, जैसे कि वे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहुत तारीफ कर रहे थे और बार-बार यूपी जा रहे थे। इसके अलावा, सांसदों को बांटे गए लैपटॉप में घोटाले की बात भी उछाली गई। यह भी कहा गया कि राज्यसभा में कुछ लोगों को पैसे लेकर नौकरी दी गई। ऐसी ही कई अन्य बातें भी कही जा रही थीं।

कारण जो भी रहे हों, यह साफ है कि आज शाम 4:30 बजे तक उनके इस्तीफे का कोई संकेत नहीं था।

लेकिन उसके बाद अचानक इस्तीफा दे दिया गया।

यह भी साफ है कि उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा गया था, जिससे सरकार के भीतर एक अभूतपूर्व स्थिति बन गई है।

एक बार फिर मोदी विदेश ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भारत और मालदीव के रिश्ते इस समय एतिहासिक रूप से बेहद खराब हैं। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू की सरकार ने भारतीय सेना को मालदीव से हटने को कहा है और मालदीव सरकार चीन के काफ़ी करीब चली गई है। हिंद महासागर में चीन का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है और भारत की पारंपरिक पकड़ कमजोर हुई है। आलोचकों का कहना है कि इस यात्रा से केवल प्रतीकात्मक फायदे हो सकते हैं, जबकि असली नीतिगत बदलाव की उम्मीद कम है।

ब्रिटेन की यात्रा भी समय के लिहाज से ठीक नहीं मानी जा रही है। ब्रैग्ज़िट के बाद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था कमजोर है, महंगाई, राजनीतिक अस्थिरता और वैश्विक स्तर पर सीमित भूमिका से इसका सामना है। भारत-ब्रिटेन के बीच लंबित मुक्त व्यापार समझौते पर कोई ठोस प्रगति नहीं दिख रही है। हाल ही में हुए आम चुनावों के बाद वहां नई सरकार बनी है, जिससे वार्ताओं में और देरी हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल ब्रिटेन भारत को कोई खास आर्थिक लाभ नहीं दे सकता। ऐसे में यह दौरा केवल औपचारिकता तक सीमित रह सकता है। यह संसद सत्र दो बड़े सुरक्षा मामलों, ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमल, के बाद पहला सत्र है। इसके साथ ही अरुणाचल सीमा के पास चीन की सैन्य गतिविधियों को लेकर भी चिंता बढ़ी है। विपक्ष की मांग है कि प्रधानमंत्री इन विषयों पर संसद में स्वयं बयान दें। उनकी अनुपस्थिति को जवाबदेही से बचने के तौर पर देखा जा रहा है, जो संसद की संवैधानिक भूमिका को कमजोर करता है।

आलोचकों का कहना है कि यह फैसला भारत की विदेश नीति और घरेलू लोकतांत्रिक जिम्मेदारियों के बीच बढ़ते अंतर को दर्शाता है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सक्रियता जरूरी है, लेकिन संसद के अहम सत्रों में प्रधानमंत्री की मौजूदगी लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है। संकट के समय संसद से दूरी, विपक्ष के उस आरोप को और बल देती है कि सरकार एकतरफा तरीके से चलाई जा रही है।

निष्कर्ष यह है कि विश्व के मौजूदा हालात को देखते हुए मोदी की इस विदेश यात्रा से कोई ठोस रणनीतिक लाभ मिलने की संभावना कम है। मालदीव पूरी तरह चीन के पाले में जा चुका है और ब्रिटेन अभी किसी महत्वपूर्ण समझौते की स्थिति में नहीं है। वहीं, भारतीय संसद में देश के सबसे गंभीर मुद्दों पर बहस हो रही है। इस स्थिति में प्रधानमंत्री का विदेश दौरा लोकतांत्रिक ज़िम्मेदारी से अधिक कूटनीतिक दिखावे को प्राथमिकता देने जैसा है।

हाई कोर्ट ने मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में सभी 12 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी किया

महाराष्ट्र सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी

- हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष के दावे में बुनियादी खामिया हैं। सबूत भी पर्याप्त नहीं हैं। यह विश्वास करना कठिन है कि आरोपियों ने अपराध किया है।
- ज्ञातव्य है कि 11 जुलाई को मुम्बई लोकल ट्रेन में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 189 लोग मारे गए थे, 700 से ज्यादा घायल हुए थे और 19 साल बाद केस पर फैसला आया है।

मुंबई, 21 जुलाई। बंबई उच्च न्यायालय ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले में 2006 मुंबई लोकल ट्रेन सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले के सभी 12 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

महाराष्ट्र सरकार ने 2006 के मुंबई ट्रेन बम धमाकों में आरोपी व्यक्तियों को बरी करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार हाई कोर्ट के आदेश की समीक्षा करेगी और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का निर्णय लेगी।

न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की एक विशेष पीठ ने अपने फैसले में कहा कि अदालत के सामने जो सुबूत रखे गए, वे आरोपियों का अपराध साबित करने में अपर्याप्त हैं। अदालत ने कहा कि 'यह विश्वास करना कठिन है कि आरोपियों ने अपराध किया था।'

उच्च न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष के दावे में कई बुनियादी खामियां हैं। पीठ ने अविश्वसनीय गवाहों, संदिग्ध पहचान परेड और यातना देकर इकबालिया बयान लेने के लिए भी जांच दल की आलोचना की। अदालत ने पाया कि इस्तेमाल हुए बम के ब्यौरे सहित दूसरे बुनियादी तथ्यों को भी स्थापित करने में एटीएस विफल रही है। गवाहों के बयानों और कथित बरामदगी का 'कोई साक्ष्य मूल्य नहीं' माना गया।

न्यायालय ने कहा कि जाँच एजेंसियाँ आरोपियों के खिलाफ आरोपों की पुष्टि के लिए कोई ठोस सबूत पेश करने में विफल रहीं। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए, अब सभी आरोपियों को इस आधार पर बरी कर दिया है कि हमलों में उनकी संलिप्तता साबित करने के लिए जांच एजेंसियों के पास पर्याप्त सबूत नहीं हैं।

अदालत ने इस मामले में पाँच व्यक्तियों को मिली मृत्युदंड की सजा और शेष सात को मिली आजीवन कारावास की सजा को भी रद्द कर दिया। यह फैसला हादसे के 19 साल बाद आया।

यह भयावह घटना 11 जुलाई, 2006 को तब हुई थी, जब शाम के व्यस्त समय में मुंबई के उपनगरीय रेलवे नेटवर्क में पश्चिम रेलवे की ट्रेनों के प्रथम श्रेणी के डिब्बों को निशाना बनाकर बम विस्फोटों को अंजाम दिया गया। उन सिलसिलेवार विस्फोटों में सांताक्रूज, बांद्रा-खार रोड, जोगेश्वरी-माहिम जंक्शन, मीरा रोड-भायंदर, माटुंगा-माहिम जंक्शन और बोरीवली सहित कई स्थानों को निशाना बनाया। हताहतों की संख्या बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रेशर कुकर बमों ने 189 लोगों की जान ले ली और 700 से ज़्यादा घायल हो गए।

यह मामला महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) को जांच के लिए सौंपा गया था। शुरूआती जाँच में आतंकवादी संगठनों, लश्कर-ए-तैयबा और सिमी की संलिप्तता के संकेत मिले थे, जिसके बाद 12 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए गए। एटीएस की जांच के आधार पर विशेष मकोका अदालत ने सितंबर 2015 में सभी बारह अभियुक्तों को दोषी ठहराया था।

इनमें से पाँच को निचली अदालत ने मौत की सज़ा और सात को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। आरोपियों ने बाद में इस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी, जहाँ न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की विशेष पीठ ने लगातार सुनवाई की।

एटीएस ने अपनी जाँच ने हमलों को प्रतिबंधित स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) और पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी समूहों से जोड़ते हुए आरोप लगाया कि मुख्य साजिशकर्ता मोहम्मद फैसल शेख (लश्कर-ए-तैयबा का मुंबई प्रमुख) को हवाला से पैसा मिला था। न्यायिक जाँच में इस दावे की पुष्टि नहीं हो सकी। अदालत का यह फैसला महाराष्ट्र एटीएस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।

न्यायाधीश वर्मा के ''इम्पीचमैंट''...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

- महाधिवक्ता का यह भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में गठित ''जांच समिति'' असंवैधानिक है, तथा इसके गठन से पुलिस के काम-काज में बेवजह दखल हो रही है।

गए एक अन्य लंबित महाभियोग प्रस्ताव का उल्लेख करते हुए, धर्मनिरपेक्षता व लोकतान्त्रिक मूल्य के प्रति संसद की प्रतिबद्धता पर प्रश्न उठाया।

इस बीच, न्यायमूर्ति वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इन-हाउस जांच को चुनौती दी है। उनका कहना है कि यह जांच संसद के अधिकारों का अतिक्रमण करती है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करती है। हालांकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका सूचीबद्ध नहीं की है, क्योंकि संसद में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर विचार चल रहा है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने के लिए कांग्रेस सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं।

मार्च में आग लगने की सूचना पर आपातकालीन सेवा कर्मचारियों ने जब दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज वर्मा के आवास पर पहुंचकर आग बुझाई, तो उन्हें उनके आउट-हाउस में बड़ी मात्रा में आधी जली हुई नकदी मिली। उस समय के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने उच्च न्यायालयों के तीन न्यायाधीशों की समिति बनाई, जिसने न्यायमूर्ति वर्मा को दोषी ठहराया।

जस्टिस संजीव खन्ना ने यह मामला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भेजा गया कि न्यायमूर्ति वर्मा ने इस्तीफा देने से मना कर दिया है, इसलिए उन्हें हटाया जाए। जस्टिस वर्मा को वापस इलाहाबाद उच्च न्यायालय भेज दिया गया, लेकिन न्यायिक कार्य से अलग रखा गया। न्यायमूर्ति वर्मा ने अपनी बेगुनाही का दावा करते हुए, सुप्रीम कोर्ट में समिति की रिपोर्ट को चुनौती दी है।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में वकील एन. एन. नडुमपारा ने न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका पर शीघ्र सुनवाई की मांग की। उन्होंने जब केवल ''वर्मा'' कहकर उनका उल्लेख किया, तो मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा, अगर आप यह चाहते हैं कि मैं इस याचिका को खारिज कर दूं, तो इसे अभी खारिज किए देता हूँ। क्या न्यायमूर्ति वर्मा आपके मित्र हैं? वे अभी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। आप उन्हें 'वर्मा' कहकर कैसे संबोधित कर सकते हैं? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इसका विरोध किया।

नडुमपारा की याचिका में दिल्ली पुलिस को निर्देश देने की ये मांग की गई है कि न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ नकदी बरामदगी को लेकर प्राथमिकी दर्ज की जाए और इसकी जांच की जाए। याचिका में कहा गया है कि इतनी बड़ी मात्रा में नकदी की बरामदगी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और मनी लॉन्डरिंग रोकथाम कानून के तहत दंडनीय अपराध है।

मार्च 14 को आग की सूचना पर दमकल कर्मी और पुलिस अधिकारी न्यायाधीश के आवास पर पहुंचे थे, जहां उन्हें प्लास्टिक के थैलों में रखी बड़ी मात्रा में अधजली नकदी मिली थी। नदुमपारा की याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने मौके पर वीडियो और फोटो तो लिए, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की, क्योंकि के. वीरास्वामी बनाम भारत सरकार केस के निर्णय के अनुसार, किसी न्यायाधीश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए मुख्य न्यायाधीश की अनुमति आवश्यक होती है।

वकील का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित तीन सदस्यीय जांच समिति असंवैधानिक है और यह पुलिस की भूमिका में हस्तक्षेप करती है।

मानसून सत्र के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के नेता होने के नाते उन्हें बोलने का अवसर न देने का, आरोप लगाया।

सरकार और विपक्ष के बीच यह टकराव सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को और भी बढ़ सकता है, क्योंकि यह खबर सामने आई है कि प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को मालदीव और ब्रिटेन के दौरे पर जा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि इस दौरे पर विदेश मंत्री या अन्य कोई मंत्री भेजा जा सकता था, तथा प्रधानमंत्री को संसद सत्र के दौरान विदेश नहीं जाना चाहिए।

विपक्ष ने अब तक कम से कम 20 मुद्दों पर बहस के लिए नोटिस दिए हैं, जिनमें बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण, मणिपुर की स्थिति और कई पुलों के ढहने जैसी घटनाएं शामिल हैं।

बांग्लादेश वायु सेना का एफ-7 विमान कॉलेज में क्रैश हुआ

ढाका, 21 जुलाई। बांग्लादेशी वायुसेना का एक एफ-7 प्रशिक्षण विमान सोमवार को कॉलेज परिसर में हादसे का शिकार हो गया। विमान कॉलेज की बिल्डिंग से जा टकराया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि170 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों में 16 छात्र, 2 शिक्षक और 1 पायलट शामिल हैं। एक अन्य मृतक से जुड़ी जानकारियां अभी नहीं मिली हैं। हादसे के वक्त माइलस्टोन कॉलेज में बच्चे मौजूद थे। प्लेन क्रैश होने के बाद स्कूल-कॉलेज में अफरातफरी मच गई। मौके पर अग्निशमन और बचाव दलों ने पहुंचकर बचाव कार्य शुरू कर दिया है।

हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी घटना की पुष्टि की है। अधिकारियों ने बताया कि प्रशिक्षण विमान ने दोपहर लगभग 1:06 बजे उड़ान भरी थी और उड़ान भरने के तुरंत बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के बाद विमान में आग लग गई।

'ईडी सारी हदें पार कर रहा है'

अधिवक्ताओं को समन भेजने पर सुप्रीम कोर्ट में ईडी पर सख्त टिप्पणी की

- सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बीआर गवई, जस्टिस विनोद चन्द्रन की बैंच ने कहा कि अधिवक्ता का अपने मुवक्किल से विशेषाधिकार प्राप्त संवाद होता है उस पर नोटिस कैसे जारी हो सकता है।

नयी दिल्ली, 21 जुलाई। उच्चतम न्यायालय ने एक मामले में कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं को तलब करने में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जांच के तरीके पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सोमवार को कहा कि वह ''सारी हदें पार कर रहा है।''

मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने ईडी द्वारा हाल ही में वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार और प्रताप वेणुगोपाल को तलब किए जाने पर स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई करते हुए कई सख्त टिप्पणियां कीं और इस मामले (ईडी जांच) में दिशा-निर्देश बनाने का सुझाव दिया।

पीठ ने इस बात पर भी खेद व्यक्त किया कि इतने सारे मामलों में जहाँ उच्च न्यायालय ने सुविचारित आदेश पारित किए थे, ईडी केवल अपील दायर करने के लिए ही अपील दायर कर रहा है।

पीठ ने कहा, एक अधिवक्ता और मुवक्किलों के बीच संवाद विशेषाधिकार प्राप्त संवाद होता है। उनके खिलाफ नोटिस कैसे जारी किए जा सकते हैं? वे सारी हदें पार कर रहे हैं...। सुनवाई के दौरान एक अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अधिवक्ता दातार जैसे कानूनी पेशेवरों को हाल ही में ईडी द्वारा जारी किए गए नोटिस का वकालत के पेशे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

बैंच ने कहा कि दिशानिर्देश बनाए जाने चाहिए। अधिवक्ता ने तर्क पर क्रिया देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि झूठे आख्यान गढ़ कर संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश की गई है।

अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमण और मेहता ने कहा कि अधिवक्ताओं को समन जारी करने के संबंध में मामला उच्चतम स्तर पर उठाया गया था और जाँच एजेंसी से कहा गया था कि वह अधिवक्ताओं को कानूनी सलाह देने के लिए नोटिस जारी न करे।

रेल्वे पेपरलीक...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ईएसएम कर्जन-बोरियावी, पश्चिम रेलवे, आणंद और रेलवे विभाग के अन्य लोगों द्वारा प्रश्नपत्र लीक करने के संबंध में मामला दर्ज किया था। दोषियों ने प्रोबेशनरी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के पद के लिए लिखित परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों से 50 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक की राशि वसूली थी। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें सजा सुनाई।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, जी-1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौन सिटी, जिला करौली से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2008/27147 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908